The question was put and the motion was adopted.

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, I introduce the Bill.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री उपसभापति: श्री श्रीगोपाल व्यास। आप कान्टीन्यू कीजिए।

There will be no lunch break today.

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, क्या कृपा कर मुझे बताएंगे कि कितना समय, आप मुझे दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): दस मिनट।

श्री उपसभापति: आपको समय वह देंगी।

श्री श्रीगोपाल व्यास: उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कल भी आपने मुझे कुछ समय दिया था, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं रामेश्वरम से आने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता, यदि उसमें निम्नलिखित बातें जोड़ी जातीं—

(1) That my Government, honouring the findings, at the instance of the Court, by the Archaeological Department that a temple exists right under the *garbh-grah* in Ayodhya, returns the land acquired in 1992 to the *Ram Janam Bhoomi Nyas* for construction of a grand temple after consulting all the concerned parties and the political parties together.

(2) That my Government, in accordance with the wishes of Mahatma Gandhi the Constitution and the Supreme Court's recent ruling in case of Gujarat, preachings of all religions, will not allow slaughter of cow and its progeny any more.

(3) That my Government will not take support of any group which feels honoured by visit of a foreign dignitary, whose country has occupied our territory and whose Ambassador declares that Arunachal Pradesh is a part of their country.

(4) That my Government will liberate the Pak-occupied Kashmir to respect the feelings of the Parliament which had resolved that it was the only matter left to be settled in respect of Kashmir.

(5) That my Government will constitute a Commission to enquire into the misuse by the Governments concerned of temple money all over the country, especially, its use for causes other than temples and the *Sewa* projects run by the temples.

(6) That my Government regrets that we could not educate our Muslim brothers and sisters, and we will treat them not as vote bank but will help them to be a part of the mainstream of the country.

(7) That my Government will explain the foreign missionaries that our country because of its great spiritual traditions and present awakening does not need them, and we have no objection to their returning to their countries to serve their own people.

(8) That my Government will preserve the age-old ties with Nepal based on Hinduism, the way of life of the entire land from the Himalayas to the Rameshwaram.

(9) That my Government will return back will Bangaldeshi infiltrators to their country.

(10) That my Government will preserve and devise means to reutilise the ancient *Rama Setu* between Bharat and Sri Lanka, which was being used as a walkway till 1480.

(11) That my Government will tell all countries to stop dishonouring the sacred symbols of worship and customs of all Indians.

With these observations, I thank you very much for giving me the time.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 23 फरवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो सम्बोधित किया गया था, उस पर अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और माननीय डा॰ कर्ण सिंह द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ की गई थी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय, का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने भाषण का प्रारम्भ सदस्यों को हिन्दी के शब्द नमस्कार से सम्बोधित करके किया। उन्होंने हिन्दी में एक कविता पढ़ी, जिसमें सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण की शुरूआत राष्ट्रभाषा हिन्दी में करके, हिन्दी का

बड़ा सम्मान किया है, उसका गौरव बढ़ाया है। उन्होंने देशवासियों को और माननीय सांसदों को एक संदेश दिया है कि वे भी अपने विचार हिन्दी में प्रकट करें। इससे राजभाषा हिन्दी का सम्मान और गौरव बढ़ेगा और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। महोदय, विश्व में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली दो-तीन भाषाओं में से हिन्दी एक है। हिन्दी इस देश की राजभाषा है। यह आज से नहीं है, अपितु 14 सितम्बर, 1949 को ही भारतीय संविधान ने इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारत की आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं सालगिरह के साथ-साथ आजादी की 60वीं वर्षगांठ की भी याद दिलाई है। उन्होंने बापू के अमोघ अस्त्र सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की ओर भी सदस्यों का ध्यान दिलाया है। महोदय, यह देशवासियों के लिए और माननीय सांसदों के लिए एक संकेत है कि आजादी के लिए देशवासियों ने जो त्याग किया, बलिदान दिया, कुबानियां दीं, हम उन्हें स्मरण रखें और आत्ममंथन करें कि आजादी के 60 वर्ष बाद भी, हम 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमने अपने देश के लिए कितना काम किया है, कितना और करना है? महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का स्मरण कराया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारा देश विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। हमारे कामगारों, हमारे व्यवसायियों, उद्यमियों में आत्मविश्वास की भावना और गतिशीलता हमें आशान्वित करती है। उन्होंने कहा है कि देश की चहुंमुखी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवीन ऊर्जा का संचार करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था में जो खाई बढ़ गई है, हमें उसको पाटना है। उन्होंने माननीय सांसदों का ध्यान दिलाया है कि अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार दिल्ली की हो या फिर पटना की, कहीं की भी सरकार हो, देश की जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है, उसे पूरा करना है। देश की जनता के सामने बुनियादी समस्याएं हैं, रोटी की समस्या है, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या है। ये सभी समस्याएं मौलिक समस्याएं हैं और इनकी जरूरत देश के सभी नागरिकों को है। हमारा जीवन इनके बिना नहीं चल सकता है। क्या हम विश्वास से यह कह सकते हैं कि आजादी की 60वीं वर्षगांठ मनाते हुए अपने देश के नागरिकों की जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, क्या हमने उन्हें वे सुविधाएं प्रदान की हैं? महोदय, आज पूरे देश को आत्म-मंथन की आवश्यकता है। सत्तर प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं। आज कृषि की क्या स्थिति है? समाचार-पत्रों में खबरें आती हैं, इस सदन में भी चर्चा होती है भारत के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, ''जय जवान, जय किसान''। जब भी गांवों की चर्चा करते हैं, गांवों के संबंध में बात करते हैं, हम कहते हैं कि देश का किसान, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मगर आज इस रीढ़ को क्या हो गया है? आज बड़ी संख्या में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। शहरों में आबादी बढ़ रही है। क्यों पलायन हो रहा है? खेती अब लाभकर

नहीं रह गई है। अस्सी प्रतिशत किसान सीमांत किसान हैं या छोटे किसान हैं। उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है। वे खेती करना भी चाहते हैं तो जो खेती के लिए बुनियादी साधन हैं-खाद, बीज, पानी या आवश्यकता पड़े तो कर्ज, वह भी उन्हें मुहैया नहीं कराया जाता है।

महोदय, सरकारी बैंक किसानों को ऋण नहीं देते हैं। अगर किसी व्यवसायी के लिए करोड़ों रुपए ऋण देना पड़े तो कोई कठिनाई नहीं होगी। मगर किसान यदि पांच हजार, दस हजार का ऋण लेना चाहता है तो उसे ऋण नहीं दिया जाता है। वह मजबूर होकर बड़े-बड़े सूदखोरों के पास जाता है। बड़ी सूद पर पैसा लेता है, और किसी कारण से उसकी खेती मारी जाती है तो मजबूर होकर वह आत्महत्या करता है। वह सूद, मूल वापस नहीं कर पाता है। जो आत्मग्लानि होती है, वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। खेती की क्या स्थिति है? 1951 में 61 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान था। आज क्या स्थिति है? जहां तक मेरी जानकारी है यह बाइस प्रतिशत पर आ गया है।

श्री अरुण जेटली (गुजरात): अठारह प्रतिशत।

प्रो॰ राम देव भंडारी: जेटली साहब ने सुधार किया कि अठारह पर आ गया है। चालीस प्रतिशत लोग खेती छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। वे खेती नहीं करना चाहते हैं। वे गांवों से भाग रहे हैं। बड़े-बड़े किसान, जिसके पास पचास एकड़, सौ एकड़ जमीन है, अगर उसे एक चपरासी की नौकरी मिल जाती है, तो वह खेती छोड़कर नौकरी करने चला जाता है। यह स्थिति है। हमारे पास आंकड़े आए कि विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में आठ प्रतिशत की दर से औसत वृद्धि हुई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नौ प्रतिशत का लक्ष्य है। इसका लाभ कहां जा रहा है? महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आय में जो वृद्धि हो रही है, इसका लाभ कहां जा रहा है? क्या इसका लाभ गांवों में जा रहा है? क्या इसका लाभ किसानों को पहुंच रहा है? मैं नहीं मानता। चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

महोदय, बेरोजगारी की समस्या है। आज बी॰ए॰, एम॰ए॰, इंजीनियर्स, डॉक्टर तो छोटी-छोटी नौकरी के लिए शहरों में, गलियों में घूमते फिर रहे हैं, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। लाखों लोग हर साल स्नातक की डिग्री लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेते है, दसवीं, ग्यारहवीं पास करके नौकरी करना चाहते हैं, मगर उसे नौकरी नहीं मिलती है। कहां जाएंगे ये? यह इतना बड़ा समूह जो ऊँची शिक्षा प्राप्त करके समाज को कुछ देना चाहता है। आज उसके पास काम नहीं है, जिसके माध्यम से समाज को कुछ दे सके। खेती से लोग भाग रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबों को जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, वे मुहैया नहीं हो पा रही हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि बजट में वित्त मंत्री ने कई बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जब बजट पर चर्चा होगी, तब हमारे माननीय सांसद बोलेंगे। महोदय, कुछ बातें, सरकार ने की

हैं और जिसका लाभ मिल रहा है। उनमें एक यह है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का विधेयक पास किया जाना है आज 200 जिलों में यह योजना चल रही है। मैं रात में टीवी देख रहा था। झारखंड के गढ़वा जिला का कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। एक गांव के बारे में चर्चा हो रही थी कि उस गांव में पानी का साधन नहीं था, उपज नहीं होती थी। इस रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से बांध बनाया गया, पानी को जमा किया गया। आज उस गांव के खेत फसल से लहलहा रहे हैं। वहां चेक डैम बनाया गया है और उस गांव के खेत फसल से लहलहा रहे हैं। इस योजना का गांवों में लाभ हो रहा है। मगर सभी राज्य इसको पूरी तरह से implement नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिहार सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता। मेरा वैसा स्वभाव नहीं है। मगर बिहार में इस योजना को अभी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है आज क्या स्थिति है, मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ दिनों पूर्व की स्थिति बता रहा हूं, इस योजना का 22 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ है। इस बार 330 जिलों में यह कार्यक्रम लागू होने जा रहा है। सरकार की घोषणा है कि हर वर्ष उसको बढ़ाया जाएगा और 5 वर्ष मे समूचे राष्ट्र को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

महोदय, बहुत चर्चा हुई है, महंगाई की बहुत चर्चा हुई है, अगर मैं इस पर दो शब्द नहीं बोलूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। महंगाई जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बढ़ी, बहुत परेशान किया, खास कर आम लोगों को। बड़े लोगों पर इसका असर नहीं पड़ता। महंगाई की मार भी छोटे लोगों को, जो आम आदमी है, उसी को झेलनी पड़ती है। सब कुछ महंगा हुआ। कहा गया कि वायदा कारोबार की वजह से जो खाद्य सामग्री है या जो दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आम आदमी उपयोग करते हैं, वे महंगे हो गए। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि चावल, गेहूं पर से वायदा कारोबार हटाया है। मगर सिर्फ उससे नहीं होगा। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग कॉमन आदमी, आम आदमी करता है, सहज रूप से उसके पास आनी चाहिए। जन वितरण प्रणाली को फिर से सुधार करके, उसमें जो कुछ अच्छा बन सके, वह किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में भ्रष्टाचार हैं, फिर भी उस माध्यम से गरीबों को अनाज मुहैया कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी हम महंगाई पर काबू कर सकते हैं, कीमतों की वृद्धि पर काबू कर सकते हैं।

महोदय, गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। महोदय, जब तक देश का गांव खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था है, मगर ग्राम पंचायत का जो उपयोग होना चाहिए, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो स्वशासन की बात होती है, वह हम नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, जब तक जनता को भागीदार नहीं बनाएंगे, शासन में और विकास में, तब तक सच्चे रूप में हम विकास का कार्यक्रम लागू नहीं कर सकते। यहां से एक रुपया चलता है, तो 12 पैसा पहुंचता है। जहां

तक एक रुपए को जाना है, वहां तक जाते-जाते 12 पैसा पहुंचता है। एक रुपया जब बारह पैसे बनकर पहुंचता है तो विकास का कितना काम होगा? इसीलिए जो पैसा जिस काम के लिए भेज रहे हैं, वह पूरा पहुंचे, इस की व्यवस्था होनी चाहिए। उस के लिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए।

महोदय, पिछले सत्र में हम ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के संबंध में एक बिल पास किया है। बाल विकास से संबंधित आज भी प्रश्न काल में कई सवाल किए गए थे। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार 50 लाख से अधिक बच्चे-बच्चियां घरेलू काम में लगे हुए हैं जिनका शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण होता है। लाखों बच्चे सड़कों पर सोते हैं। वे दिनभर जहां-तहां काम करते हैं और रात में सड़कों पर सोते हैं। हमारे देश में बच्चों की यह स्थिति है। उसका क्या कारण है? महोदय, इस के पीछे भी आर्थिक कारण है। गरीबी, आर्थिक विपन्नता की वजह से कम उम्र में ही उन के माता-पिता पैसा कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। बिहार से बड़ी संख्या में कालीन बुनने के लिए बच्चे लाए जाते थे। आज भी भदोही और उत्तर प्रदेश की कई जगहों में बच्चों को कालीन बुनने के लिए लाया जाता है। उन्हें कभी-कभी ग्रुप में पकड़कर वापस भी कर दिया जाता है, मगर गरीबी की मजबूरी की वजह से उनके माता-पिता उन्हें खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं। वे घरों में काम करते हैं जहां उनका सभी प्रकार से शोषण होता है।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं dropouts के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम जानते हैं कि स्कूलों में पहली कक्षा में कितने बच्चों का एडमिशन होता है और पांचवी-छठवीं कक्षा तक कितने पहुंचते हैं। हमारे देश में बड़े पैमाने पर dropouts होते हैं। महोदय, बजट में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है, स्कूल टीचर्स के appointments की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ पैसे दिए गए हैं। देश में शिक्षा का एक अच्छा कार्यक्रम सर्व-शिक्षा अभियान चल रहा है। मगर इस में राज्य सरकारों को सहयोग करना पड़ेगा। जो केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, वह राज्य सरकारों के माध्यम से implement होता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए, उन के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। अगर उसे सही रूप में implement किया जाए, तो मैं समझता हूं कि सर्व-शिक्षा अभियान के इस कार्यक्रम से, शत-प्रतिशत की बात तो मैं नहीं जानता, मगर इस से शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ा सुधार होगा।

[उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी) पीठासीन हुए]

महोदय, मैंने प्रारंभ में किसानों की बात की थी। आजकल Special Economic Zone की बात बहुत सुनायी दे रही है। महोदय, इस कार्यक्रम के तहत किसानों की जमीनें ली जाती हैं। जो भूमि अधिग्रहण का कानून है, इस के बारे में येचुरी साहब भी बोल रहे थे, यह बहुत

पुराना कानून है। इसके तहत किसानों की जमीन ले लेते हैं। उनका जीवन उसी जमीन पर निर्भर करता है। हमें उद्योग-धंधों की भी जरूरत है और उस के लिए भी जमीन की आवश्यकता है। मगर हम उन किसानों की जमीनें लेते समय उन के बारे में पूरी तरह विचार नहीं करते। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। अगर हम उनकी जमीन ले लेते हैं, तो हमें उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले सोच लेनी चाहिए। उनको मार्केट रेट नहीं देते। औने-पौने दाम पर हम उनकी जमीन ले लेते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ता है। उनको जो मुआवजा मिलता है, वह मुआवजा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने में चला जाता है। उनको नौकरी नहीं देते। रोजी-रोजी का जो भी साधन उनके पास होता है, वह साधन हम उनसे छीन लेते हैं। उनके लिए हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करते।

महोदय, इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। हम किसानों की जमीन लें, अगर आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही जमीन लें जितने की आवश्यकता है। कल येचुरी साहब बोल रहे थे कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी जमीन ले लेते हैं, उसका 25 प्रतिशत निर्माण काम में लगाते हैं। क्या जरूरत है उतनी जमीन की? हमारे पास सरप्लस जमीन नहीं है, महोदय। हमारे पास जो जमीन है, वह कभी बाढ़ में तो कभी सुखाड़ में चली जाती है। महोदय, मैं उत्तर बिहार से आता हूं। हमारे और भी साथी उत्तर बिहार से हैं। उत्तर बिहार के 38 में से लगभग 20 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। नेपाल से नदियां आती हैं। नेपाल के साथ वर्षों से बात हो रही है, मगर अभी तक उसका जो कोई रास्ता निकलना चाहिए, जो समाधान निकलना चाहिए वह नहीं निकला है, वह दूसरा देश है, वह अपनी सुविधा देखेगा। इस प्रकार बाढ़ में जमीनें चली जाती हैं, सुखाड़ होता है। हर तरफ से किसान मारे जाते हैं। फिर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करके, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था या उनके लिए अन्य व्यवस्था नहीं करके, उनकी जमीन ले लेते हैं। महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। कई माननीय सांसदों से सच्चर कमेटी कर रिपोर्ट पर चर्चा की है और उसे लागू करने की भी मांग की है। महोदय, 13 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है। उनकी आर्थिक स्थिति भी दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के लोगों से अच्छी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी। एक अच्छी रिपोर्ट आई है। अल्पसंख्यकों के लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे। मैं सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कहता, दूसरे लोग हैं, ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Your time is over. Please conclude.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, मैं राष्ट्रीय न्यायिक परिषद के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस समय कोर्ट की यह स्थिति है कि 25 हजार से अधिक मुकदमें सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हैं। जेटली साहब बैठे हुए थे, अभी नहीं हैं। करीब 35 लाख हाई कोर्ट में हैं और ढाई करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में पैंडिंग हैं। 10 साल से, 20 साल से मुकदमें पैंडिंग हैं। इन मुकदमों का निपटारा नहीं हो रहा है।

महोदय, जजों की संख्या बढ़ाई जाए और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन हो। महोदय, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। ज्युडिशियरी में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। एकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अभिभाषण में भी इसकी चर्चा हुई है। एक विधेयक भी सदन के सभा-पटल पर रखा गया है। मैं येचुरीसाहब की इस बात से सहमत हूं कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ज्युडिशियरी है, इनमें जो इमिनेंट लोग हैं, कानून के ज्ञाता हैं, बार के लोग हैं, जो परिषद बने, उनको भी शामिल करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude. Your Party's time is over.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे एक-दो मिनट का समय दिया जाए।

महोदय, ग्रामीण न्यायालय विधेयक लाने की बात हो रही है। लाखों ऐसे छोटे-छोटे मुकदमें हैं, जिनको अगर ग्रामीण न्यायालय विधेयक बना कर गांव में ही इनका समाधान किया जाए तो मुकदमों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। एक-दूसरे से मेलजोल, तालमेल भी बढ़ेगा। यह ग्रामीण न्यायालय विधेयक बनने के बाद उसके माध्यम से जो कानून बनेगा, उसके द्वारा इसका समाधान किया जा सकेगा।

महोदय, उच्च शिक्षा में आरक्षण के बारे में विधेयक पास किया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे शीघ्र लागू किया जाए। दांव-पेंच से उसे फंसाने की बात हो रही है। कानून पास हो जाने के बाद भी इसको रोकना चाहते हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दांव-पेंच लगाकर इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, वे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें अच्छी टेक्नीकल एजुकेशन मिले, देश में जो अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, इंस्टीटयुशन्स हैं, उनमें इनको शिक्षा मिले। इसके लिए यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, इसे शीघ्र लागू किया जाए।

महोदय, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। मुझे बस दो मिनट का समय और दे दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी): सात मिनट अधिक हो गए हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है—''मेरी सरकार भारतीय रेल का कायापलट करने में सफल रही है''। यह बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है —''बेहतर आपूर्ति व मांग प्रबंधन, क्षमता के युक्ति-संगत उपयोग तथा बाजार संचालित मूल्य-निर्धारण नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय रेल एक बार फिर से दौड़ पड़ी है''। भारतीय रेल पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि राकेश मोहन कमेटी ने कहा था कि वर्ष 2015 तक 61 हजार करोड़ रुपए का भार रेलवे पर पड़ेगा। महोदय, लालू प्रसाद जी कोई बहुत बड़े हिसाब-किताब करने वाले नहीं हैं। वह तो गांव में पैदा हुए किसान का बेटा है, देश के गरीब दबे-कुचले लोगों का बहुत प्रिय नेता है। उन्होंने रेलवे के माध्यम से कोई बोझ आम जनता पर नहीं डाला। लालू प्रसाद जी इतिहास में रेलवे का एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रहे हैं। रेलवे में 20 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा होने जा रहा है, जो एक करिश्मा है। यह वही रेल है, जो वर्ष 2001 में डिविडेंड का भुगतान करने से चूक गई थी, जिसका फंड बेलेन्स गिरकर 359 करोड़ रुपए रह गया था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Prof. Bhandary, you please conclude. Your party's time is already over.

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, आज पूरा देश रेल बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है। माननीय जनेश्वर मिश्र जी नहीं हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हमारे नेता रहे हैं। उन्होंने गाय के दूध की एक-एक बूंद दूहने की बात कही थी। गाय का एक-एक बूंद दूह लेंगे, तो बछड़ा क्या पियेगा? लालू प्रसाद जी का जन्म गांव में हुआ है और वह जन्म के बाद ही गाय और बछड़ों में खेले होंगे। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि गाय का कितना दूध निकालना चाहिए, कितना बछड़े के लिए छोड़ना चाहिए। एक इन्क्वायरी की बात कर रहे थे। इन्क्वायरी होनी चाहिए। हम इन्क्वायरी से नहीं घबराते। आजकल सीबीआई की बहुत बात हो रही है, जब लालू प्रसाद जी को बार-बार सीबीआई जेल में भेज रही थी, तो हमारे मित्र सीबीआई की पीठ ठोक रहे थे। कहते थे कि सीबीआई एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार एजेंसी है। आज वही सीबीआई उनकी नजर में निष्पक्ष नहीं रह गई है, ईमानदार नहीं रह गई है, बेईमान हो गई है। इस तरह दो तरह का चेहरा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सीबीआई सरकार के कब्जे में है, मगर एनडीए की गवर्नमेंट में क्या हुआ था? एक कद्दावर नेता को बचाने के लिए किस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था, देश जानता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी): आप खत्म कीजिए।

प्रो॰ राम देव भंडारी: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरी बात खत्म हो गई है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो कुछ कहा है, उसको कहने से पहले मैं एक और विषय की ओर सरकार

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, नेपाल में करीब-करीब आधी जनसंख्या 'मधेशी' नागरिकों की है। हजारों नागरिक ऐसे हैं जिनको अभी तक नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा लगने लगता है कि उनको नेपाल से बाहर कर दिया जाएगा। मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि सरकार इसमें पहल करे, नेपाल सरकार से बात करे और नेपाल में 'मधेशियों' की जो समस्या है, उसको दूर करे।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं तीन-चार पंक्तियां, जो राष्ट्रपति जी की ओर से अभिभाषण में दी गई हैं, उन्हें पढना चाहूंगा--'सतत् जागरूकता के जरिए ही लोकतंत्र बहाल रखा जा सकता है। हमारे देश के लोगों को बेहतर प्रशासन मिले। मुझे आशा है कि आपको जो अधिकार मिले हैं, आप उनका इस्तेमाल हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के हित में करेंगे।'

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Dr. M.S. Gill. You have four speakers. The total time left is one hour and twenty-eight minutes.

डा॰ एम॰ एस॰ गिल (पंजाब): मुझे कहा गया है कि 15 मिनट बोलें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Anyway, I have just reminded you.

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: उपसभाध्यक्ष जी, मैं इंतजार करता रहता हूं ऐसे माहौल का—शांति है, सब अमन से बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, मेरे को भी सुन लेंगे। अगर ऐसा माहौल ज्यादातर रहे तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, जो उन्होंने पढ़ा था, जो सरकार का प्रोग्राम दिया था, डा॰ कर्ण सिंह जी का जो रेज़ोल्युशन है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने इसको बड़े ध्यान से दो-तीन दफा पढ़ा है। सब देख रहे हैं, यह ठीक बात है, खुशी की बात है कि 8 परसेंट भी ग्रोथ हो गई, 9 भी हो गई, 9 से थोड़ी ऊपर भी इस साल जा रही है और 10 का निशाना भी शायद लग जाए। यह एक बड़े गौरव की बात है इस देश के लिए। 3 परसेंट या 3.5 परसेंट में हमारी जिंदगी निकल गई थी, लेकिन अब यह हो रहा है। इसके साथ-साथ एक और बड़ी अच्छी चीज है कि जो सेविंग्स रेट देश का है और जो इन्वेस्टमेंट है, वह बहुत बढ़ा हैं 20 साल या 30 साल पहले हम देखते रहे हैं कि 20, 21, 25 परसेंट तक सेविंग्स के लिए कोशिश हुआ करती थी, स्मॉल सेविंग्स वगैरह की, लेकिन अब 34 परसेंट ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यह देश की सेविंग्स से हो रहा है और यह बहुत ही बधाई की बात है।

इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं तो कल एक घंटा मेरे को बड़ा मज़ा आया, जब सीरियसली, सवाल तो एक ही था, लेकिन उस पर एक घंटा लगा और अच्छा हुआ, क्योंकि प्राइसिस देश की जान और जिंदगी से बंधी हुई हैं और उसके ऊपर सबने चर्चा की और बड़ी गंभीरता से जवाब हुए। फाइनेंस मिनिस्टर को भी बड़े जोर से कोशिश करनी पड़ी हाऊस को कन्विन्स करने की। इन्फ्लेशन जरूरी है, इन्फ्लेशन को रोकना जरूरी है और कल वे इस बारे में बात कर चुके हैं, मैं तो यही आशा करता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काबू पाया जाएगा। क्योंकि, हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगी, तो डेमोक्रेसी तो आलू के भाव से, प्याज़ के भाव से और गंदम के भाव से ही चलेगी और अगर उसमें कोई आपत्ति आएगी तो कोई भी हो, इधर का हो या उधर का हो, उसको दिक्कत आएगी। दाल की बात हुई थी, हम पंजाब में कहते हैं- दाल, जो निभे सदा नाल। दाल के बगैर हिन्दुस्तान नहीं जी सकता है। दाल हिन्दुस्तान की प्रोटीन है, उसके बगैर तो इंसान फिज़िकली ही नहीं जी सकता है। इसलिए कल जो दाल की चिंता थी, जो हुई, उसके लिए मैं एक ही आशा रखता हूं कि जो भी करना पड़े, किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में लोगों को दाल न मिले या महंगी मिले। बजट भी चूंकि आ चुका है, मैंने उसको भी साथ-साथ पढ़ा है, उसमें पैरा 49 में लिखा है कि mission for pulses, maize, oil, palm, *dal*, इन सबके लिए एक मिशन बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी देर इंतजार शायद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब ड्राई लैंड फार्मिंग दाल की कोई नहीं करता, पंजाब में बहुत होती थी, सब किसानों ने छोड़ दी। तो अगर उसको लाना है तो किसानों को दाल की प्राइसिस देनी होगी, उसके बीज देने होंगे, उसके लिए और साधन उपलब्ध कराने होंगे और जल्दी उपलब्ध कराने होंगे, मैं तो इतना ही जानता हूं कि इस पर ही मैं इसको छोड़ देता हूं।

मैंने भारत निर्माण के प्रोग्राम को भी देखा, उसमें दो-तीन चीज़ें हैं। सरकार का एवं प्राइम मिनिस्टर का यह फोकस रहा है कि इन चीजों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों के लिए कुछ न कुछ कर सकें। उस प्रोग्राम में जो तीन चीज़ें रखी गई हैं, उनमें से पहला है स्वास्थ्य। इसके लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को रखा गया है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन, ''सर्वशिक्षा अभियान'' है। मैं एक बात हिन्दी वालों से अवश्य कहना चाहूंगा, चाहे यहां के हों अथवा वहां के, आप नाम तो रखें, लेकिन सीधी-सादी हिन्दी में रखें, ताकि मेरे जैसे आदमी के लिए उसे समझना आसान हो सके। दूसरा प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम है। तीसरा, रूरल इम्प्लॉइमेंट का प्रोग्राम है।

मैं इन तीनों के संबंध में कुछ न कुछ जिक्र करना चाहता हूं। मैं तो इतना जानता हूं कि चाहे कोई भी, कहीं की भी सरकार हो, उसके शायद तीन ही फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है —'लॉ एंड ऑर्डर'। हमारी बहन, बहू, बेटियां यदि रात के दो बजे भी कहीं जाती हैं, तो कोई उनकी तरफ उंगली भी न कर सके, उठाना तो दूर की बात रहे। सरकार का दूसरा फंक्शन होता

है, सेहत। हिन्दुस्तान की सारी जनता की सेहत अच्छी रहे, अगर वह बीमार हो, तो उसे उचित इलाज मिले। एक बात इस संबंध में मैं बार-बार कहता रहता हूं कि हिन्दुस्तान में हेल्थ और एजुकेशन कमर्शियल होते जा रहे हैं। एक श्रेणी के लोगों को तो फाइव स्टार होटल मिलता है, मैं भी कभी सरकारी खर्चे पर उसमें गया हूं। वहां पर मुझे तीन कमरे भी मिल जाते हैं और ड्राइंग रूम भी मिल जाता है, लोग आते हैं तो हम उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। ऐसे में बेअंत खर्चा होता है, मेरे संबंध में तो वह खर्च सरकार दे रही थी। आज भी कुछ लोग तो इस प्रकार का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान के लिए रीज़नेबल कॉस्ट पर सेहत का बंदोबस्त हो, इसे हम अवश्य देखें। आम आदमी की जो इन्कम है, आम जनता की जो इन्कम है, जिनका हम ज़िक्र भी करते रहते हैं, उसे उस इन्कम में इस प्रकार की सुविधा मिले। मुझे खुशी है कि बजट में भी इसके लिए शायद 20 या 22 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है और इस पर अतिरिक्त रुपया आबंटित किया गया है। इसे और भी बढ़ाया जाए, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि वास्तविकता यह है कि पिछले दस-बीस वर्षों में सोशल सैक्टर पर खर्चे बहुत ही कम रहे हैं। इसलिए इसे और बढ़ाया जाए। मैं इतना जानता हूं कि सरकारी अस्पतालों के माध्यम से अथवा अन्य किसी भी प्रकार से गांवों अथवा छोटे कस्बों में कोई भी व्यक्ति बीमार हो, उसे मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, जैसा अंग्रेज करते हैं। इसका क्या कोई प्रबंध है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस कार्यक्रम को और भी आगे ले जाए और आम लोगों को यह तसल्ली दे कि आपके लिए भी डॉक्टर, कमरा और बिस्तर जरूर मिलेंगे।

दूसरा नम्बर एजुकेशन का आता है। मुझे खुशी है कि बजट एलोकेशन में इसके लिए 34-35 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज़ादी के बाद से आज तक हम सारे हिन्दुस्तान की लिट्रेसी को 90 प्रतिशत तक क्यों नहीं ले जा सके। केरल में अथवा मिज़ोरम में ऐसा क्या जादू है? पंजाब, हरियाणा, यूपी या बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो सका? आज भी पंजाब 65 प्रतिशत लिट्रेसी के ऊपर ही अटका हुआ है, यह हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। हम तो इसे 100 की जगह 150 प्रतिशत कर सकते थे, हमारे पास इसके लिए साधन भी थे, ग्रीन रेवोल्यूशन भी था, लेकिन आज तो हमें यह कार्य करना ही है।

मैं दो-तीन बार अपने किसी कार्य से ईरान गया। उनके बारे में फंडामेंटलिज्म इत्यादि की बातें तो की जाती हैं, लेकिन उनके बारे में मैंने एक अच्छी बात देखी कि जब वहां खुमैनी इत्यादि लोग आए तो वहां पर केवल 25 प्रतिशत लिट्रेसी थी और 15-20 साल के थोड़े से समय में ही वह 75 प्रतिशत हो गई। मुझे मालूम नहीं कि आज वहां पर कितनी साक्षरता है, लेकिन अगर वास्तविकता में हमारे भारत में 70-80 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कई बार झूठे आंकड़े भी दे दिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में अगर इतने लोग पढ़े-लिखे हों तो हमारी पॉलिटिक्स का नक्शा कुछ और ही होगा। वे जो कुछ भी करेंगे, सोच-समझ कर,

पढ़ कर ही करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अत: लिट्रेसी के संबंध में सरकार का जो प्रोग्राम है, उसके ऊपर मैं खुशी प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि उसे और भी आगे ले जाएं और इफैक्टिव बनाएं।

एक बात में अवश्य कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बहुत अधिक हैं और जरूरत से ज्यादा खुलती जा रही हैं, लेकिन स्कूल एजुकेशन नहीं है। स्कूल एजुकेशन के बगैर तो यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाना चाहिए, वहां पर आप क्या पढ़ाएंगे? स्कूल एजुकेशन, रूरल एजुकेशन और टोटल एजुकेशन, इनके संबंध में क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, इस सवाल को देखने की जरूरत है।

जो नेशनल रूरल इम्प्लॉइमेंट गारंटी स्कीम है, वह बहुत अच्छी है, अब उसमें 330 जिले कर दिए जाएंगे, यह बहुत अच्छी बात है। इस संबंध में मुझे केवल एक चीज़ की चिंता है, मैं मध्य प्रदेश जाता रहता हूं, वहां पर ट्राइबल्स हैं, पंजाब में तो शायद यह प्रोग्राम नहीं भी चलता होगा, लेकिन मैं देखता हूं और लोगों से बात भी करता हूं, मध्य प्रदेश में यह चलता है। और वह यह है कि इसमें जो लिखा है कि 5 लाख वर्क्स यह होंगे, वाटर वर्क्स होंगे, वाटर कंजर्वेशन के होंगे, कोई और डवलपमेंट वर्क्स होंगे, यह जो स्कीम हैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो गांव के जिन लोगों को कहना है कि आओ, तुम्हारी बीस की हाजरी लगाएंगे और आज का तुमको सौ-सौ रुपया मिलेगा क्योंकि तुमको काम नहीं है। तो सरपंच भी यह जो भी चौधरी मेरे जैसा होगा वह कहेगा कि सौ में से बीस तो मेरे हैं। यह आप कैसे रोकेंगे आप सोचते रहो। लेकिन इसके बगैर वेस्टेज होगी, लीकेज होगी, दूसरा यह है कि जो वर्क्स हैं वे रिअली डवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए वरना पैसे का फायदा नहीं होगा। किसी को दे भी दिया तो वह कंजूमर में चला जाएगा। अब यह सोचने की बात है कि कैसे करेंगे, कहां करेंगे। एक और बात बड़े जोर से कही गई है, बजट में भी आई है कि टेक्नीकल एजुकेशन, आई॰टी॰आई॰ या जो भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका किया जाए। इसके साथ स्कॉलरशिप का भी आया कि ओ॰बी॰सी॰ के लिए, एस॰सी॰, एस॰टी॰ के लिए, मॉयनोरिटी के लिए। मैं तो यह कहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप स्कॉलरशिप डटकर बढ़ा दो, पैसे हैं, सरकार ने इतने पैसे कमाए हैं कि इसका रोज जिक्र आ रहा है कि इस साल में कितनी इन्कम बढ़ी है। वैसे भी आप 180 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रखे बैठे हो। तो जो भी इकोनॉमिकली बैकवॉर्ड है, ब्राह्मण है, या यह हो या वह हो, सबको स्कॉलरशिप में कहीं न कहीं ले आओ। लेकिन नीचे के लोगों को जो गरीब हैं, जिनके पास अपने साधन नहीं हैं उनको पढ़ाओ और उनको टेक्नीकल पढ़ाओ। इस प्रोग्राम में मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

मैं एक-दो एग्रीकल्चर की भी बातें करता हूं। उसका जिक्र किया है कि इंवेस्टमेंट ठीक है बढ़ाई गई है लेकिन फ्रेंकली इंवेस्टमेंट पिछले 10-20 साल से एग्रीकल्चर में, अर्जुन सेन गुप्ता

यहां बैठे हुए थे, हम बातें करते रहते हैं कि एक-डेढ़ परसेंट ही रही है, इसको करेक्ट करना है चाहे कोई सरकार रहे या कोई सरकार आए। और इसको बहुत आगे बढ़ाना है। आपको चिंता तो यह होनी चाहिए कि जी॰डी॰पी॰ का जिक्र करते रहते हैं कि 51-52 परसेंट तो आई॰टी॰ से आ गया, सर्विसिंग इण्डस्ट्री से आ गया। सर्विस इण्डस्ट्री वालों को आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेता, बड़े-बड़े महापुरुष हैं, बड़े हिन्दुस्तान के वे नए अर्जुन हैं। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि जो इस देश के जो 65 परसेंट लोग हैं उनकी इनकम तो अब 18 परसेंट पर आ गई, 25 भी नहीं रही। तो 18 परसेंट जी॰डी॰पी॰ ही उनको बांटना है, 65 परसेंट में। तो भूख ही बांटेंगे उसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो उसको सोचना होगा कि उसमें क्या होगा। एग्रीकल्चर में मैं देख रहा हूं कि यदि क्रेडिट बढ़ाया, 175 लाख करोड़ था, 190 हुआ, अचीवमेंट बढ़ गई और सवा दो लाख करोड़ अगले साल के लिए रखी है, यह बजट से मैं ले रहा हूं। लेकिन मुझे एक चिंता है क्योंकि सारी उम्र मैंने यह काम किया है कि यह आंकड़े ब्रेकअप करके देखने हैं, क्योंकि यह जो स्टेटिस्टिक्स वाले होते हैं इनका बड़ा अजीब गिनती का तरीका है। आप किसी प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री को दे देते हो, शायद यह भी एग्रीकल्चर क्रेडिट ही गिना जाएगा, दिया तो किसी फैक्ट्री को। मैं तो देखना चाहता हूं कि जो डॉयरेक्ट क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर ऑफ इंडिया बिलो 10 एकड़ हैं उनको क्रॉप लोन के लिए मिडियम टर्म्स इंवेस्टमेंट के लिए एक डीजल इंजन के लिए, वह कितना दिया? यह कोई नहीं बतलाता है, मैं यह जानता हूं। और वह बढ़ा है या नहीं। अच्छा, कोआपरेटिव को रिवाइव करने के लिए तेरह हजार करोड़ है, कोआपरेटिव के बगैर गति नहीं है। क्योंकि किसानों की आइटम तो वही बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, नेहरू ने उसको पाला था और अब वह बहुत गिर चुकी है। तो कब उसको उठाओगे, क्योंकि जो आपके सरकारी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वे क्रेडिट देना चाहते हैं एक सेठ को जो दस हजार करोड़ या इकट्ठा ही ले जाए और वह वापिस भी कर देगा, जब करेगा। लेकिन दस-दस हजार या पांच-पांच हजार कर्जे वाले दो लाख किसानों को वे डील नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सिरदर्दी है। यह कोआपरेटिव ही करते थे। तो यह बहुत लम्बा सब्जेक्ट है, मेरे पास टाइम नहीं है नहीं तो मैं और भी कुछ कहता। लेकिन यह आपको करना होगा। मुझे तो यह जानना है कि क्या क्रेडिट डॉयरेक्ट फार्मर्स को बढ़ा है, क्या उसमें कोआपरेटिव रिवाइव की हैं और जब कोआपरेटिव बीमार हो जाए, उसकी ओवरड्यू हो जाए, किसान की हो जाए तो उसको तो आप दे ही नहीं सकते हैं। तो फिर आप इधर-उधर किसी एग्रो फैक्टरी को दे देंगे या भगवान जाने कहां देंगे। तो इसको आपको सोचना है। यह जो एग्रीकल्चर इनडेब्टनैस की राधाकृष्णन जी की कमेटी है, उनको मैं नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ता हूं कि आप रिपोर्ट ले आओ, यहां समय निकलता जा रहा है। फिर देखें कि आप क्या रिपोर्ट ला रहे हैं। क्योंकि हर बार राधाकृष्णन का जिक्र आता है, राधाकृष्णन तो हमारे थे यहां के और यह कोई और राधाकृष्णन होंगे। तो इसका कुछ किया जाए क्योंकि there is indebtedness of farmers. अच्छा एक बड़ी मुसीबत किसान को बनी है, जो पिछले

पांच-दस साल में बनी है। अंग्रेजों के समय में, पंजाब में यह बिल्कुल बंदिश थी कि अगर किसान ने किसी आढ़तिये से या किसी साहूकार से कर्जा लिया है और अगर वह उसने वापिस नहीं किया तो आप उसकी जमीन, उसके हल-बैल, उसका चूल्हा-चौका, उसका घर नहीं ले सकते हैं। हम जीने के साधन उसके हाथ से नहीं खो सकते हैं। अब यह हो रहा है, मैं पंजाब में रोज यह पढ़ लेता हूं कि जो दो एकड़ जमीन वाला है, उसकी जमीन खोने के लिए डीएसपी और मजिस्ट्रेट साथ आ गए। ऐसा आजादी के बाद तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने किया है, तो उसको रोको।

लैंड एक्विजिशन के बारे में भी मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। पैराग्राफ 9 में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इंडस्ट्री के लिए जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेंगे, लेकिन यह मुझे खुशी है कि इसमें कहा है कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या जरूरत है। whatever is necessary, we should that. मेरी अर्ज यह है कि नेसेसरी तो यह है कि अंग्रेजों ने 1884 या 1894 में कानून बनाया था, to acquire for public purpose. नहर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए या फौज के लिए, पांचवीं चीज़ मुझे नहीं पता है, मैंने यह एक्ट चलाया है। एक छोटे आदमी से एक-दो एकड़ को लेकर, एक बड़े आदमी को देना, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेरी अक्ल में नहीं आ रहा है। यह तो कम से कम अंग्रेज की पालिसी पर जाना चाहिए। अंग्रेजों के देशों में, मैंने चैक किया है— अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड कहीं भी लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं है। Stanford Airport की बीस-तीस साल रुकी रही, क्योंकि एक किसान रुका हुआ था कि मैं नहीं देता अपनी 10 एकड़ जमीन। मैं इसको बड़ी आशा से देखता हूं कि सरकार क्या अमेंडमेंट लायेगी और इसको कैसे tighten करेगी, क्योंकि इसके ऊपर सारे देश में चिंता है। मैं इसको आगे नहीं ले जाता हूं।

एनवायरनमेंट का जिक्र है बिल्कुल ठीक है। जो एनवायरनमैंट है, उसमें 27 परसेंट पाल्युशन यूरोप कर रहा है, 38 प्रतिशत अमेरिका, हम और चीन 12 परसेंट कर रहे हैं। लेकिन हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। गरीब इंडिया का एक प्रोग्राम एक्टिव कंसिडरेशन है। मैं तो इतना ही जानता हूं। डा॰ कर्ण सिंह ने कहा था कि पापुलेशन का तो इसमें जिक्र नहीं हुआ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर आप पापुलेशन में कंट्रोल शब्द के ऊपर एतराज करते हैं, तो कोई और शब्द एस्टेबिलाइज करने का ढूंढ़ लेते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है। उसके आगे टाइगर का पैरा है। मैंने सब टाइगर देखें हैं, शेर भी देखे हैं, मैं शिवपुरी में टाइगर के साथ पला हूं। मैं जानता हूं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आबादी होगी तो जंगल नहीं रहेंगे, जंगल नहीं होंगे, तो शेर नहीं रहेंगे और जंगल नहीं रहेंगे, तो पानी नहीं रहेगा, तो सारे सूबे एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे। यह विषय तो बहुत बड़ा है। अगर इसको बचाना है और अगर वाकई ये ग्रीन प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे खुशी होगी।

रेलवेज़ का मैं एक शब्द में जिक्र करता हूं। यह ठीक है कमाया है, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और उसको बेहतर करना जरूरी है। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक फ्रेट कॉरिडोर नया बन रहा है। मुझे तो यह समझ आती है, मेरे ख्याल से रेलवे लाइन 65 या 70 हजार किलोमीटर है और ऐसे ही तीस साल से रही है। इनको आप क्यों नहीं हंड्रेड थाउजेंड कर सकते, सारा मध्य प्रदेश खाली पड़ा है, उड़ीसा खाली पड़ा है और प्रदेश खाली पड़े हैं। आप उनमें नई-नई रेलवे लाइनें बिछाओ। Rail is the cheapest means of transport and a sensible transport. Ours is a flat country and we have a good railway network. इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें।

सिविल एविएशन के बारे में, थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। जो चार-पांच बड़े शहर हैं, इनका तो बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन जो 35 एयरपोर्ट्स हैं, उसमें आपका अमृतसर भी आयेगा। आप फिर कहेंगे कि अमृतसर की बात कर रहे हैं, तो उनका भी हमें कोई काम दिखाओ। सात-आठ साल में अमृतसर में छोटा सा आने-जाने का बना है। अब फिर साठ-सत्तर करोड़ का काम हो रहा है, साठ-सत्तर करोड़ से तो दाल-फुल्लियां भी नहीं आतीं। हम क्या करेंगे? हमें भी 500 करोड़ का कर दो और बाकी 35 को भी उठाओ। हिन्दुस्तान को थोड़ा खोलो।

मैं नेशनल जुडिशियल कमीशन के ऊपर जरूर कुछ कहना चाहता हूं। यह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय चल रहा है। यह मेरी नजर में पार्टियों से ऊपर है और आपस में जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको आपस में बैठकर कभी इस पर गंभीर चर्चा करनी है। मेरी अक्ल में फैसला यूनेनिमस करना है। मैं जब किसी और जगह था, तो मैंने सभी पार्टी वालों से बात भी कर ली थी, उस समय के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी से भी बात करी थी। प्रधानमंत्री से चर्चा की थी। मैं तो ऐसा मानता था कि the state of Indian judiciary must be debated in both the Houses for two days like the No-Confidence Motions were debated twice for Prime Ministers; शांति से, प्रेम से, विस्तार से यह हुआ था, मुझे आनन्द आया था। यह होना चाहिए, to decide what is the balance, नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन का जो बिल आ रहा है, मुझे उसके संबंध में कुछ हो रहा है और मैं कमेटी के सामने भी जाऊंगा—मैंने इस संबंध में रिक्वेस्ट की थी। एक बड़ी सिम्पल सी बात है कि हम ही अपने आपको नियुक्त करेंगे, हम ही अपने आपकी टोका-टोकी करेंगे या देखेंगे और जो हम देखेंगे, वह अपने पास ही रखेंगे, किसी और को नहीं दिखेएंगे—यह प्रिंसिपल दुनिया में कहीं नहीं चलता है। डेमोक्रेसी का आप पढ़ो, अमेरिका का पढ़ो, अंग्रेजी का पढ़ो, हिन्दुस्तान का कॉस्टीटयूशन पढ़ो। जो 20-25 साल पहले था, वह बिल्कुल ठीक था। In a democracy, the Chief Justice will recommend; the Prime Minister is somebody in this country; he and others will look at it and the President will have a role. And I think that

2.00 P.M.

is a democratic way. America does it even now. Bush has the mandate today. He proposes. Of course, the Senate checks it in their system. When Clinton was there, he proposed and they checked it. The will of the people is coming through the President. It is a social issue also, as to what is the leaning of any human being, including a Judge, and this has to be looked at in a democratic way. I would appeal to both the sides. The Leader of Opposition is sitting here क्या मज़ा है मेरे बोलने का कि सभी यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं! The Home Minister is here. Please address it because it is time India addressed it along with many other problems.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Your time is over. Please conclude.

SHRI M.S. GILL: Yes, Sir. I would just take one or two minutes. On Foreign Policy, I have two small items on which I have to say something; I don't want to hang on. पॉवर की बहुत बात हुई है, बजट में भी हुई है, इसमे भी हुई है। There is a crisis of power. Yesterday, there was a talk कि 80 हज़ार मेगावाट नेपाल में है। सबको दिखता है। दरिया उधर से ही आते हैं। बिहार और ईस्टर्न यूपी तो perpetual flood में डूबे हुए हैं because unless you have dams up there, you cannot control the water. वह हो रहा है, but I say to you, Sir, if we want to have power from Nepal, if we want to stop floods to Bihar and UP, and even Bengal, तो उनसे फॉरेन पॉलिसी का रिश्ता बहुत अच्छा, गूढ़ा करना होगा, कैसे करेंगे, यह आप लोग जानें। इंडो-चाइना के संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आज भी उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान मैंने 'हिन्दू' में पढ़ा है, उन्होंने वहां कुछ कहा है—अच्छी बात ही कही है कि हमें ये हिस्टॉरिकल चीज़ें सोचनी चाहिए। यहां भी मैं सुनता रहता हूं कि हमारे जो रीप्रेज़ेंटेटिव्स हैं, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, बेअंत मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब तो मुझे गिनती भूल ही गयी है। It is like what happened after the Korean War between America and North Korea in Panmunjom. I only want to say this to the Government and to everybody, it is time they and we settled the border issue so that I know, which is India, which is China, and then we go further from there. And I think we need to do this. And I think we need to pursue it as hard as we can.

Thank you very much. I am grateful that you have given me time.

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का तीसरा दिन है। बृहस्पतिवार को डा॰ कर्ण सिंह जी ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और राशिद

अल्वी जी ने उसका अनुमोदन किया था। कल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरूआत की गयी थी। आज मैं अपने दल की ओर से इस राष्ट्रपति अभिभाषण पर कुछ बातें कहने के लिए खड़ी हुई हूं। लेकिन मैं प्रारम्भ में ही आपको बता दूं कि मेरी कही गयी बातें महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कोई टिप्पणी नहीं है। हां, इस सरकार की कारगुज़ारियों पर,इस सरकार की कार्यशैली पर और इस सरकार की सोच पर टिप्पणी जरूर है। महोदय, यह वर्ष, 2007 का वर्ष भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं सालगिरह का और भारतीय स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ का वर्ष है। इसलिए बहुत सही तौर पर राष्ट्रपति जी ने इसी प्रसंग से अपने अभिभाषण को शुरू किया। उन्होंने पहले ही पैराग्राफ में कहा—

''एक सशक्त, आधुनिक, सर्वसमावेशी, पंथनिरपेक्ष और गतिशील भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने के ये अवसर हैं।''

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि हमारी आज़ादी को बचाए रखने के संकल्प लेने का भी यह वर्ष है। महोदय, आज़ादी को प्राप्त करना जितना कठिन होता है, उससे ज्यादा कठिन होता है उसको बचाकर रखना। एक कवि की चार पंक्तियां मुझे कभी भूलती नहीं हैं। उन्होंने लिखा है—

''आज़ादी की रक्षा करना बहुत कठिन है,

जगते हैं जो सदा वही इसको पाते हैं।

जो विलासिता की निद्रा में सो जाते हैं,

वो पीछे से सिर धुन-धुन कर पछताते हैं।''

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी आज़ादी के इतिहास को भूल रही है। अगणित अज्ञात शहीदों की कुर्बानियों से हमने आज़ादी हासिल की थी। कितनी यातनाएं झेली थीं उन्होंने, इसका आज की पीढ़ी को भान नहीं है। महोदय, जन्म तो मेरा भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ है, लेकिन वह समय स्वतंत्रता संग्राम के चंद वर्षों बाद का समय था, इसलिए उस समय संग्राम की यादें ताज़ा थीं। उस समय विभाजन की पीड़ा के बाद की यादों को ताज़ा रखने का समय था, इसलिए हम उस पूरे इतिहास को पढ़-सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन आज जो बच्चा अठारह से बीस वर्ष का भी है, उसे आज़ादी के इतिहास का ज्ञान नहीं है और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। आज से दस वर्ष पहले 1997 में हमने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। उस समय हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक स्वर्ण जयन्ती रथ यात्रा निकाली थी। मैं पंद्रह दिन उस यात्रा मे उनके साथ थी। उनके रथ पर स्वतंत्रता-संग्रामियों के चित्र लगे हुए थे। जहां कहीं भी वह रथ रुकता था, वे नवीं-दसवीं के

बच्चों से जाकर पूछते थे—बताओ इनमें से किस-किस को पहचानते हो? दुख होता है यह कहते हुए कि चार-पांच से ज्यादा चित्रों को बालक पहचान नहीं सकते थे। जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल में गए, तो सुभाष जी का चित्र पहचाना गया, हम झांसी के पास से निकले, तो लक्ष्मीबाई का चित्र पहचाना गया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता संग्रामियों के चित्रों को बच्चे पहचानते नहीं थे। मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि यह जो 150वां सालगिरह का वर्ष है, इसमें हमें इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि टी॰वी॰ धारावाहिकों के माध्यम से, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से, क्विज़ कांटेस्ट्स के माध्यम से बच्चों को इस पूरे इतिहास की जानकारी दें। मैं तो चाहूंगी कि एच॰आर॰डी॰ मिनिस्ट्री एक ऐसी योजना बनाए, जहां इस वर्ष में बच्चों को जलियांवाला बाग से लेकर अंडमान-निकोबार तक के शहीद स्थलों के दर्शन कराए जाएं, ताकि उन्हें पता चले कि हमने किस कीमत पर यह आज़ादी हासिल की है और उसके साथ ही एक और बात कहना चाहूंगी कि अभी केवल साठ वर्ष ही हुए हैं, जब हमने अंग्रेजों को यहां से भगाया था। उपसभाध्यक्ष महोदय, कभी अनजाने अनसोचे अनचाहे हम अपने हाथ से सत्ता विदेशियों को ने सौंप दें। अगर हमने ऐसा किया, तो स्वर्ग में बैठे उन अगणित शहीदों की आत्माएं कलपेंगी, दुखी होंगी, हमारी नासमझी और नादानी पर आंसू बहाएंगी और ताज़िंदगी हमें माफ नही करेंगे। महोदय, जो राष्ट्र अपने नायकों को भूल जाता है, वह राष्ट्र बरबाद हो जाता है, इस छोटी सी चेतावनी के साथ मैं इस अभिभाषण पर अपनी बात को आगे बढ़ाती हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने इस अभिभाषण को आदि से अंत तक पूरा पढ़ा है। कई बार पढ़ा है और मैं एक बात कह सकती हूं कि अभिभाषण विरोधाभासों का दस्तावेज़ है, A bunch of contradications और जितनी बार मैं इसको पढ़ती थी, एक नया विरोधाभास मेरे सामने उभरकर खड़ा हो जाता था। मैं यह बात कहने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं इस अभिभाषण में से एक-एक उदाहरण देकर इस आरोप को, अपनी इस बात को पुष्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें एक विरोधाभास दिखाई पड़ता है, बढ़ती हुई विकास दर बनाम बढ़ती हुई महंगाई का। महोदय, सरकार अपने अर्थ-प्रबंधन से बहुत खुश दिखाई पड़ती है। आर्थिक समीक्षा में भी वह खुशहाली झलकती है और इस अभिभाषण में भी। राष्ट्रपति महोदय अपना भाषण शुरू करते हुए कहते हैं कि हम आज अपने आर्थिक क्रिया-कलापों और भविष्य के संबंध में अत्यधिक आशावादिता के माहौल में एकत्र हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में आठ प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। उन्हें एक तरफ आशावादिता का माहौल दिखता है, लेकिन जब मैं अगला पैराग्राफ मुद्रास्फीति पर पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्री डा॰ मनमोहन सिंह और प्रधान मंत्री डा॰ मनमोहन सिंह के मन में एक द्वन्द चल रहा है। अर्थशास्त्री डा॰ मनमोहन सिंह बढ़ी हुई विकास दर को देखकर आत्ममुग्ध हैं, लेकिन प्रधान मंत्री

डा॰ मनमोहन सिंह बढ़ती हुई महंगाई के लिए चिंतित हैं। अर्थशास्त्री डा॰ मनमोहन सिंह जब अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में जाते हैं तो इसे बढ़ी हुई महंगाई को बढ़ी हुई विकास दर का द्योतक बताते हैं, एक खुशनुमा अर्थव्यवस्था का संकेत बताते हैं और महंगाई का औचित्य ठहराते हुए उसे उचित बताते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस सम्मेलन से वापस प्रधान मंत्री कार्यालय पहुंचते हैं, तो महंगाई को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख डालते हैं। अर्थशास्त्री डा॰ मनमोहन सिंह का तर्क है कि जब विकास दर बढ़ती है तो लोगों की जेबों में पैसा आता है और जब जेबों में पैसा आता है, तो खरीदने की ताकत बढ़ती है, क्रय-शक्ति, परचेज़िंग पावर बढ़ती है। उस पैसे को लेकर व्यक्ति बाजार में जाता है, तो चीजों की मांग बढ़ती है और जब मांग के बराबर आपूर्ति नहीं हो पाती, तो महंगाई बढ़ती है। महोदय, यह तर्क अर्थशास्त्रियों की समझ में तो आ सकता है, लेकिन अपनी-अपनी रसोई में खड़ी, खाली डिब्बे खड़काती हुई गृहणियों की समझ में नहीं आता। गली मोहल्लों में बैठे, बिना बिछौने की खाटों पर लेटे हुए लोगों की समझ में नहीं आता। महोदय, उनका पेट तर्कों से नहीं भरता है उनका पेट आंकड़ों से नहीं भरता है। उनको अपना पेट भरने के लिए गेहूं का दाना, चावल का दाना और दाल का दाना चाहिए,लेकिन उनकी खाने की थाली में से दाल-चावल नदारद हो रहा है। उनको दूध देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें राहत चाहिए, उन्हें समाधान चाहिए, लेकिन समाधान और राहत के नाम पर इस भाषण में कोरा आश्वासन मिला है। आश्वासन भी कैसा मिला है, मैं पढ़कर सुनाती हूं, 'मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है।' उपसभाध्यक्ष जी, प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ गया है। यह प्रतिकूल प्रभाव तो गरीब पर भी पड़ गया है और उस गरीब की मार का प्रतिकूल प्रभाव सरकार पर भी पड़ गया है। जिस समय यह अभिभाषण लिखा गया और उसके पढ़ने से एक दिन पहले पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव परिणाम आ चुके थे। वे परिणाम आपके कितने प्रतिकूल गए। आप दोनों जगहों पर, जहां पर सरकार में थे, आप सत्ताच्युत कर दिए गए। आप सत्ता से बाहर कर दिए गए, तो गरीब ने तो प्रतिकूल प्रभाव आप पर भी डाल दिया है, लेकिन उसका असर वित्त मंत्री पर नहीं पड़ा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उस अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है, जिसका कोई सानी नहीं है। वे अपना बजट भाषण पढ़ते हैं और pet lovers की बात कहते हुए, आदमी का खाना और

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

कुत्तों का खाना सस्ता कर देते हैं। हमें pet food घटाने से कोई ऐतराज नहीं है, आप घटाइए। सैकड़ों आइटम्स पर कस्टम डयूटी घटी है, उसमें एक यह आइटम भी जोड़ देते, लेकिन यह उनकी प्राथमिकता का प्रदर्शन है कि उन्होंने इस आइटम को इतना महत्वपूर्ण माना कि इसका उल्लेख अपनी बजट स्पीच में किया। इसे कहते हैं कि जले पर नमक छिड़कना। यह

उनकी अपरिपक्वता का प्रदर्शन है कि उन्होंने भूख से कराहते हुए लोगों पर, जो लोग राहत की बाट जोह रहे थे, ऐसी गृहणियों पर उन्होंने कुत्तों के खाने पर कस्टम ड्यूटी कम करके, डॉग विस्किट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करके, उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। यह पहला बिरोधाभास मैंने बताया। उपसभापति जी, बढ़ती हुई विकास दर बनाम बढ़ती हुई महंगाई का पहला विरोधाभास बताया है। अब दूसरा विरोधाभास देखिए। दूसरा विरोधाभास है, ''खाद्य सुरक्षा बनाम स्पेशल इकॉनॉमिक जोन'' का। सरकार कहती है, ''गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारी अहम नीति है''। लेकिन एक मंत्रालय, जो लक्ष्य निर्धारित करता है, दूसरा मंत्रालय उस लक्ष्य को ध्वस्त कर देता है। पैरा पंद्रह में सरकार खाद्य सुरक्षा की अपनी इस नीति का वर्णन करती है। ''मेरी सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है'' यह कहते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन पैरा 19 में राष्ट्रपति जी कहते हैं, ''कृषि भूमि के उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है और इसके मुद्दों पर नीति और कानून, दोनों दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी सरकार एक नई पुनर्वास नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ आपकी सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ आपकी सरकार कृषि भूमि के उचित मूल्य निर्धारण और पुनर्वास नीति की आवश्यकता को महसूस करती है। उपसभापति जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी जब अनाज का पूर्ण भंडार हमारे यहां होगा। जब खाने के लिए दाना लोगों के पास होगा और किसी अकाल की स्थिति से निपटने के लिए भंडार में पर्याप्त अनाज होगा, तब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आज से तीन साल पहले तक, उस कैबिनेट में मैं स्वयं मंत्री थी, जसवन्त सिंह जी मेरे साथ मंत्री थे, हर बार हमारे यहां एक प्रस्ताव आता था कि देश में इतना अनाज का भंडार है कि अनाज रखने की जगह नहीं है, इसलिए इस अनाज को समुद्र में फेंक देना चाहिए और नया अनाज भर लेना चाहिए। इसका मतलब भंडार भी भरे थे और नई आमद भी हो रही थी। फिर तीन साल में क्या ग्रहण लग गया कि सारे तो भंडार खाली हो गए, नई आवक खत्म हो गई और गेहूं का आयात करना पड़ा। मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई। हम बहुत बार यह सवाल पूछ चुके हैं कि वह अनाज कहां गया? नया अनाज क्यों नहीं आ रहा है? भंडार खाली क्यों है? बाजार में कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? चलिए, इसका जवाब तो आप अलग से देंगे, लेकिन मैं जिस विरोधाभास की बात कर रही थी, आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, खाद्य सुरक्षा तब होगी, जब ज्यादा कृषि योग्य भूमि पर पैदावार होगी। ज्यादा कृषि योग्य भूमि कैसे बनेगी? जब असिंचित भूमि सिंचित होगी, अनइरिगेटिड लैंड इरिगेटिड होगी। आप जानते हैं हिंदुस्तान में कितनी भूमि असिंचित है और कितनी भूमि पर हम हर साल सिंचित कर रहे हैं। मैं आप ही का

दिया हुआ एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूं। यह मेरा स्वयं का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 252 अतारांकित प्रश्न, 27 फरवरी को उत्तर दिया गया। मैंने पूछा था, देश में राज्यवार कुल कितनी असिंचित भूमि है, जवाब आया है, देश के भीतर 85.8 मिलियन हेक्टेयर यानी 858 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है, और लक्ष्य है 2.40 मिलियन हेक्टेयर का यानी 858 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है, केवल 24 लाख हेक्टेयर भूमि इस वर्ष सिंचित करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। अगर इस गति से भूमि सिंचित होगी तो सारी भूमि को सिंचित होने में पैंतीस वर्ष लग जाएंगे। लेकिन असिंचित भूमि को सिंचित करना एक बात, जो सिंचित भूमि है, जो उर्वरा भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, जो धन धान्य वसुन्धरा है, जो आपको लहलहाती फसल दे रही है, उसे आप अधिगृहीत कर रहे हैं या बेचने की अनुमति दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री लक्ष्य रख रही है गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का और आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री लक्ष्य रख रही है कृषि भूमि से उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास का। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यह जो असिंचित भूमि है, क्या यह उद्योगों के लिए नहीं दी जा सकती? उर्वरा भूमि अधिगृहीत करना जरूरी है क्या? उपसभापति जी, मुझे दुख होता है कि हमारे वामपंथी साथी, सदियों से जिनके मुंह से हम एक ही स्वर सुनते आए कि संदक इमसवदहे जव जपससमतेण आज उनका भी सुर बदल गया। आज वे भी कहने लगे कि संदक इमसवदहे जव उपससमतेण कभी सिंगूर घटता है, कभी नंदीग्राम घटता है। उर्वरा भूमि, उपजाऊ भूमि किसानों से लेकर अगर आप उद्योगों के लिए दे देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जॉंस के लिए दे देंगे, रोजगारों के अवसर सृजन करने के नाम पर किसानों को बेरोजगार करने का सरकार ने ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह खाद्य सुरक्षा बनाम सेज़ का विरोधाभास समाप्त करिए। अगर आप वाकई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जितनी भूमि कृषि के नीचे है, खेती के नीचे है उसको बने रहने दीजिए और यह जो असिंचित भूमि है, इसको सिंचित करके और पैदावार बढ़ाने का काम करिए, तब जाकर यह विरोधाभास समाप्त होगा।

उससभापति जी, मैं तीसरा विरोधाभास बताती हूं — कृषि ऋण बनाम किसान हत्याओं का। कृषि ऋण के लिए पैराग्राफ नं. 17 — यह सरकार कहती है कि हमारे पास कृषि ऋण के लिए बहुत उपलब्धता है। बजट में भी यह बात कही गई और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी यह बात कही गई। लेकिन उपसभापति जी, प्रतिदिन किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि हो रही है और प्रदेशों में भी वृद्धि हो रही है। गिल साहब बैठे हैं। गिल साहब, मैं एक गल कही सी पंजाब विच जाके कि सानु इस गल दा गर्व सी कि पंजाब दे विच आत्महत्यावां नहीं हुंदियां। पर कैप्टन ने यह अभिमान भी साडे तो खो लिता। उपसभापति जी, अभी तक तो आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ, इन प्रदेशों के नाम आत्महत्याओं से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे दुख होता है कि अब उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड और हमारा समृद्ध प्रान्त पंजाब आत्महत्याओं के घेरे में आ गए। पंजाब

ज़ैसे प्रदेश का नाम किसानों की आत्महत्याओं के साथ जुड़ जाए, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। गृह मंत्री जी, जरूरत है किसान को इस भंवर से उबारने की, लेकिन आप तो किसान को और कर्ज में फंसाने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात का दुख हुआ। देखिए, पैराग्राफ 17 में क्या लिखा है — "एक विशेषज्ञ दल कृषि ऋणग्रस्तता की समस्या की जांच कर रहा है और वह त्रस्त किसानों को राहत देने के उपाय सुझाएगा।" संकोच होना चाहिए ऐसी बात लिखते हुए। उपसभापति जी, आप इस पीठ पर बैठते हैं। जब हम अन्दर विषयों की पहचान करते हैं, आप वहां बैठे होते हैं। हर सत्र में farmers' suicide का विषय identify किया गया और चर्चा भी हुई। लोग कहते थे कि और किसी विषय पर चर्चा न हो, farmers' suicide पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो संसद हर सत्र में किसानों की समस्या के लिए, किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर चर्चा कर रही है, उस संसद में खड़ी हुई सरकार कहती है कि विशेषज्ञ दल अभी जांच कर रहा है, उपाय सुझाएगा। कब वह जांच पूरी होगी, कब वे उपाय किए जाएंगे, कब उन उपायों के ऊपर नीति बनेगी, कब उस नीति पर अमल होगा और कब किसान अपनी आत्महत्या करना बंद करेंगे। इस एक वाक्य को पढ़ कर मेरे मन में केवल ग़ालिब का वह शेर उभरा, जिसको आज़मी साहब कह सकेंगे, appreciate कर सकेंगे।

"यह तो माना कि तग़ाफ़ुल न करोगे लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक।"

मुझे मालूम है कि यह सरकार बेवफाई नहीं करेगी, कहती है, लेकिन जब तक वफादारी करेगी, तब तक किसान भस्म हो चुके होंगे, चिता की राख बन चुकी होगी। यह तीसरा विरोधाभास है किसान के ऋण बनाम किसानों की आत्महत्याओं का।

उपसभापति जी, मैं चौथा विरोधाभास आपके सामने रखती हूं। ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक। उसका बहुत गाना गाया गया। बहुत गाना गया। क्या है वह विधेयक? क्या प्रदान करता है वह विधेयक? पहले तो हम उसका खुलासा कर लें। इस अभिभाषण में उसको सामाजिक सुरक्षा कवच कह कर पुकारा गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक का पैराग्राफ नं॰ 10 है — सामाजिक सुरक्षा कवच। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है। महोदय, पहले मैं यह बता दूं कि यह विधेयक क्या है। पहली बात, यह विधेयक शहरों पर नहीं, केवल ग्रामीण क्षेत्र पर लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 जिलों में लागू है जिसे अभी 330 किया है, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में 200 जिलों तक लागू है यानी दो-तिहाई भारत अभी इस से अछूता है। यह केवल एक-तिहाई भारत पर लागू है और यह कार्यक्रम एक बड़े कार्यक्रम एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है। महोदय, एक-तिहाई क्षेत्र में, जहां यह लागू है,

वहां इस विधेयक ने क्या दिया, यह सुन लीजिए। इस विधेयक के तहत सौ दिनों का गारंटी रोजगार दिया। इस विधेयक के तहत सौ दिन का निश्चित तौर पर रोजगार दिया जाएगा और वेतन 60 रुपए रोज दिया जाएगा। उपसभापति जी, अगर हम असंभव को संभव मान लें तो पूर 200 जिलों में यह रोजगार मिलता, सौ दिन का पूरा रोजगार मिलता, एक रुपए के 18 पैसे नहीं, पूरे 60 रुपए वेतन मिलता। अब पूरे 60 रुपए वेतन मिलता तो क्या मिलता — 100 x 60 यानी 6 हजारे रुपया। अब वर्ष में 12 महीने होते हैं और अगर 6000 को 12 से तकसीम करें तो 500 रुपए निकलता है। अब यह विधेयक 500 रुपए देता एक परिवार को, एक household को, तो आप पहले मुझे यह बता दीजिए कि यह विधेयक सब कुछ देता तो क्या 500 रुपया आज के जमाने में एक परिवार के तन ढकने और पेट भरने के लिए काफी है? यह मजाक नहीं है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि अगर इस पर पूरा अमल हो जाता है और सौ दिन का रोजगार भी मिल जाता, 60 रुपए का वेतन भी मिल जाता, तो भी हम कहते कि जो विधेयक ने कहा था, वह मिल गया।

आप जानते हैं बजट भाषण में इस विधेयक की क्या समीक्षा उभरकर आयी है, जो एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है?

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Are you objecting to that programme? ..(*Interruptions*).. I am just asking this question. ..(*Interruptions*).. I only asked one question. ..(*Interruptions*).. Are you objecting to that programme? This is what I wanted to know.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am not opposing that. I am only elaborating that law. I am not opposing that law. I am only explaining that law. अगर मैंने उस में कुछ गलत कहा है तो बताइए? आप ने 100 नहीं 500 दिया था, आप ने 60 रुपया नहीं 100 रुपया दिया था। महोदय, जो दिया था वह मैंने बताया। मैंने कहा कि यह टोटल दिया था, मगर मिला क्या? बजट की समीक्षा में आया है साढ़े 37 दिन का रोजगार इस विधेयक के माध्यम से मिला। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह बजट समीक्षा के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। Rural plan fails to honour guarantee. Average of 37.5 mandays work provided against promised hundred. इसका हैडिंग है 'Flop Show'. यह हैडिंग मैंने नहीं लगाया है, यह भारतीय जनता पार्टी का समाचार पत्र नहीं है, न यह हमारे पार्टी कार्यालय से निकलने वाला भा॰ज॰पा॰ समाचार या बी॰जे॰पी॰ टुडे की रिपोर्ट है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया है और इसे आप बहुत ''प्रो बी॰जे॰पी॰ पेपर'' भी नहीं कह सकते। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आप से कहना चाहती हूं कि जिस ग्रामीण रोज़गार गारंटी विधेयक पर लाखों नहीं, करोड़ों रुपया प्रचार पर खर्च किया गया था, बड़े-बड़े होर्डिंग्स के साथ

अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे, टी०वी० पर उसका विज्ञापन आज तक चल रहा है। मैंने भी परसों देखा। एक महिला सिर पर टोकरी रखकर ''चलो री चलो गांव में काम आया है'' बोलती जा रही है। यह है उस गांव में काम आने का फ्लॉप शो जिस में सिर्फ साढ़े 37 mandays of work मिलता है। यह है आप के ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक का विरोधाभास - साढ़े 37 दिन का रोजगार। यह चौथा विरोधाभास मैंने आप के सामने रखा। अब इसके आगे मैं एक और विरोधाभास की बात करने जा रही हूं।

सर, पैरा 26 में अल्पसंख्यकों की बात की गई है। सरकार के अन्दर अल्पसंख्यकों की घरेलू नीति और विदेश नीति में बहुत बड़ा विरोधाभास है। उपसभापति जी, जब भी कोई सरकार आती है, तो वह अपना एक थीम निर्धारित करती है, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करती है और अपनी नीतियां उस थीम को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाती है। यह सरकार जब आई तो इसने अल्पसंख्यकों के वोटों पर आंखें गड़ाईं और अल्पसंख्यकों के वोट बटोरने के प्रयास शुरू किए। उसी प्रयास में से निकला - मजहब पर आधारित आरक्षण; उसी प्रयास में से निकला - गोधरा कांड पर बनर्जी कमेटी का गठन; उसी प्रयास में से निकला - अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का रिजर्वेशन से एग्जेमप्शन; उसी प्रयास से हो रहा है - बे-खौफ धर्मांतरण और उसी प्रयास में से निकला - सच्चर कमेटी का गठन। लेकिन जब सच्चर समिति सामने आ गई, तो सरकार मुंह छिपाने लगी, क्योंकि वह समिति इन तथाकथित मुस्लिम हितैषियों को इनका आइना दिखा रही थी। हमने पिछली बार बहुत कहा कि इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार दाएं-बाएं कर के निकल गई। इस राष्ट्रपति अभिभाषण में उन्होंने कहा है कि हम चर्चा कराएंगे। देखें, चर्चा होती है या नहीं। कम-से-कम मेरा मन तो नहीं मानता कि चर्चा होगी, क्योंकि उस समिति में इनका एक ऐसा चेहरा उभरकर आएगा, खास तौर पर उन लोगों का, जो मुस्लिम समुदाय के सबसे ज्यादा पैरोकार बनते हैं। देश में दो राज्यों के मुस्लिमों को सबसे ज्यादा बदहाली की हालत में दिखाया गया। उनमें एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है बिहार। पश्चिम बंगाल, जहां पिछले 25 वर्षों से वामपंथियों का शासन है और बिहार, जहां 15 वर्षों तक आर०जे०डी० का शासन रहा है। हम चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि वह रिपोर्ट पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से ग्रस्त है। वह रिपोर्ट देश के नए विभाजन की नींव डालने का काम करती है। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो। अभी तक जो हमने बी०ए०सी० में विषय पहचाने हैं, उनमें उस विषय को सच्चर समिति के नाम से तो सरकार ने नहीं माना, लेकिन status of minorities के नाम से माना है, लेकिन, अगर चर्चा होगी तो उसकी विकृतियों और विसंगतियों को हम लोग सामने निकाल कर रखेंगे।

उपसभापति जी, घरेलू नीति, पर मुस्लिम वोट बटोरने का यह प्रयास चल रहा है, लेकिन सरकार जैसे ही अमेरिका की तरफ उन्मुख होती है, ये सारे प्रयास धराशायी हो जाते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति बुश भारत आते हैं, तो भारत की संसद एक संयुक्त अधिवेशन में उनके भाषण का आयोजन नहीं करवा सकती, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वह ऐसा करवाएगी, तो हिन्दुस्तान का मुसलमान उससे विमुख हो जाएगा, उसको वोट नहीं देगा। यह अमेरिका-परस्ती इतने तमाम प्रयासों के बावजूद देश के मुसलमान भाईयों के गले नहीं उतर रही है और सरकार इस द्वंद्व में ग्रस्त है कि घरेलू नीति चलाए या विदेशी फ्रंट पर अमेरिका-परस्त नीति चलाए।

सर, अब मैं छठे विरोधाभास की बात करती हूं-शिक्षा के आवंटन बनाम शिक्षा पर लगे एजुकेशन सेस की। उपसभापति महोदय, बजट आ गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर डा॰ मनमोहन सिंह जी ने कहा—Education and health are the cornerstones of this Budget वित्त मंत्री जी ने भी शिक्षा पर कई पैराग्राफ लिख डालें उनकी यह बजट स्पीच मेरे पास है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसका सब वक्ताओं ने जिक्र किया, उस पर क्या आवंटन हुआ है-10 हजार 671 करोड़ रुपए। यह देखिए। In Para 15 of the Budget Speech, it is mentioned: Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-day Meal Scheme: Out of this amount, Sarva Shiksha Abhiyan will be provided Rs. 10,671 crores. 10 हजार 671 करोड़ बहुत ज्यादा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने शायद इतना पैसा दे दिया। उपसभापति जी, उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिए। जो एजुकेशन सेस लगाया था, मैंने यह जानना चाहा कि उससे कितना पैसा आया, क्योंकि सेस तो हमेशा एडिशनल अमाउंट देता है? तो मैंने बजट दस्तावेजों में से Expenditure Volume 1 निकाला और उसमें मुझे वह 10,393 करोड़ का आंकड़ा मिल गया तथा वह आंकड़ा बजट स्पीच में टैली भी हो गया। उससे बिल्कुल अगले पैराग्राफ में यह लिखा है—The transfer to Prarambhik Shiksha Kosh will increase from Rs. 8746 crore to Rs. 10,793 crores. एग्जैक्ट रिकन्साइल कर दिया वह आंकड़ा। अब मुझे आप बताइए कि 10,393 करोड़ रुपया आपका एडिशनल सेस से आता है और 10,671 करोड़ रुपया वित्त सर्व-शिक्षा अभियान के लिए देते हैं, तो अपनी जेब से क्या देते हैं? 300 करोड़ से कम, और जब सेस नहीं लगा था, तब भी तो हम शिक्षा के लिए आवंटन करते थे, लेकिन आज इस सारे के सारे पैसे का बोझ आपने आम जनता पर डाल दिया है। यह 10,693 करोड़ रुपया आपको एजुकेशन सेस से मिलता है और आप 10,671 करोड़ रुपया सर्वशिक्षा अभियान के लिए दे देते हैं। यही खेल आगे उच्च शिक्षा में किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए 6,483 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, लेकिन उसके साथ ही अतिरिक्त उपकर लगा दिया, एक परसेंट एडिशनल सेस लगा दिया। अगर 10,393 को बेंच मार्क मान लें, तो अतिरिक्त उपकर से 5,200 करोड़ रुपया और आ जाएगा। आपने अपनी जेब से क्या दिया? 1200 करोड़ रुपया।

उपसभापति महोदय, यह वैश्वीकरण का युग प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का युग है। इसमें हर देश अपनी ताकत की पहचान कर रहा है कि किस क्षेत्र में मेरी शक्ति है, मैं उसका संवर्द्धन करूं, तभी प्रतियोगिता में टिक पाऊंगा भारत ने बहुत सही तौर पर ज्ञान को अपनी ताकत के रूप में पहचाना है। हम नॉलेज इकोनोमी की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। हमने एक ज्ञान-आयोग का गठन किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता यह 6,493 करोड़ रुपए से पूरी होगी। यहां तो हमें इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे एनडीए सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में केवल सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1,60,000 करोड़ की योजना बनाई थी। उस कमय लोग पूछते कि पैसा कहां से आएगा? आज खुद सरकार कह रही है कि 2,22,000 करोड़ रुपया हमने सड़कों पर खर्च कर दिया है। इसलिए यह 6,400 करोड़ रुपए का मामला नहीं है, यह 1,06,400 करोड़ का मामला है। आज मेधावी और प्रतिभावान छात्र हमारी पूंजी है। अगर इन्हें हमें संभालकर रखना है, अगर इनकी ताकत हमें बढ़ानी है, तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी कि हर राज्य में एक-एक आईआईटी, एक-एक आईआईएम, एक-एक एम्स देने का काम करिए, ताकि हर राज्य के अंदर बच्चे इस नॉलेज इकोनोमी में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान कर सकें, लेकिन मुझे दुख से कहना कहना पड़ता है कि यह एक-एक आईआईटी, एक-एक आईआईएम, एक-एक एम्स क्या देंगे?

उपसभापति महोदय, वर्ष 2003 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री हुई थी, यहां जसवन्त सिंह जी बैठे हैं, इनकी अपार कृपा से, मैं ''अपार कृपा'' शब्द हृदय से कह रही हूं और वह इसलिए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना की वह स्कीम नहीं थी, जब मैं वर्ष 2003 में आई थी, तो पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी। वह दसवीं पंचवर्षीय योजना की स्कीम नहीं थी, लेकिन मैंने जाकर इनसे कहा कि जसवन्त सिंह जी, मैं देश में 6 एम्स बनाना चाहती हूं, लेकिन यह स्कीम टेन्थ फाइव ईयर प्लान की स्कीम नहीं है । इन्होंने कहा कि क्या हुआ, सुषमा जी, अगर टेन्थ फाइव ईयर प्लान में कोई स्कीम नहीं आई, तो क्या वह दूसरी स्कीम रुक जाएगी, आप आगे बढ़िए। मैंने कहा — पैसा बहुत लगेगा। बोले—मैं दूंगा, जितने मर्जी की स्कीम बनाकर आप लाइए। वह स्कीम थी 6 एम्स की और उसमें केवल भाजपा शासित राज्य नहीं थे, जिसमें मैंने एम्स दिया था— छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह कांग्रेस शासित राज्य थे। उत्तरांचल में दिया, बिहार में राजद की सरकार थी, तीनों कांग्रेस शासित राज्य थे, एक उड़ीसा में एनडीए का राज्य था, भाजपा शासित राज्य नहीं था इन 6 पिछड़े राज्यों की पहचान की थी और 10 महीनों की अवधि में योजना भी बना दी, इन-प्रिंसिपल एप्रूवल भी ले ली, उसके बाद जमीनों का आवंटन भी करवा लिया, जमीनों का शिलान्यास भी करवा दिया और इनके बजट भाषण में बजट मद भी बनवा दी थी, जिसमें से 6 करोड़ रुपया ले लिया गया, एक-एक करोड़ रुपए की चारदीवारी

भी खड़ी कर दी गई। आपको लगता है इतनी सुपर हाई स्पीड से कम हो सकता है? मगर यह हुआ। यह सच है, दस महीने में योजना तैयार होकर वहां चारदीवारी खड़ी हो गई थी, लेकिन पिछले तीन साल से प्रतीक्षा चल रही है कि आगे कोई ईट तो किसी एम्स में लग जाए। इन चारदीवारियों से कोई एकाध ईट निकालकर जरूर ले गया होगा, लेकिन आगे एक ईट का भी निर्माण इन 6 एंम्स में सरकार नहीं करवा पाई, और हम बात करते हैं शिक्षा की। इसलिए, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उन 6 AIIMS का निर्माण तो कराइए ही, लेकिन एक-एक IIT, एक-एक IIM और एक-एक AIIMS हर राज्य को देने का काम करिए, तब इस प्रतियोगी युग में भारत टिका रह सकेगा।

उपसभापति महोदय, अब अगले विरोधाभास की बात करती हूं, जो महिला आरक्षण बनाम महिला विकास का है, पैरा 30, गृह मंत्री जी, सिर्फ पांच मिनट के लिए यह सुनते जाइए, क्योंकि यह आपसे ही जुड़ा मुद्दा है। आप बहुत कृपालु हैं कि आप बैठे रहे, वरना मुझे तो लग रहा था कि सत्ता पक्ष की बैंचों पर लोग नहीं हैं, प्रस्तावक, अनुमोदक नहीं हैं, पर चलिए, आप चूंकि सबको कम्पनसेट कर रहे थे, अगले दोनों पैराग्राफ मैं आपको सम्बोधित कर रही हूं। पैरा 30पर बाद में आऊंगी, राम देव भंडारी जी आ जाएं, फिर बात करुंगी। पैरा 13- महिला और बाल विकास मंत्रालय। उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी कहते हैं '' महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले तथा उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने वाले ऐतिहासिक विधान बनाए गए हैं। गृह मंत्री जी, ऐतिहासिक विधान की तो हम इंतजार कर रहे हैं बनाए तो रूटीन के विधान गए हैं। जब संसद बैठती है, सरकार चलती है, तो लेजिस्लेशन तो आते हैं, बिल तो बनते हैं। हम हर सत्र में बीसियों बिल पास करके उठते हैं और बीसियों बिल संसद बना रही है। एक ऐतिहासिक विधान बना था 73वें, 74वें संशोधन के माध्यम से, जब ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के मेयर तक 33 फीसदी का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन पिछले 11 वर्ष से हम ऐतिहासिक विधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे दुख है कि तीन वर्ष पहले तक उस ऐतिहासिक विधान का एक प्रारूप तो था, ड्राफट देखकर तो खुश हो लेते थे, सोचते थे कि शायद कभी न कभी चर्चा भी हो जाएगी, लेकिन पिछले तीन वर्षों से तो हम इस ऐतिहासिक विधान के प्रारूप को भी तरस गए हैं महिला आरक्षण विधेयक का एक ड्राफट बिल भी हमारे सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग हमारे ड्राफट बिल को संसद में फाड़ा करते थे, वे अब कैबिनेट में बैठे हैं, वे कैबिनेट से ही उसको निकलने नहीं देते, कैबिनेट में ही सहमति नहीं हो पा रही। एक भी ड्राफट बिल आप कहां यहां लाकर नहीं रख सके। उपसभापति जी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह संयोग है कि मैं उसकी पूर्व संध्या पर अपनी बात कह रही हूं। लेकिन मुझे शर्म आती है, एक आंकड़ा IPU के माध्यम से परसों पढ़ने को मिला IPU— Inter Parliamentary Union ने यह आंकड़ा जारी किया है। पूरी दुनिया में 189 देश

हैं। आप जानते हैं गृह मंत्री जी कि महिला प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भारत का नम्बर क्या है? 108वां पड़ोसी पाकिस्तान हमसे ऊपर है और थोड़ा-बहुत ऊपर नहीं है, बल्कि उसका स्थान 48वां है। पाकिस्तान महिला प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में 48वें नम्बर पर और भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 108 वें नम्बर पर, क्या यह शर्म की बात नहीं है। 10 प्रतिशत से कम का आरक्षण, 10 प्रतिशत से कम का प्रतिनिधित्व। 1996 में बिल आया था, देवेगौड़ा जी के समय रखा गया, गुजराल जी के समय रहा, हमारी दो सरकारें आई 1998 में, 1999 में, लेकिन लोक सभा डिजॉल्व हो जाती थी, बिल चला जाता था, दोनों बार रखा गया और संसदीय कार्य मंत्री के नाते तो मैंने आर्डर पेपर पर चर्चा के लिए भी रख दिया था, लेकिन तीन साल से हम तरस रहे हैं, बिल का कोई प्रारूप भी नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो सुरक्षा की बात करते हैं, सशक्तिरण की बात करते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण या सामाजिक सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा और अगर एक बार आप राजनीतिक सशक्तिकरण कर देगें तो फिर उन्हें किसी से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं एक तिहाई यहां बैठी होंगी, वे अपने विधान स्वयं बना लेंगी, अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगी। लेकिन आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, जब यह तस्वीर उभरकर आई है कि भारत का 108वां नम्बर है, तो कम से कम कल, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज रात को बात करके, जहां-जहां आपको बात करनी है, अगर कल आप यह आश्वासन दे दें कि बजट के इस सत्र में, पहले खंड में तो मैं नहीं कहती, वह अव्यवहारिक होगा,.....। और बीच में रिसेस आ रही है, उसके बाद दूसरा खंड आ रहा है। कल हमारे यहां प्रधान मंत्री जी जवाब देने आ रहें है। अगर अपने जवाब में कल वह हमें इतना आश्वासन दे दें कि बजट के सत्र के द्वितीय खंड में वह इस बिल को ला कर पारित करवाएंगे, तो निश्चित तौर पर मैं यह कहूंगी कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर मेरा बोलना सफल हो गया है।

उपसभापति जी, इसमें आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र का एक और विरोधाभास उभरा है, वह भी आपसे संबंधित है, इसलिए मेहरबानी होगी अगर आप पांच मिनट और बैठें।

मैं पैरा 42 को कोट करना चाहूंगी। पूरा पैराग्राफ तो मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, राष्ट्रपति जी कहते हैं,

''जहां हमारी सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों ने आतंक फैलाने के आतंकवादी गुटों के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है, वहीं मुम्बई तथा असम में और अभी हाल ही में, समझौता एक्सप्रेस पर हमले की दुखद और कायरतापूर्ण आतंकी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सामने आई इन सभी चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है।''

यह सत्य नहीं है,यह बिल्कुल सत्य नहीं है। सख्ती भरे बयान तो टीवी पर जरूर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन मालूम नहीं आपने एमओएस को क्या जिम्मेदारी दे रखी है कि वह टेलिविज़न पर

ज्यादा दिखाई देते हैं और दफ्तर में कम काम करते हैं। मुझे नहीं मालूम लेकिन जब ट्राज़ैक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स में आबंटन किया जाता है, तो एक जिम्मेदारी उन्हें यह दी गई है कि जब भी कोई बड़ी घटना हो तो जा कर टीवी पर बोलना शुरू कर दें। टीवी पर सख्ती भरे बयान जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि सरकार इन चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है, तो यह बात सत्य से परे है।

उपसभापति जी, आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व के तमाम देशों ने विशेष कानून बनाए हैं, कम से कम इससे उनकी नीयत तो पता चलती है कि वे आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। लेकिन यह अकेली सरकार है और भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर बने हुए कानून को रद्द किया जाता है और जब पूछा जाता है कि कानून क्यों रद्द कर रहे हो, तो एक ही वाक्य का तर्क दिया जाता है कि पोटा मुस्लिम विरोधी है। नहीं, गृह मंत्री जी, पोटा मुस्लिम विरोधी नहीं था, पोटा मुजरिम विरोधी था और मुजरिम का कोई मज़हब नहीं होता। वह न हिन्दू होता है न मुसलमान, न ईसाई, न सिख, मुजरिम केवल मुजरिम होता है। एक तो आज विशेष कानून हैं नहीं और अगर किसी पुराने कानून के कारण अदालत ने फैसला दे दिया तो उस फैसले पर अमल करने की हिम्मत नहीं है।

आप अफज़ल की फांसी को और कितने दिनों तक रोके रहेंगे?कितने दिन? क्या इससे बड़ी दुर्घटना कोई हो सकती है कि वह संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाती है, उसकी पूरे की पूरी लीडरशिप को कोई व्यक्ति समाप्त करने का प्रसास करे। एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, उसे फांसी की सज़ाएं देती जाएं और उसके बाद वह एक पुनरीक्षण याचिका दायर करे, उसे भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, सरकार किस चीज़ का इंतजार कर रही है? आप चुनाव निकालना चाहते हैं? कितने चुनाव निकालेंगे?

मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं, जब आप यह कहते हैं, साथ ही लोग यह तर्क देते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए सरकार ऐसा कर रही है, तो मुझे दु:ख होता है, क्योंकि ऐसा करके आप हिन्दुस्तान के मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिहन लगा रहे हैं। देश का कौन सा मुसलमान ऐसा कहता है कि देश के एक आतंकवादी मुसलमान को फांसी मत दो? क्या किसी आम मुस्लिम नेता या आम आदमी ने आपसे यह आ कर कहा? आप उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान लगाते हैं, जब आप यह कहते हैं कि यूपी का चुनाव निकल जाने दिया जाए, उसके बाद फांसी की बात होगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आंतरिक सुरक्षा का यह विरोधाभास बहुत दुखद रूप में इस अभिभाषण के अन्दर सामने निकल कर आया है, क्योंकि विरोधाभास कथनी और करनी का भी है, विरोधाभास सोच का भी है।

उपसभापति जी, अब मैं अंतिम पैराग्राफ पर आती हूं। वह तो विरोधाभासों से भरा पड़ा है ...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कह रही हैं। आपके विचारों से सहमत नहीं होते हुए भी, जिस प्रकार से आप अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा आंतरिक सुरक्षा के बारे में कि हम जब आंकड़े देकर आपको बताते हैं तो कहते हैं कि आंकड़े क्यों दे रहे हो। आप चर्चा मांगते हैं और हम चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं और चर्चा करने के बाद हम जो बताना चाहते हैं तो वह सुनने के लिए आप नहीं बैठते हैं। उसके बाद हम लिखित रूप से आपको देते हैं और पढ़ने में देरी हो जाए इसलिए ग्राफ के रूप में दे देते हैं। शायद उतना आप देख लें और फिर बताएं कि आंतरिक सुरक्षा का मामला सुधरा है या बिगड़ा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: गृह मंत्री जी, जहां तक आपके आंकड़ों का सवाल है, आपको मालूम है कि मैं तो स्वयं कमेटी ऑन होम की चेयर पर्सन हूं। इसलिए मैं तो उन आंकड़ों को आदि से अंत तक पढ़ती हूं। मैं यहां आंकड़ों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस वाक्य की बात कर रहीं हूं कि जहां आपने कहा है कि हम सख्ती से निबट रहे हैं। वहां मैंने आपको एक प्रसंग बताकर यह कहा कि क्या इसीको सख्ती से निबटना कहते हैं। मैंने तो केवल इतनी बात का जवाब मांगा कि एक व्यक्ति जिसने संसद पर हमला किया, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है तीनों अदालतों से, जिसकी पुनरीक्षण याचिका भी समाप्त और रद्द कर दी गई, उसकी फांसी अगर आप रोके हुए बैठे हैं तो क्या ऐसी सरकार यह दावा कर सकती है कि हम आंतरिक सुरक्षा को सख्ती से निबट रहे हैं। मैंने तो केवल एक बात के ऊपर अपनी बात कही, और बाकी लम्बी बात जब जवाब देंगे तब बता दीजिए।

उपसभापति जी, मैं अंतिम पैरा पर आ रही हूं। मैंने कई विरोधाभासों का जिक्र किया। यह अंतिम पैराग्राफ है तो छोटा, लेकिन यह अकेला पैराग्राफ है, तीन-तीन विरोधाभासों को उजागर करता है। पहला, सरकार में सुधार, इसे अधिक पारदर्शी और उत्तराकारी बनाना तथा भ्रष्टाचार के कैंसर का उन्मूलन समग्र विकास की किसी भी नीति के अनिवार्य तत्व हैं। मैं तो एक सीधा सा सवाल पूछती हूं बहुत छोटा सा, गृह मंत्री जी, क्या आपकी सरकार भ्रष्टाचार को कैंसर मानती है, क्या आपकी सरकार भ्रष्टाचार को, मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को शामिल करने में, भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने में इस सरकार का कोई सानी नहीं है। उपसभापति महोदय, पहली बार हुआ है कि एक केबिनेट मिनिस्टर कत्ल का दोषी पाया जाए, सजा मिल जाए, सजा के लिए जेल काट रहा हो, लेकिन वह अभी तक माननीय सांसद बना हुआ है। प्रधान मंत्री में यह हिम्मत नहीं कि जेल काट रहे एक मिनिस्टर से एम. पी. शिप से इस्तीफा लें। यह एक सांसद की बात है।...**(व्यवधान)**...मंत्री कौन है, यह मैं बताऊं। आपको यह भी नहीं पता कि कौन है, मैं किसकी बात कर रही हूं। और हर रोज एक नया तत्व सामने आ जाता है। अभी कल रात को खुलासा हुआ कि कांग्रेस के एक सांसद भारत के नागरिक नहीं, पत्नी की हत्या के अपराध में दोषी जेल काटते हुए सांसद बने बैठे हैं। उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि पांच हजार रुपए की रिश्वत लेने पर यह संसद ...**(व्यवधान)**

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Can you yield for a minute? Mr. Deputy Chiarman, Sir, there was a chargesheeted Minister in the NDA Government....(*Interruptions*).

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): सर, अगर वे बोलेंगे तो .....*(व्यवधान)*

श्री उपसभापति: उन्होंने यील्ड किया है।

SHRI V. NARAYANASAMY: As Shrimati Sushma Swaraj was Parliamentary Affairs Minister in the NDA Government, she will also agree with me that there were Ministers who had been chargesheeted. They were holding important positions, the highest positions, in the Government. That was the situation in the NDA Government also.

श्रीमती सुषमा स्वराज: नारायणसामी जी, मुझे आपकी तुलना पर हंसी आती है, कम से कम कोई प्रसंग बराबर का तो लेकर आते chargesheeted Ministers were in the Cabinet.' मैं कह रही हूं एक व्यक्ति मर्डर का दोषी, हाई कोर्ट से चार्जशीटेड नहीं हाई कोर्ट से सजा याफ्ता और सजा के लिए कंविक्ट होने के बाद जेल में और वह मेंबर बना हुआ है, वह सांसद है। इसका कोई सानी कोई बराबर में आपका, एन.डी.ए. में आप बताना चाह रहे हैं। और कल जो निकला वह भारत का नागरिक नहीं, पत्नी का हत्यारा और बैठा है संसद् में और मैं आपसे यह पूछना चाह रही थी कि केवल पांच हजार रुपए की रिश्वत प्रश्न पूछने के लिए लेने के अपराध में इस संसद् ने दस सदस्यों को निकाल बाहर कर दिया।

पांच हजार रुपये की रिश्वत, केवल प्रश्न पूछने के लिए लेने के अपराध में, इस संसद ने 10 सदस्यों को निकाल बाहर कर दिया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, लेकिन एक मर्डर का दोषी व्यक्ति, जेल काटने वाला व्यक्ति सांसद बना हुआ है, यह विरोधाभास नहीं है, तो और क्या है? .... (व्यवधान)....मैंने तो निकाल दिया था। .... (व्यवधान).... मैंने तो निकाल दिया था। ....(व्यवधान)....सभ्रवाल जी,...(व्यवधान)....एक मिनट। एक मिनट।....(व्यवधान).... सभ्रवाल जी, मैं जिस कमेटी की मेम्बर थी, उसमें मेरी ही पार्टी का व्यक्ति फंसा हुआ था और मैंने निकाल दिया था। अगर किसी एक को मोह होता, तो मुझे हो सकता था। उसे पहले दिन निकाल दिया था। यह विरोधाभास नहीं है, तो और क्या है? मैं अब इस पैराग्राफ के दूसरे विरोधाभास की ओर आती हूं। पहला विरोधाभास अंतिम पैराग्राफ का, क्या भ्रष्टाचार को कैंसर मानते हो, ऐसे-ऐसे लोग पाले हुए हैं और उनको कहते हो कि भ्रष्टाचार कैंसर है। दूसरा विरोधाभास है - सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने का एक साधन है। सूचना के अधिकार की आप बात करते हो, गृह मंत्री जी, और 17-17 दिन संसद् से, देश से, अदालतों से एक महत्वपूर्ण सूचना को छुपाते हैं, यह विरोधाभास नहीं, तो और क्या है?

उपसभापति जी, जिस समय मैंने विदेशी मूल का प्रश्न उठाया था, तो एक वाक्य कहा था, शायद देश के लोग भूल गए हों। मैंने यह कहा था कि सामान्य समय में सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन जिस दिन कभी भारत और इटली का हित टकरायेगा, उस दिन यह कहावत चरितार्थ होगी, Blood is thicker than water...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): बिल्कुल गलत है।...(**व्यवधान**)...आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। ....(**व्यवधान**)....

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये।.....(**व्यवधान**).....

श्रीमती सुषमा स्वराज: आज यह बात सामने आई कि एक व्यक्ति भारत का अभियुक्त है। जांच एजेंसियों ने उसके लिए इंटरपोल को रेड कार्नर नोटिस दिया है और वह व्यक्ति अर्जेंटीना में किसकी जमानत पर छूटता है, इटली का राजदूत अपनी जेब से जमानत देता है।...(**व्यवधान**)... यह विरोधाभास नहीं, तो और क्या?..(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: उपसभापति महोदय,...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये। ....(**व्यवधान**).....आप क्या.....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुषमा स्वराज: यह विरोधाभास नहीं, तो क्या है? ....(**व्यवधान**).....तीसरे, इसी पैराग्राफ में हमको राष्ट्रपति कहते हैं - आपका यह दायित्व हो जाता है कि आप हमारे लोकतंत्र की महान संस्थाओं के मार्फत यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के लोगों को बेहतर प्रशासन मिले। इस वर्ष संसद् की कार्यवाही के सार्थक संचालन के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं।

उपसभापति जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस सरकार का लोकतंत्र की संस्थाओं में विश्वास है? तीन-तीन दिन यह संसद् नहीं चल पाई, हम केवल एक चीज चाह रहे थे कि प्रधान मंत्री जी या विदेश मंत्री जी आकर के अपनी बात कहें। प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी अपने कक्ष में बैठे रहे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री को भेज दिया। उपसभापति महोदय, अगर हमारे चेयरमैन साहब पहल नहीं करते, तो शायद संसद की कार्यवाही चल नहीं पाती। ...(**व्यवधान**)... यह तो प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने उन्हें कक्ष में बुला लिया, बीच-बचाव का रास्ता निकाला और संसद् की कार्यवाही चल पड़ी। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि लोकतंत्र में कुछ पार्लियामेंट्री प्रोपराइटीज भी होती हैं। उन पार्लियामेंट्री प्रोपराइटीज का यह तकाजा है कि जब रेल बजट पर चर्चा हो रही हो, तो रेल मंत्री उपस्थित हों, जब बजट पर चर्चा हो रही हो, तो वित्त मंत्री जी उपस्थित हों, उसी पार्लियामेंट्री प्रोपराइटीज का तकाजा है कि जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो, तो प्रस्तावक और अनुमोदक उपस्थित हों।

मैं परसों से देख रही हूं। प्रस्तावक और अनुमोदक पर तो प्रधान मंत्री स्वयं आकर बैठे, लेकिन कल नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे थे, तब भी नदारद और आज भी नदारद। जो सरकार स्वयं लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकती, जो सरकार संसदीय गरिमाओं का पालन नहीं कर सकती, वह हमें लोकतांत्रिक दायित्व सिखाती है। यह विरोधाभास नहीं तो और क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि यह राष्ट्रपति अभिभाषण विरोधाभासों का पुलिंदा है और मैं एक-एक बात को अभिभाषण से उद्धत करके बताऊंगी। मैंने एक-एक बात अभिभाषण के अंश से उद्धत की है, एक भी बात अलग से नहीं कही और अपने उस आरोप को पुष्ट किया है कि इस अभिभाषण में कथनी और करनी का विरोधाभास भी है और सोच की दुविधा भी । इसलिए इस सरकार को मुखातिब करके मैं केवल चार पंक्तियां कहना चाहती हूं। आजमी साहब बैठे नहीं हैं, वरना वे इसको ऐप्रिशिएट कर सकते थे।

श्री उपसभापति: प्रभा ठाकुर जी बैठी हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, वे ऐप्रिशिएट करेंगे। प्रभा जी भी बैठी हैं। प्रभा जी, आपकी सरकार को मुखातिब करके चार पंक्तियां पेश करती हूं:

नजर, उनकी, जुबां उनकी,

ताज्जुब है कि इस पर भी,

नजर कुछ और कहती है,

जुबां कुछ और कहती है।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हुए भाषण के कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, अभिभाषण के पैरा-तीन में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में आठ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है और आगे 9 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह एक सराहनीय कार्य है, मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इस वृद्धि का कितना अंश गरीबों के पास और कितना अमीरों के पास पहुंचता है? इसका विश्लेषण करने की जरूरत है और इस पर अगर चिंतन किया जाए तो आज इस देश की आबादी सौ करोड़ से ज्यादा है जिसमें से केवल एक प्रतिशत से कम लोगों के पास देश की आर्थिक संपदा का 80 प्रतिशत भाग है और 99 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के पास 20 प्रतिशत से कम आर्थिक सम्पदा है। यह एक चिंतन और मनन का विषय है। इसका परिणाम आजादी के बाद से हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि अमीर अमीर

3.00 P.M.

होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है तथा अमीर-गरीब की खाई बढ़ती चली जा रही है। चंद लोग खा-खा करके मरने की ओर अग्रसर हैं तो ज्यादा लोग खाने के बगैर मरने को मजबूर हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि समय रहते इस विषमता पर अंकुश लगाने की जरूरत है नहीं तो इसका बुरा परिणाम देश के सामने आने वाला है क्योंकि 'मरता क्या नहीं करता' को हम रोक नहीं पाएंगे इसलिए इस आर्थिक विषमता को कम करने के लिए कोई कारगर उपाय करने की आवश्यकता है और इस पर सरकार को बल देने की जरूरत है। आर्थिक विकास ही अपने आपमें उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यह एक माध्यम है, जिसके द्वारा हमें अधिक रोजगार पैदा करने, देश की आय को सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में अधिक समानता से बांटने तथा सर्वाधिक निर्धनों को, गरीबी, अज्ञानता और रोग के दुखों से निजात दिलाने की शीघ्र आवश्यकता है। अभिभाषण के पैरा-चार के अंतिम भाग में कहा गया है कि ''मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह हमारी दृढ प्रतिबद्धता है।''

किंतु सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम वास्तव में नहीं उठाया गया है, जिससे मुद्रा-स्फीति का कुप्रभाव गरीबों पर पड़ने से रोका जा सके, इसलिए देश के कोने-कोने से गरीबी और भूखमरी के कारण आज देश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उसे रोकने में सरकार विफल है और मेरी राय में कोई कारगर उपाय करने की जरूरत है।

महोदय, अभिभाषण के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की काफी सराहना करते हुए कहा गया है कि देश के दो सौ जिलों में चल रही इस स्कीम से 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है। जब इस देश में लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी के शिकार हों और उनमें से केवल 1.4 करोड़ परिवारों को केवल सौ दिन की रोजगार गारंटी योजना हो, मेरी राय में यह काफी नहीं है और यह ऊंट के मुंह में जीरा दिखाने को चरितार्थ करता है। अत: इस स्कीम का और विस्तार करने की आवश्यकता है, इस पर बल देने की जरूरत है।

महोदय, अभिभाषण के पैरा 12 में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न आहार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटित निधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह एक सराहनीय काम है, लेकिन इसके उपरांत भी देश के सभी विद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं है। राजकीय विद्यालयों से कहीं ज्यादा प्राइवेट, सरकारी वित्त-विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय इस देश में शिक्षा में योगदान कर रहे हैं, किंतु मध्याह्न आहार कार्यक्रम से वंचित रहते हैं। मेरी राय में इस योजना के क्रियान्वयन में सभी विद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।

उपसभापति महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बालक और बालिकाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, किंतु यदि सही मायने में सर्वेक्षण कराया जाए, तो इन्हीं वर्गों में ज्यादातर अशिक्षा, निरक्षरता और अज्ञानता है, जिसके कारण यही वर्ग जागरूकता की कमी के कारण शोषण का शिकार होता है। अत: सरकार को विशेष ध्यान देकर इन्हें जागरुक करके शोषण से उबारने की जरूरत है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि में निवेश बढ़ाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके किसानों की आय बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे, मेरी राय में खेतिहर किसानों के प्रति सरकार का उदार रुख जरूर है, किंतु अभिभाषण में कहीं भी चर्चा भूमिहीन किसानों की नहीं की गई हैं जो किसान पूरे परिवार सहित कृषि का कार्य करते हैं, उनके पास सिर छिपाने के लिए नीली छतरी के अलावा एक इंच ज़मीन भी नहीं रहती है। आज अगर इस देश में ऐसे किसानों की आबादी देखा जाए, तो जो भी कृषि में लगी हुई आबादी है, उसमें 25 से 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्हें सामंती जुल्म और ज्यादती का शिकार होना पड़ता है और गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है और पशुओं से भी खराब जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है, अत: सरकार को ऐसे भूमिहीन किसानों के विषय में चिंतन करने की जरूरत है। मेरी राय में आज देश में काफी कृषि योग्य ज़मीन पड़ी हुई है, भूमि-सुधार करके ऐसी ज़मीनों को भूमिहीन किसानों में वितरित करके उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है। इससे देश की खाद्यान्न समस्या को भी हल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस दौरान हमारी नेता, बहन कुमारी मायावती जी ने भूमिहीन कृषकों को तीन-तीन एकड़ का पट्टा देकर, उन पर कब्ज़ा दिलाकर लगभग दस लाख परिवारों को रोज़गार देने का काम किया। मेरी राय में सरकार द्वारा ऐसे ही सभी प्रदेशों में भूमि-सूधार करके किसानों को, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराकर, उनको रोज़गार भी मुहैया कराया जा सकता है और देश के खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है, जिससे कि उत्पादन बढ़ जाने से आज किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वे अपने आप रुक जाएंगी। अभिभाषण के पैरा-24 मेरी सरकार सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, स्वैच्छिक और आर्थिक सशक्तिकरण को अधिक महत्व देती है। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इस देश का सामाजिक ढांचा ही गलत है। जब सामाजिक ढांचा ही गलत है तो सामाजिक न्याय की आशा करना, न्यायसंगत नहीं है, बल्कि एक धोखे समान है। इस देश को जो सामाजिक ढांचा है, वह जातिवाद, वर्गवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद पर सीढ़ीनुमा खड़ा है। इसका परिणाम सामाजिक विषमता का भयावह रूप, आज देश के सामने खड़ा है। इसलिए अब देश को सामाजिक न्याय नहीं

बल्कि सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, जिसके माध्यम से पैदा हुए संतों और महापुरूषों के सपनों को साकार करते हुए, समतामूलक समाज बनाया जा सके। इस भारत देश में 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, उन्होंने कहा था कि इंसानों की जातियां नहीं होती हैं । चौदहवीं शताब्दी में हमारे देश में बहुत सारे संत पैदा हुए थे। उनमें प्रमुख संत कबीर दास, संत रविदास, संत दादू, संत नानक थे और मोहम्मद साहब थे। इन सभी संतों ने कहा था कि इंसानों की जातियां नहीं होती हैं, सब इंसान बराबर होते हैं। हमारे देश में 18वीं शताब्दी में बहुत से महापुरूष पैदा हुए, जिनमें प्रमुख थे, महात्मा ज्योति बा फूले, पैरिया रामास्वामी नायकर, नारायणा गुरू, छत्रपति साहू ही महाराज और बाबा साहेब डा॰ अम्बेडकर, इन सभी लोगों ने कहा था कि इंसानों की जातियां नहीं होती हैं। बाबा साहेब डा॰ अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा था कि जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराष्ट्र की कल्पना करना भी निरर्थक है। उन्हीं संतों की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज मान्यवर कांशी राम जी, जो कि हमारे बीच में नहीं हैं एवं बहन कुमारी मायावती जी मंच से नारा लगाती हैं, 'जाति तोड़ो, समाज जोड़ो'। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो जाति तोड़कर भ्रमता मूलक समाज बनाने का अभियान चलाने की बात करता है, उसी को मीडिया के लोग जातिवादी की संज्ञा देते हैं और जिन्होंने जातियां बनाई है, उन्हें समाजवादी की संज्ञा देते हैं। मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों के बैकलॉग को भरने में काफी प्रगति की है और शेष खाली पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है। मेरी राय में यह एक छलावामात्र है। आजादी के बाद से आज तक प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक बैकलॉग देश या प्रदेश में कहीं भी पूरा नहीं हुआ है। पहले कहा गया कि able candidates not available, योग्य candidates नहीं हैं, इसलिए आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। जब हजारों सालों से पढ़ने-लिखने के लिए दरवाजे बंद किए थे, तो कहां से able candidates पैदा होंगे? मैं संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डा॰ अम्बेडकर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे समाज के लिए पढ़ने-लिखने के दरवाजे खोले और 1935 में एक एक्ट बना, तब सारे शूद्र समाज के लोगों को और स्त्री समाज को पढ़ने-लिखने का अवसर मिला। आज उसका यह परिणाम है कि सभी able candidates हैं, लेकिन जो सत्ता के पोषक लोग हैं और जिनकी मानसिकता खराब है, कोई न कोई lacuna लगाकर, आज भी आरक्षण पूरा नहीं करना चाहते हैं। आज एक दूसरा lacuna पैदा हो गया है कि able but not suitable for the post. Able तो हैं, योग्य तो हैं, लेकिन जिस पद के लिए योग्य होना चाहते हैं, उस पद के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज भी कोटा या आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। आज हर गली और मोहल्ले में able भी हैं और suitable भी है, लेकिन आज न नौकरी able को मिल रही है और न suitable को मिल रही है? आज नौकरी ट्रेसेबल हो गई है। ट्रेस किया जा रहा है। इसके लिए दो तरीके हैं, सबसे बड़ा रुपया

या सबसे बड़ा भैया। इन दोनों के अभाव में यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग कहीं भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहिन कुमारी मायावती, देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं तो उत्तर प्रदेश में भी बैकलॉग का विशेष अभियान चलाया गया था। लगभग पच्चीस हजार नौकरिया देकर विशेष अभियान के दौरान बैकलॉग भरने का काम किया था। आज देश में महिलाएं अनेक उत्पीड़न की शिकार हैं। देश में महिलाएं अनेक उत्पीड़न की शिकार हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विचार ही नहीं बल्कि निवारण करने की जरूरत है। अत: इस प्रत्याशा में कि सरकार देश में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों, महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ ही साथ इस देश में काफी अरसे से सामाजिक विषमता के शिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों, को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ravula Chandra Sekar Reddy. You have 16 minutes. *(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: You speak only on the subject. *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has got 16 minutes. Don't disturb him.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, if he goes on disturbing, I will take 30 minutes.

Sir, the hon. President's Address to the Joint Session of the Parliament is most disappointing. I am unable to support the Motion moved by Dr. Karan Singh and seconded by Shri Raashid Alvi. Unfortunately, both of them are not here. I oppose the Motion. If we consider the Address of the hon. President to the Joint Session of the Parliament as a policy document, unfortunately, he read out the earlier programmes of the Government. There is nothing new in this Address. He has just given a balance-sheet of the programmes which are already in the public domain and nothing new. He has not addressed the rising prices. Unfortunately, in our country neither the purchaser nor the consumer is happy with this. The farmers say

that they are unable to get remunerative prices; whereas the consumers say that the prices of essential commodities are skyrocketing. *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, the hon. Member is speaking.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: The *aam admi* in our country is the worst sufferer and the biggest beneficiary is the middleman. The Government is also helping the middleman in usurping the public money. The Address of the hon. President is disappointing in this respect.

As far as the disputes between the States are concerned-when I was sitting in the Central hall, there was a quarrel between Tamil Nadu and Karnataka Members in the Lok Sabha on sharing the Cauvery water-the Government of India has just forgotten that and it has left it to the fate of the State. Let them quarrel. What will happen? That is the attitude. They want to survive in the Government without resolving the problems which are existing for a long time among the States. We have a problem. I am coming from Andhra Pradesh. We have a problem with Karnataka. We have problem with Maharashtra. The Mahrashtra Government was allowed to construct many irrigation projects which would definitely cause problems to the farmers in my State

SHRI RUDRA NARAYAN PANY(Orissa): You have a small problem with Orissa also.

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: When I am speaking about water, it is *paan*. Naturally, he is interested in it. The problems with the neighbouring State, as far as my own State is concerned, are still there. The Government of India is not taking any steps to resolve the problems. They have definitely forgotten about the interlinking of the rivers. The good work done by Shri Suresh Prabhu has gone watse. Nothing is happening on the issue of interlinking of rivers. The biggests problem in my State Andhra Pradesh and in the neighbouring States Maharashtra and Karnataka is, the farmers are committing suicide. We have been raising the issue of suicide by farmers in almost every Session. I have the

figures of my own State Andhra Pradesh. During the past three years, 3,904 farmers have committed suicide. I am willing to share the information with you about the name of the farmer, date and place where he committed suicide. Sir, 3,904 farmers have committed suicide during the last three years in Andhra Pradesh. *(Interruptions)*... You have not heard me. I said that farmers are committing suicides in Mahrashtra and Karnataka also. You are busy in interacting with your colleagues. You are not paying attention to me. This is the problem in Andhra Pradesh also. They are neglecting this issue. The State Government has conveniently forgotten to resolve the problem of farmers. They are allowing the farmers to die. Starvation deaths and suicide by weavers in Andhra Pradesh since last three years. the number is 486. I would like to mention another issue wherein the farmers have been sent to jail. The case is the State Bank of India files suits against farmers in my own district Mahaboobnagar. Two farmers were given Rs. 5,000/- and Rs. 7,000/- each. They were sent to a civil prision. Having filed a civil suit, EP was filed and the subsistence allowance was deposited by the State Bank of India and farmers were sent to jail. What will happen to those farmers and their families? When they come back to the village, they feel ashamed of being in the jail. How would they live in the same village? This is the attitude of the Government. What is the policy of the Government so far as small and marginal farmers are concerned who are owing some money to the banks? If this is the state of affairs, no farmer will survive in the country. The Government has not addressed this issue. The hon. Prime Minister has announced a package by giving some interest waiver and other things. The relief package announced by the hon. Prime Minister is in no way helpful to the farmers of Andhra Pradesh. Since we have severe drought in the State for four consecutive years, *(Interruptions)*. What is the benefit? I will read it out. Your own Minister went on record saying this. This is for the information of the hon. Minister who happens to be from my own State, who got elected from Andhra Pradesh and hails from Karnataka. There are 16,45,000 farmers in 16 districts of Andhra Pradesh, who have availed a total loan of Rs. 917 crores and an amount of Rs. 1733.45 crores is the interest accrued on

the principal amount of Rs. 917 crores. The package is in no way helpful to the farmers, as the package is applicable to the loan from the period of 1st April to 30th June 2006. But these loans were rescheduled prior to April 2004. What will happen to those farmers? This package is in no way helpful to them. And the State Government says that they were not consulted. There is an error on the part of the officials. Due to non-consultation and due to the mistake committed by the officials, the farmers are suffering. They are unable to take the benefit of Prime Minister's package. Sir, there are a lot of distress sales in the State. In spite of producing some grain, the farmers are unable to sell it in the market. The debt relief which was announced by the Government of India is in no way helpful to them.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

This is another big problem in the State. The hon. President has simply mentioned about suicides in one sentence in his Address. This statement which has been prepared by the Cabinet has forgotten to address the real problem. The real problem is with regard to the credit facility, with regard to marketing, with regard to storage. This issue has not been addressed by the President's Address. And there is the Report of Dr. Swaminathan. What happened to that Report? Having appointed Committees, there is nobody to go into the details of those Committees. Even, in my State, there are Committees. I request the Government to constitute another Committee to go into the Reports of those Committees. I do not know what is happening in the Central Government; nobody is bothered to look into the grievances of the people. The hon. President has highlighted certain programmes like the Welfare Programmes, Mid-day Meal Programme, etc. The Mid-day Meal Programme was there earlier too. In my State, in a district called Adilabad, — the hon. Minister often visits that districts — in one of the schools, — this is just one example; there are hundreds of cases like this — one boy called Shravan Kumar, while eating a boiled egg, died in the school for want of water. There was no water there. He was eating a boiled egg; he cried for help. He was rushed to a nearby house, but it was closed. The boy died in the school. Having provided mid-day meals, it is not the responsibility of the Government to see whether drinking water is provided or not? What sort of review is taking place? When there is no review of your Mid-day Meal Programme, such things will happen. I am

not saying this for the sake of criticism. It is a fact. It has happened in Kotipalli Mandal, Mallampet village of the Adilabad district. Let the officials verify the fact. There are hundreds of schools where no safe drinking water has been provided, and the mid-day meal programme is on. What will happen to the students? Having highlighted the Mid-day Meal Programme in the Address of the hon. President, is it not the responsibility of both the Central and the State Government to ensure that adequate water supply is made to the schools. I am afraid if the Government of Andhra Pradesh would take my speech seriously. Instead of providing drinking water, they might withdraw the boiled egg from the meals. I never wanted that. The Government should ensure safe drinking water in the schools, instead of withdrawing the boiled egg scheme.

Then, Sir, another scheme highlighted by the hon. President is the National Rural Employment Guarantee Scheme. I would like to remind the House that having launched the programme in the Anantapur district of Andhra Pradesh by the hon. Prime Minister, in the same village where the programme was launched, there is lot of corruption taking place. Social audit was conducted. Now, Sir, there are hundreds of news reports with me. I cannot read them because of paucity of time. But the programme miserably failed in that district. There are instances where one individual ...*(Interruptions)*

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश): आप authentic figure बताइए, यह आप अखबार के जरिए बता रहे हैं।

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी: आपकी आदत हो गयी है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं। ...(व्यवधान)... I read a lot of newspapers — *Vaartha, Eenaadu, Jyothi, Andhra Bhoomi,* etc. Sir, in one village, one individual has drawn Rs. 70,000. If they are interested, I can make copies and send it to them. But I would request them to prevail over the State Government and see to it that things are rectified. In one constituency, which a Minister is representing, about Rs. 60 crores has been misused. One individual has drawn Rs. 70,000 from the Post Office. Is it practically possible? But it is possible in Andhra Pradesh. I request and demand the Government to have an evaluation of the whole programme. The people, who had gone for the social audit, were not allowed in villages; they were locked in a room. And you want that we should not highlight

these issues! What other mechanism do we have except reading the newspapers or getting information from other electronic media! After all we cannot go to each and every village. That is the official report I am quoting from official records. It is the duty of the Government to rectify the mistakes and see to it that the money, for whom it is intended, reaches the common man, reaches the labourers and not the middlemen. As I have earlier stated, these job cards have become ATM cards for the ruling party people in the villages. I am prepared to prove this. These job cards have literally become ATM cards that they are able to withdraw money as and when they require. And you claim that this programme is successful ! Sir, I would like to cite the reply to Starred Question No. 310 on 13.12.2006 given by the hon. Minister in this House. Sir, in Andhra Pradesh, about 43 lakh job-cards were issued. But the work has been provided only to fifty per cent people. And you claim that this has been successful. Earlier, we had a Power-Point presentation wherein they claimed that in three districts — Anantapur, Ranga Reddy and Adilabad — the programme has been a grand success; and it was also shown to the hon. Prime Minister. I had said that that should be replicated in all the districts. In the districts which I have cited, my party has won in the recent elections. This is the state of affairs in my own State as far as this Rural Employment Guarantee Programme is concerned. People are literally looting public money, Sir. The people who are closed to the ruling party are literally looting public money. I am prepared to prove this. *(Interruptions)* Sir, the hon. President has highlighted certain programmes. I wanted to give the details. Please do some introspection and have an evaluation. Then only will you come to know the ground reality. Don't fly in the air; look down at the earth too; otherwise, you will be losing your power. Sir, I am aware that the Congress Party is losing fast in the country. They have lost all the big States recently — Punjab, Uttaranchal; they are left with Andhra Pradesh. *(Interruptions)* Recently, Karnataka you have lost.

श्री नंदी येल्लैया: सर, इन्होंने बोला कि ...(व्यवधान)...

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी: कर्णाटक भी चला गया ...(व्यवधान)...

श्री बी॰ के॰ हरिप्रसाद (कर्णाटक): तेलुगू देशम आंध्र प्रदेश से बाहर चला गया ...(व्यवधान)... अब आंध्र में ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Ravulaji, you address the Chair. Don't be detracted by them. Please address the Chair. *(Interruptions)* Please, please, please.

SHRI V. NARAYANASAMY: When you talk about Andhra Pradesh, I can talk about Orissa also.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, earlier, we used to call certain parties as National Parties. Now, they have become notional parties in certain States. Still, you want to fight that losing battle! I am talking about the ground reality. If you have the guts to go to those villages, I am prepared to give you the names of the villages.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): All right. Now, please come to the point. Do not fall into their trap.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, take the case of SEZs. They are Special Exploitation Zones. They are not Special Economic Zones. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Address the Chair. *(Interruptions)* No, no, Hariprasad. Your chance is also coming. *(Interruptions)* No, please.

श्री रूद्रनारायण पाणि: उस समय बढ़िया था और अब कम खराब है ...(व्यवधान)...

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी: पाणि जी का समाधान सुनिए। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is getting over. That is their trap. Do not fall into their trap.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, you have to deduct this time of interruption and add it to. ...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Address the Chair. Don't look at them. Address the Chair.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, these so-called Special Exploitation Zones are helpful neither to the farmers nor to the people living in the vicinity of that area. All the small employees are also being brought from outside. Everything is mechanised. No local person is getting any job in these so-called Special Economic Zones. What is happening? Adequate compensation is not being given. The

Supreme Court gave a direction that when a farmer is displaced, he should be adequately compensated. What is meant by adequate compensation? They are paying pittance, Rs. 35,000 or Rs. 50,000 per acre. Your Act says that the Government will not acquire agricultural land, as far as possible. Now, people at the lower levels are exploiting that particular sentence of the Act. The State Governments have actually become — I dare say — real estate brokers to certain industrial people. The State Governments are acting as land brokers to the industry people — taking the land of poor farmers, displacing them, not adequately compensating them and forcing them to beg in the streets. When this is the state of affairs, you want to call them the Special Economic Zones! Sir, this is going to dismantle the entire agricultural system in our country. We have already heard the hon. Agriculture Minister for whom I have got the tremendous respect. But, unfortunately, our country has now imported 55 lakh metric tons of wheat. Where are we going? Once we were having surplus foodgrains, but now we have shortage of foodgrains. They say that they want to create buffer-stocks in Southern India's Tuticorin Port. But, now you have imported 55 lakh metric tons of wheat. Sir, by quoting all these things, I am coming to a conclusion that there is a mismanagement at the national level. Nobody is responsible for his activities. Nobody is taking care. There is no introspection; there is no review; there is no evaluation of the programmes which are already launched.

Sir, as far as inter-State relations are concerned, and misuse of Constitution is concerned, take the case of UP. Sir, the Ruling Party was asked to do the floor test 22 times. Time and again, the hon. Governor of the State will be willing to send a report to the Central Government to dismiss the State Government. What is this? Is it democracy? Wherever there is a non-Congress Government, from day one, there will be a sword hanging on that Government. Never in the history that a Congress Government was dislodged by using article 356. This article is there in the Constitution only for the non-Congress Governments. Sir, this is gross misuse of constitutional powers. So, it should be taken care of. The hon. President, being the constitutional head, is unable to address this particular aspect.

Sir, now I would like to say something about the partisan attitude of the Central Government. Sir, as I said, when we were crying for recognition

of Telugu as a Classical language, all the Members of Parliament from Andhra Pradesh belonging to both the Houses of Parliament met the hon. Minister and the hon. Prime Minister in this respect. The State Assembly of Andhra Pradesh has passed a resolution in this regard. But, nothing happened. I have no grievance when Tamil is given the status of a classical language. But, what happened to Telugu? Why is this partisan attitude being taken? Telugu is a more than 1000 years old language. It is called the Italian of the East. I think, it will impress you. It is called the Italian of the East. ...*(Interruptions)*... I am willing to add Kannada. What happened to our representation? What happened to the unanimous resolution of the Andhra Assembly?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COMMERCE, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JAIRAM RAMESH): Malayalam also.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Any language which is having the required eligibility condition or the requisite qualification or the required condition, that should be added. But, what happened to the Resolution of the Andhra Legislative Assembly? Sir, there is a clear partisan attitude. Sir, I would like to remind that by virtue of 29 Lok Sabha Members from Andhra Pradesh for the Congress Party they are surviving in the Government at the Centre. But, you have conveniently ignored the claims of the State of Andhra Pradesh. Sir, opening an IIT at Basra is another big problem. The Andhra Pradesh Assembly has passed three resolutions for creation of an IIT at Basra. But, now there is a problem as there is a dispute between Rangareddy and Adilabad districts and Medak and Adilabad districts. Sir, this problem has been created by the Central Government. What is this partisan attitude? Why are you creating problems amongst districts?

SHRI JAIRAM RAMESH: An IIT is being set up in Andhra Pradesh.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Thrice we have passed resolutions for creation of an IIT in Andhra Pradesh. I was in the Andhra Assembly at that time. Sir, three unanimous resolutions have been passed, but the Government of India is not bothered.

Sir, the hon. President has also referred about the Railways. Sir, there is a phrase about Railways. It means 'right way or wrong way, there is another way, railway'. Unfortunately, Laluji's train is not stopping

in Andhra Pradesh. It is in no way helping the Andhra people. Sir, in the last Budget Session, all the Members of Parliament from Andhra Pradesh went to the hon. Railway Minister and the hon. Prime Minister to give a representation about the grievances of Andhra, as far as the Railway programmes are concerned. We did not get anything out of that. Sir, we definitely oppose this partisan attitude of the Central Government.

Finally, Sir, I know you are looking at me, and I am aware of the time constraint. Sir, finally, I would like to say that as far as women are concerned, tomorrow, on the 8th March is the World Women's Day. The Women Reservation Bill is pending with the Government. All the political parties were called in the chamber of the hon. Home Minister for consultation on the Women Reservation Bill. So many consultations are taking place and nothing is coming out of them. Why are you misleading the nation? If you are really having any intention, come out with it. Or if you are not willing to do it, tell it openly to the nation through this Parliament. Sir, instead of keeping them in dark, instead of denying them their legitimate claim of having reservation in the legislative bodies, give them this right. With this demand, as I said earlier, while thanking the hon. President for coming to the Parliament House, I am opposing the Address made to this House. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (Maharashtra): Hon. Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak in this august House today on the Motion of Thanks to the Presidential Speech. The President in his speech mentioned that investment in the well being of the children is an investment in the future of our country. I would like to specifically speak about the problems of our children and their future in our country. The President stated in his speech that child protection is high on the Government's agenda. Sir, I would like to take this opportunity and highlight this issue of the Nithari episode, which has highlighted the lack of security of all our children. This episode has exposed India's carelessness in protecting our children. The brutal killing, murdering, kidnapping, and raping in the Nithari episode is of serious concern to us. Sir, I think time has come when we all together have to stand up against these atrocities against our children and condemn this act. Children go missing daily in India and the authorities are not taking this seriously. So, I appeal to the Government that we take some stringent action against this and ensure

that such things do not occur. The Central Panel and the various NGOs have suggested a few things about the widening the scope of investigation because they feel the possibilities of organ trade and sexual exploitation as well. Sir, there are certain measures that can be recommended to avoid such things to happen again. I am happy to say that the Home Ministry has asked the CBI to conduct an inquiry, which is still in progress. But we are all awaiting to see the report eagerly. The Government also is considering a legislation regarding child abuse, which includes sexual exploitation, economic exploitation, domestic violence, trafficking for prostitution and corporal punishment in schools. Sir, a time has come when you have to consider the protection of our children. Invariably it is pleaded, with my little knowledge about this House, that all these issues or protection or law and order are State Subjects. Sir, when it come to the security of our children I think we need to have a Central legislation in place where there has to be a good coordination between the Centre and the State Governments to make sure that our children have a secure place to go to if they are missing or lost. It could be anything, Sir. And there has to be a legislation to be made which is very strong, and it should be implemented exclusively for our children. We have recommended through the help of our NGOs, that there should be special police posts where there can be a special guidance for all these issues. And all there has to be a good interaction among all the districts in the States, which is probably monitored with the help of the Home Ministry at the Centre, and it should not be considered by the States as any kind of interference. Further, Sir, there should be special courts to be set up to dispose of all these cases where all these people should be punished and this should above caste, creed and religion. Sir, this law should be applicable to every citizen of our country and there should be no social or political interference in this legislation. Sir, according to the National Human Rights Commission, about 45,000 children are missing in our country every year, out of which, according to the numbers that are available, 11,000 are never even found. Sir, it is a serious and alarming situation. I appeal to the Government that the protection of our children and the missing children should be taken on a war-footing. The other issue, which is connected to this, is abolition of child labour. This august House has made a lot of legislation for child labour but as we are all aware the ground reality is far different. Children today in large

numbers are still working at various levels be it home or carpet making. And this number I do not want to state, it happens all over India. There is no particular state suffering from this. I think, without a rehabilitation programme I don't see these children getting out of this vicious circle. A lot of State Governments are taking initiatives to bring these children out. But unless we give them good protection as well as good quality education and security these children will go back into the whole circle again and the root cause of this entire problem is poverty which is really what we need to address and try and rehabilitate all our children at all levels. I am proud to say that the Maharashtra Government and the Home Ministry have taken major steps to improve the situation of the children in our State. The Home Minister has taken personal interest and has informed all the Commissioners in all districts to prepare dossiers to have a regular follow up and he himself has taken interest in it and has regular meetings and is updated. So, I appeal to all the other States and like the hon. Home Minister mentioned in the morning, if at all the Maharashtra model works, I think, we will all be happy to use it and implement in other States and have a good interactive situation in the interest of protection of our children. The other issue which is alarming our country is of malnutrition. The National Family Health Survey has given us numbers which are absolutely alarming. As many as 45.9 per cent children are underweight today, 38.4 per cent are stunted and 19.1 per cent are wasted. The numbers of anaemia are even more alarming. The infant mortality rate instead of going down is going up. Sir, in this regard, the Supreme Court intervention has really helped. The Supreme Court on July 19, 2006 appointed a two-Member Committee to look into the serious lapses in the ICDS. Even the Planning Commission has taken serious cognisance of this issue and has passed some serious comments about this thing. The Planning Commission has mentioned that there is a clear gap between the intention and the actual implementation of this programme, which does not reflect upon us as policy makers, and the implementers of the same. I am happy to say that the Prime Minister's personal intervention has really helped in the ICDS programme approval of all. I think, he has written to all the Chief Ministers in all the States and because of that things have really started moving. I appreciate his effort and I am optimistic that because of his personal intervention we would be definitely getting some good results. The Draft Approach Paper of the Eleventh Survey has suggested

that the development of our children would be prioritised and there would be effective implementation of the ICDS programme. Sir, I really feel sorry to say this but so far there are only 7.4 lakh anganwadis in our country which are well short of the estimated 17 lakhs required for universal coverage. I appeal, on behalf of all of us who work for the children of this country, to the Finance Minister that I wish he would do something more. We appreciate what he has done for us in this Budget but definitely we need much more to be done for our children. Sir, the alarming issue for us women, is maternal mortality. One woman every seven minutes dies in our country due to pregnancy related complications. According to various reports of UNICEF, 30 per cent cases like this even go unreported. Sir, I am ashamed to say this but the statistics are alarming. Even our other neighbours such as Bangladesh and Sri Lanka are far ahead of us in this case. I appreciate the Government's effort. In the Rural Health Mission, there is a lot of money being given for all these programmes but somehow they are not reaching women in every village. There aren't any good hospitals and we are all aware of what the ground reality is. The medical facilities are not improving. In many places there are no doctors available at any time. So all these programmes are available and look glamorous on newspapers and all our reports. But the ground reality, as we are all aware, is far different. Even today, 65 per cent births take place at home without any assistance or trained staff. Today, India at present has an MMR at 301. That means out of one lakh births, 301 women die during pregnancy. If you have to achieve the millennium goal, the Millennium Development Goal or the MMR, we need to reach the number of 106. But, Sir, at the rate we are going, by 2015, we will just about reach the number of 240. I urge upon the Government that through the Rural Health Mission they need to focus more and reach every corner of our country and make our dream come true. I am very happy that the Ministry of Social Justice and Empowerment is taking all the initiatives to support women and children belonging to the SC/ST. There are a lot of policies made, but are not implemented. But, I am sure, with regular meetings, according to what the hon. Minister has mentioned in the past, these targets will be met which are lagging behind.

The other heartening effort which the Government is making is strengthening the office of the Chief Commissioner of differently-abled. Even this year, the hon. Railway Minister and the hon. Finance Minister

have made special provisions for differently-abled people and I express my gratitude and say a big thank you to them. At the same time, I urge the Government that it is important to simplify the process of assessment of disabilities and issue disability certificate to all these people and make the process much easier, because it is extremely difficult to get as there is a lot of corruption to get a disability certificate in our country. Therefore, I appeal to the Government that we have to make sure that all these great schemes, which we are making, are implemented for the welfare of our people.

Sir, being a woman, a girl-child and an only child this point is really close to my heart and appreciate the Government's efforts for Adopt the Girl Programme to check the alarming rise in the female foeticide in our country. The Ministry of Women and Child Development has started a welcome measure about the Cradle Scheme where anybody who has a daughter and does not want her can leave her and the Government will look after her. I appreciate this effort. But, there are other issues connected to the girl-child. The parents are still selling their daughters. The other issue which is really harming our country is child marriage. This august House enacted umpteen legislations on child marriage. But even today, in various parts of the country, even the educated cities, I am really sorry to say, the child marriage still exists and is in huge numbers. I think we all need to address this issue and, probably, make more serious legislation to stop these atrocities against young women, because even they deserve a good quality life, good quality education and they would also want to have good future and work. The root cause of all these problems, as I mentioned earlier, is poverty. I think, we all need to help and remove poverty from our country and try to uplift the people living below the poverty line. These issues continue to haunt us unless we address the issue of poverty. And, as Legislators, I think, we have failed the people of our country.

Sir, the hon. President has stated in his Address earlier that highest emphasis will be given to education. I appreciate and thank the UPA Government for increase in allocation that it has given for education. We are all aware that India is an ancient country. But, today, 40 per cent of our population of more than 1 billion is under the age of 20 years. This is a huge pool of youthful manpower which can lead India to its destiny. The fabulous programmes which are implemented like

the Sarva Shiksha Abhiyan and Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas have helped every child in our country to get good education, especially girls from the SC/ST and minorities. I don't want to sound like a cynic. There are a lot of aberrations in the implementation of these programmes. I myself have a little experience, because I work in the rural areas and run a few schools. There are a lot of challenges that are put ahead in education. At the same time, as a new entrant to this august House, I would like to share my perceptions of the diverse challenges confronting the youth of today. Competition is enormous due to population. The demand for quality education has become a big issue, because everybody realized that unless you get good education, you cannot get employment. The number of dropouts in schools is alarming; illiteracy. rate is still 65 per cent which implies that 35-crore Indians still illiterate. Reading skills, according to a survey conducted are still very low. If you visit many schools in the rural areas, children cannot even read, right or comprehend many subjects. The problem is paucity of resources leading to abysmally poor infrastructure. Unionism is rampant and accountability is extremely low. The external environment of terrorism, casteism, corruption, patronage and red tape add to youth frustration in our country.

The higher education sector also suffers with similar issues. Only 8 per cent of our population between the age group of 18 and 23 has access to higher education. Sir, 60 per cent of our colleges are located in urban areas, while only 40 per cent are in rural areas. Besides this, there is even a divide among the States. The children in Southern States have much more access to Secondary Education, while the Northern States and the North Eastern States suffer. There is a need to open many more colleges and institutes in the un-served areas. Due to inadequate financial resources, States are unable to set up new colleges. I appeal to the Central Government to find out some route by which we can have more access to education; not just Elementary Education, but even concentrate on Higher Secondary and Higher Technical Education. Maybe, we can even encourage private sector people to come in to help us achieve this goal.

By and large, the Higher Education in our country is very rigid. The content and the syllabus are outdated. I think time has come that we need to get some urgent reforms which will enable the domestic sector to compete effectively in a competitive environment. There is the cafetaria

type credit system which is used worldwide. I think, we need to use that in our country, which will help every students. This is a facility to transfer credit from one university to the other university. This will help him get relevant courses, which will guarantee him a job. The UGC, AICTE, Medical Council and State Universities will have to play an extremely pro-active role in all these reforms.

While at the Elementary Education level, we see a great improvement in the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and minorities, there is a serious concern for providing Higher Education for all these classes, especially, among the girls. The Maharashtra Government has started a special programme to help girls from financially difficult backgrounds. They have given them scholarships. On behalf of every girl child, I appeal to the Central Government to make available some benefits so that all of us get good quality education.

The financial health of the Education Sector is a matter of serious concern for all of us. Way back in 1964, as we are all aware, the Kothari Commission recommended increase in provision for education to at least 6.4 per cent of the GDP. Sir, we all know what the figures today are. And because of paucity of adequate financial resources we are facing a lot of problems of not having good infrastructure available to our students. There is a great shortage of buildings, classrooms, libraries, laboratories and we cannot even maintain the schools we have. This has even compelled many States to impose a ban on teachers' recruitment and we have seen that unless you guarantee them good quality job, the institutes are not giving good results. If we need to increase access to Higher Education from 8 per cent to 20 per cent, we will have to increase our spending by 150 per cent, which is probably, not possible. But, I think, the time has come that we should allow private sector, both foreign and domestic to supplement our efforts. This will improve efficiency and promote excellence. But the fee structure should be safeguarded to prevent commercialisation of education. As competition is being keener, Indian students have started going abroad to study. But, this is possible only for children who can afford it or even who have got good scholarships. I think the time has come that we try and give this education to all our children in our country at home.

Globalisation of the world's economy has fuelled competition. It is

compelling that the best institutions worldwide to continuously review their curriculum, make it inter-disciplinary and conduct research in collaboration with industry to stay afloat. Our institution still have a long way from achieving this. The General Agreement on Trade in Services is a challenge for which a great deal of preparation and clarity is required. A clearly articulated policy followed by a legislation, *inter-alia* instituting a regulatory regime that would ensure transparency and quality is necessary. Fortunately or unfortunately, Sir, the failure in the last round of talks has given us another chance to prepare for the next round. Some courageous decisions are necessary, both in the interest of quality and equity that Government should not shy away from.

Sir, we are 60 years into independence and time has come for us to ask ourselves what we have achieved. If I could quote, Sir, Pandit Jawahar Lal Nehru. "Aim of having a strong free and democratic India where every citizen has an equal place and full opportunity of growth and service, where present day inequalities in wealth and status have ceased to be, where our vital impulses are directed to creative and cooperative endeavour." Sir, have we been able to provide even the basic necessities to our people? Have we been able to provide even the basic necessities to our people, be it potable drinking water, electricity, sanitation, good quality education, eradication of poverty, and so many things? I myself feel that time has come when we need to review all these issues and at least provide our people with the bare minimum. Sir, Friedrich Max Muller once said: "If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow — in some sense the very paradise on earth I should point to India. If I were to ask under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions to some of them, which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India.

Sir, the greatest philosophers and our forefathers dreamt big for us and saw that India should be the best, if not one of the best. Everybody says "India is shining and India is everywhere." Now, time has come for all of us to make this dream into reality, not just economically but also socially. The future of our country is in our hands; let us not fail

4.00 P.M.

the citizens of this great land. I support the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Ms. Supriya for the maiden speech.

SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA (Nominated): Sir, I would like to thank the President for his Address, outlining the priorities and the achievements of Government. The President in his Address stated that his Government is building a new architecture of inclusive growth. Sir, this has only been possible because of the tremendous growth that India witnessed over the last few years. On the 60th year of our nation's independence, we have much to be proud about. We have made many strides, but, Sir, it is one thing to achieve the economic performance that we have and it is another thing to hold on to it and to use it as a launching pad for greater progress. As President Kalam himself said, by progress his Government cannot be exclusively taken up by the rising and shining India, but its programmes such as Bharat Nirman, National Rural Health Mission, Sarva Shiksha Abhiyaan, Mid-day Meal, National Rural Employment Guarantee Act and other such schemes that form the building blocks of this inclusive architecture. Sir, the whole debate about the SEZs versus industrialisation is being seen in the light of development versus rights. To my mind, it is not development versus rights, but development for greater rights that this sort of a scheme should actually ensure. Sir, we often talk about the demographic dividend which is going to take us to places. If we are to ensure that this demographic devidend does not turn into a demographic nightmare, then we have to ensure that the twin objectives of medical health care and education are easily accessible to our entire population. I would just like to dwell on these two issues which to my mind are extremely critical for the Government. I will first deal with health. With the public spending on health being almost lower than 1.3 per cent, it is abysmally low, vast swathes of our population remain outside of basic medical health care. The Government through the National Rural Health Mission has been seeking to address this in partnership with the States, Communities, Panchayats, by creating institutes that bring heath care to millions of its people. But the main issue, according to me, really, is of creating awareness of these programmes, of improving educational

facilities, and more importantly, ensuring women's welfare. The National Rural Health Mission takes a holistic approach to the way in which it defines health care. It seeks to identify the key ingredients or determinants of good health, be it nutrition, be it safe drinking water or promoting hygiene. Also, Sir, the plan of action of the National Rural Health Mission talks about increased public spending in the field of health. It talks about reducing regional imbalances, of trying to ensure greater infrastructure. of pooling resources, and of decentralising the district management of health schemes and improving community participation. The Government should ensure that all these criteria are met because, as of now, Sir, millions of our people do not have access to basic health care. What is extremely startling is that almost 22 per cent of our nation's diseased population suffers from malnutrition. For a country with its growing economic clout like India, Sir, this does not fit well at all. More importantly, almost 50 per cent of the 2.2 million annual child deaths are caused by malnutrition as well. This shows the growing importance of women and, more importantly, mothers in our nation's health care. And it is not just poverty and food insecurity, Sir, but its unsafe feeding habits, its lack of proper nutrition that leads to this. So, the irony is, Sir, that whereas 70 per cent of Indians live in rural India, almost 70 per cent of India's doctors reside in urban India. This dichotomy has to be addressed even if incentives have to be given. Therefore, Sir, also falling out from malnutrition is a subsequent low birth weight of infants in this country, and almost 60 per cent of women in India suffer from anaemia, which is also linked to low birth rate. So, Sir, health care really means drastically improving sanitation providing safe drinking water, promoting hygiene practice, directly or indirectly, all what Government should ensure, is covered under health care.

Sir, I will spend a little time on education now. The IITs and the IIMs in our country are world class. But they are just too few in number. There is a need for many, many more. But the primary and secondary education is what requires extensive and urgent attention. If India is to take advantage of its reputation as a knowledge economy, what we really need is a quantitative expansion and a qualitative improvement in our educational services. For the past 25 years or so, we have been spending less than three per cent of our GDP on education. This year, the Government has given a healthy increase, but even so, Sir, a lot of this money has actually come from the education cess that has

been applied. The CMP took not and said that 'we should achieve six per cent spend on education by 2009.' But if we still haven't crossed the three per cent mark, how is it going to be possible for us to come anywhere near this figure? And whether this figure is relevant or not too needs to be debated. The basic assumptions and the basic parameters which led us to arrive at the six per cent spend by the 2009 have undergone a sea change. To my mind, Sir, it is very inadequate if India is to make rapid strides that are required for us to maintain our position in the world scenario. The Government's priority should be to remove illiteracy and to provide quality primary education across the country. Sir, I would like to cite the example of one State, namely, Himachal Pradesh in this regard. In the 1950s, Himachal Pradesh had a literacy level of 4.5 per cent. Today, it is second only to Kerala. They have the highest enrolment rate of 99 per cent , almost one of the lowest drop-out rates at just two per cent and in spite of the hilly terrain, they have got easy access to school. Their per capita expenditure on students, on education is almost double that of the all India average at almost Rs. 140 and they have one of the highest teacher-to-student ratios. And, how was this possible? All this was possible because of a very proactive Government policy pursued by subsequent Government and a very high spend, almost 16 to 17 per cent of their expenses, go on education. So, if Himachal can achieve this, why can't we replicate this model all across the country? Sir, the paradigm of ensuring education for all has to change. This old attitudes and old mindsets will simply not work. There is just no transparency, no accountability and there is no incentives for the mover's of the scheme. Sir, even if we have to look around us to see what are the best tools used world-over to achieve higher levels of literacy, we should not shy away from doing so and I would just like to cite a few examples of schemes which have been extremely successful world-over. Sir, I would cite the case of Brazil where the resources for a district or a municipality are given through a framework of incentives. So, the higher the enrolment, greater the resources that are allocated to a district. This greatly incentivises districts and communities to work for greater enrolment. Also, Sir, they follow a pattern where education is not a linear experience; it is not a continuous experience; you have to have nine years of mandatory education which makes it so much easier for people to complete the so-called educational syllabus. Besides that,

incentives are given to teachers to go to the countryside and pay-scales have also been hiked manifold. This has led to far better educational services that are being provided all through. Sir, I would strongly urge the Government to carry out some kind of an annual school census. The Govenment, the Prime Minister and the Finance Minister have often spoken about outlays versus outcome. Why don't we apply the same yardstrick, not only in terms of budgetary outlays versus outcomes, but annual school census too that actually measures student enrolment, teacher participation and community participation to see where the money is being spent and the position that we have reached.

Sir, we must have a proactive education policy that provides quality primary education to the villages of India and the small towns. Without this, the knowledge disparity will only grow. The Navodaya Vidyalaya Samiti which seeks to ensure this must be prioritised and must be given all the support. Retention of students, student enrolment, absenteeism of teachers are all major issues plaguing the system today. The Government needs to address these.

Sir, the task before us is huge, and the holes are gaping. It is quite clear that the Government cannot achieve this on its own and, therefore, it has to involve the private sector. Our entrepreneurial energy has taken the economy to greate heights. This energy, Sir, needs to be harnessed so that the national goals of education and healthcare are met with jointly not only by the Government but by the private sector as well. Thank you, Sir.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, as I rise to support this Motion of Thanks to the President, I would be bringing to the notice of this House—unfortunately, many of the Congress Members are not here—how this whole notion of *aam admi and aam janata* came into the picture because we have been hearing about this from many quarters but, regrettably they are not being fully reflected in the policies that are being followed by this Government. I would like to draw attention to a document which was published in 2004 February-March, called 'Economic Growth—the Congress Agenda'

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

This was the basis on which later the Congress Manifesto and also the Common Minimum Programme were written. This particular document

was drafted by Dr. Manmohan Singh and myself who were the co-chairman of the Congress Economic Affairs Committee but they reflected entirely the ideas of Mrs. Sonia Gandhi. I would like to bring this to the notice of this House because this should be recorded. It was she who brought the entire Congress movement back into the mainstream saying that the Congress is basically a follower of the Nehru-Indira Gandhi tradition, followed by Rajiv Gandhi where common people, *aam janata, garib people*, are the main aims of Congress policies. This particular document was not critical of economic reforms. It, of course, hailed the economic reforms and also pointed out the very good points of these economic reforms resulting in the high rate of growth. This House is aware that the high rate of growth achievement is not the achievement only of this Congress Government; this was also achieved during the NDA period. This document clearly points out what the problems were and why the Congress approach to economic reforms and growth was superior. But, the most important feature in the Congress approach was the clear spelling out of the notion of the purpose of the economic reforms, the purpose of economic growth, which is the improvement or upliftment of the *aam janata* or the poorest people. Sir, I want to emphasise this point because I want to be constructive. Let me first take this issue of agriculture. All of us have talked about it; I don't have much time to go into the whole notion of agricultural development. But, it is important that we must realise that out of the agriculture—I quote from the document of 2002-03, Farm Survey—94 per cent of the farmer household belong to holdings of less than four acres. That is the *aam janata* of agriculture. No agricultural programme should be considered as the Congress agricultural programme or the UPA agricultural programme which does not address this 94 per cent people. I would like to ask the Ministers here—I am sorry, there are no Ministers here—I hope this would be communicated to them. I would like to hear what exactly is the Congress' economic reforms agenda in agriculture which is addressed to this 94 per cent people. Mr. Chidambaram has talked about a lot of increase in credit, but at the same time, as he said in the last budget that to the marginal and small farmers, we know, credit is not going there. He is talking about agriculture investment, helping NABARD and all these things. Only 1.8 per cent of the total investment in India is going to agriculture. When the total investment in the country is 34 per cent of G.D.P. and of that, only

1.8 per cent or 1.6 per cent is going to agriculture and only one quarter of that is only Public investment. And it is this public investment only that will go to the aam *janata*. They cannot borrow money to invest; they cannot have access to the investment fund of the capital market. So, Sir, I am pointing it out that in the formulation of all our policies, the most important step is to use this social aspect. As all Congressmen should ask; all Members of this House should ask after this UPA Government has come on the picture, are we really having a programme which is helping the *aam janata*?

Next, Sir, let me come to the question of employment because this document is talking about agriculture, freedom from hunger and unemployment. Now, employment, Sir, if you look at the Economic Survey, it clearly says that unemployment is increasing. It is a bad thing, we all know. But, I am not going into that. But it also says—we should not take credit for that—that the rate of growth of employment is about 2.3 per cent. It came down a little before that, but it has again gone up to 2.3 per cent. But then it says—it is very important to note—that the rate of growth of employment in the organised sector is negative. Not only that employment is stagnant, it is actually falling. And in the organised sector, manufacture sector is growing at a very fast rate at 10 or 11 per cent. I want to ask those friends of ours who say, if there is high rate of growth, there will be higher employment. How is it related to that? Nine to ten per cent growth is taking place in the manufactures' with negative growth of employment. Where are these people going? Employment is increasing in the unorganised sector. What is this unorganised sector, Sir? It is the sector where there is no minimum wages; it is the sector where there is no labour laws; it is the sector where there is no social security. The people work in the most difficult situation. Without water, without light, without shelter, they work there. They work there because without working they would starve. Are we taking pride in this that employment is increasing in that sector which is growing at very low levels of income, to avoid starvation? What is the policy that this Government is following to increase the productivity of the unorganised sector? I tried my best to look into the Economic Survey, Sir, I did not see a single sentence which would say this policy should be followed in the unorganised sector so that their productivity increases, their enterprises expands.

Sir, I have a small Commission, which I head, where we have given a programme which is that if you are talking about the SEZs,—which I think is a wrong approach—but SEZ has one implication that if you can put a cluster of inter-dependent units, there are external economies for each other. So they can benefit from that and after that they can grow. But it has to be supported only if we have infant industries, only when they do not have markets. There is absolutely no reason for supporting those who are rich, who are not infant, who can invest, who have their capacity to do all that. There is very little reason today to support export industry because our exports are growing at 20 per cent. Today, Sir, there is no difference between the Indian Rupee and the exchange rate in dollar. In fact, Indian Rupee is probably under valued or should be overvalued a little bit. There is no reason why we should subsidise exports for this SEZ by giving them land, giving them development, subsidies. So, what we suggested that if you are accepting that in your law as SEZ law, apply that to the cluster of poor, tiny sector establishments who need this kind of support, who need developers to come forward to help them, to push forward their markets and investments. If your SEZ is accepted principle apply that to the unorganised sector. Sir, I am just putting this as an example how to improve this thing. There are questions of skills, there are questions of all other kinds that we can actually look at. But I do not see any reference to these either in the Economic Survey or in the Budget and not in the President's Speech either. Sir, there is a reference to a proposal for the social security for the workers in this unorganised sector. I just want to mention, I do not want to talk about it much because we have initiated this whole thing. We proposed a scheme for 370 million workers in the unorganised sector—37 crores—for giving, as you say, maternity benefit, life insurance, health insurance of a recoverable amount, accident benefits, sometimes if they are thrown out of employment, employment benefit and pension benefit. This is a completely feasible set of programme. One year earlier, we had submitted this report and this particular programme is absolutely feasible, Sir. We have gone to places, we have discussed with those who can do it and we have had several discussions. Mr. Oscar Fernandes is not here. He would tell you that this is the programme, which is perfectly feasible. The total cost is only 48 per cent of the GDP, less than half a per cent of the GDP. If you could provide that, 36 crore people in our country would

come and support our UPA Government. Unfortunately, we have not made any progress in that.

I am just talking about one particular area. The other question is, social sector programmes. I am just trying to be as brief as possible. Mr Sitaram Yechury pointed out that the share of expenditure in social sector is down. It is going very true. But it is a mistake to think of expenditure as the criterion of developing social sector. You have to deliver, you have to see that it is actually delivered. In fact, in the Budget document they have increased the allocation for the National Rural Employment Guarantee Programme. Now, it clearly says that they have increased from 200 to 300 districts but the Budget allocation for these 300 districts has increased by only Rs. 700 crores. Why? It is clearly saying that whatever we have provided, we have not been able to spend. Who is responsible for that? Who is responsible for the fact that the National Rural Employment Guarantee Scheme having been enacted has not been implemented in this country. It is this Government, which should accept the responsibility and not only the Finance Minister, the whole Government should accept the responsibility. The only way to accept the responsibility, Sir,—again this is in this document which I can say was drafted and written under the leadership of the Congress President—was that you have to bring development through grassroot organisations, you have to go to the district level, village Gram Sabha to see how it can be organised, monitoring system. All these things have been spelt out how it should be done. Why have you not tried to do anything? Do not be personal because this is something, which probably should be done by the Planning Commission because they can do it with the States. Sir, anything you talk about the social sector, they would say that it is the State's responsibility. But this is not correct. It is the Planning Commission, which will sit with the State Governments, hold their hands, give them incentives, and show how this can be done. The State Governments have also their problems, see how those problems can be solved, and go beyond that, to the Panchayats and all these places. We have a person in our Government. He is not present here, Mani Shankar Aiyar. I would say that he has shown a way to organised the Panchayats to do this kind of job. Sir, I am saying that this is possible if we really want to do this thing. It can be done? Unfortunately, it has not been done. The social sector projects whether it is *Sarva Shiksha Abhiyan*, whether it is the National Rural

Health Mission, more and more money that you give, the money probably either will not be spent as in the Employment Guarantee Scheme mainly because we have a very good Rural Development Minister who does not waste money. I must give him credit or not spending money without delivering. There has to be a mechanism to monitor those delivering and the only way to monitor this thing is to have the whole planning mechanism revamped. Unfortunately, that has not been done here.

Sir, I wanted to bring these points, through you, to the House to note that the time has come for us to realise that the people of this country are not fools, they can see things as they are done. They are not expecting miracles from this Government but they have trust. They trusted this Government. They trusted the Congress President when she went to the people and said that, look we are going back to the Congress ideology. This trust should not be betrayed. If you betray the trust you must know people of our country have shown again and again how to penalise and punish those in power. Thank you.

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Sir, the President's Address has conformed to the time honoured format followed by all Presidents, including himself in the past and that is to list out all the achievements of the Government but not refering to the shortcoming or warning signals. I propose to bring out three or four such points.

In the first place, I was somewhat disappointed by the fact that the President did not refer to what I would call the most pressing problem that the nation is facing today and that is the threat to our internal security. I would particularly mention the fact that we think of internal security or debate or we talk about it only when some disaster happens somewhere. Yesterday, we listened to very impassioned speeches about the need for better safeguards internal security because we were shocked by the dastardly killing of a sitting Member of Parliament in Jharkhand. A few months ago, we were shocked by the attack on Jehanabad jail when several maoists prisoners were forcibly released from the jail. Again we were shocked by the mass murder of the tribals in Chhattisgarh. Once we get shocked we debate, we discuss and then we forget all about it the next day. The Home Minister as usual will come forward with the stereo-typed explanation, "it is mainly a subject of the State Government. We are doing everything to strengthen the hands of the State Government but it is mainly the work of the State

Government. We will continue to strengthen their hands". But when their hands get weakened, we do not see the strong Central hands, strong hands behind it and the result is, the whole approach to the problem of internal security continuous to remain a law and order approach in our country. I should also say—it may not be treated as a criticism of the Home Ministry—as one familiar with the working of the Government system for long years that internal security should be handled by the Prime Minister of the country. I don't say that it should be taken away from the Home Ministry. The Home Ministry is directly responsible. But, at the same time, the main responsibility should be with the Prime Minister. Then only it will be possible to enlist the full cooperation of all other Ministries concerned and also the State Governments concerned. If it is left solely to the Home Minister, you will see that he himself is helpless and is not able to deliver as much as the Prime Minister would be. This problem has become much more serious now than ever before because of the fact that India, today, is surrounded by failed States. In a Survey conducted by Washington-based Fortune Magazine, in 206, about 146 countries were listed in the order of their failure or tendency to fail. In the top list of 25 countries, there were 5 countries in our immediate neighbourhood. Pakistan ranks at number 9 in the list, Myanmar at 18, Bangladesh at 19, Nepal at 20 and Sri Lanka at 25. Our country is ranked at 97; and to that extent, we may feel happy. But the fact that we are living in the midst of failed States, surrounded by failed States, and also the fact that many of the things which caused the failure of these States are in evidence in our country also should send us the right warning signals for taking timely corrective answers. A State fails not only because law and order fails. A State failes for a variety of reasons and some of these reasons are very conspicuous in our own country. For example, the failure of institutions of democracy, failure of electoral system, failure of the executive, failure of political parties or the collapse of political parties influence over several parts of the country, lack of political leadership, lack of, at least, a few leader whose voice will be respected and heard all over the country, irrespective of religion, caste, community or political differences. These are all the reasons which had led to the failure of the neighbouring States. And, I say, Sir, with all sense of responsibility, many of these reasons exist in our country today and if we just go on ignoring them and continue to have the policy of putting the blame only

on the State Governments and not doing what we are expected to do as a united nation to handle this problem, we may also find ourselves in that list of failed States.

The Home Minister does not like this Statement. Sir, I am a Member of the Consultative Committee of the Home Ministry and I have raised my voice there also. I know, he does not like the statement that I am making. When we say 17 districts in India have seen affected by the menace of naxalite extremism. The Home Minister always defends by saying that these 17 districts are not affected, only certain areas in these districts are affected! That is, certainly, not the proper way of looking at this problem. If a whole district get affected, then, that will secede and will cease to be a part of India. If, tommorrow, the whole district is affected naturally, it will become some other State with some other name. So, the Home Minister should have the capacity to understand, if a portion of a district is affected, then, that district is affected. Therefore, the number of 170 districts should be taken seriously. These 17 districts are spread over fifteen States in India and therefore, it is no longer a localized problem. We used to speak of this problem in the periphery States of the country – North-East or somewhere in the Jharkhand, Bihar or some parts of Andhra Pradesh. But, 15 States have been affected and I would earnestly appeal to this House to exert adequate pressure on the Home Ministry, on the Cabinet and on the Prime Minister to make sure that this problem moves from the low-periority in the scale of importance which the Government has and moves right up to the top. If we fail as a State, what is the use of thinking of 9 per cent growth or striving to achieve 10 per cent growth? We may create an oligarchial system where a few people will be benefited and the country would have lost its integrity and strength as a country.

Sir, I now come to a few areas where the President's Address has not focussed on the causes of failure or even the fact of failure. The hon. Minister for Rural Development is present here, and I am encouraged to talk on this subject particularly because of his presence. I entirely agree with Shri Arjun Sengupta when he said that the Rural Employment Guarantee Programme has been a failure so far. It is only one year it has been started, but in this one year, the performance has been a total failure. I am not blaming the Minister at the Central

Government for this. I, certainly, have high regard and respect for him. He is a real rural person. But the failure is. ....(*Interruptions*)....

ग्रामीण विकास मंत्री (रघुवंश प्रसाद सिंह): सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: You will get the chance.

DR. P.C. ALEXANDER: You may kindly allow me to continue. You can reply at your convenience.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सभापति महोदय, रिप्लाई नहीं, हम सही पाइंट आफ इन्फोरमेशन देना चाहते हैं। हम सही सूचना माननीय सदस्य को दे देते हैं। सभापति महोदय, यदि कोई रोजगार गारंटी कार्यक्रम को फेल्योर कहता है, तो उसे जानकारी का अभाव है। सर, 64 करोड़ मेंडेट हुआ है, जो देशभर में 64 करोड़ होता था। ....(**व्यवधान**)....

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: वह आपका आंकड़ा है।....(व्यवधान)....

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: एक मिनट। इसलिए यह कुछ राज्यों में चुनाव के चलते पीछे हुआ, लेकिन इसकी बहुत सफलता से शुरूआत हुई है और यह प्रथम वर्ष है।....(**व्यवधान**).... यह भ्रम फैलाना कि गरीब विरोधी होगा।

श्री सभापति: वह गरीब विरोधी नहीं बता रहे हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, इसीलिए सही बात की सूचना हम आपको भेज देंगे। उसके बाद कमेंट हो, तब हम उसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति: यह सवाल इसलिए आया है कि इसको 37 परसेंट बताते हैं।

DR. P.C. ALEXANDER: Sir, since the hon. Minister has referred to mandays and the amount of money that has been spent, may I take a minute more to explain the position as it is? The average mandays created is only 37.5 as against the 100 expected to be created. When the Scheme was introduced some of us had said that 100 mandays will not make a difference and that the people in the rural areas should be given, at least, 150 days mandays in order to make an impact. But instead of 100 mandays, the average has worked out for the last one year at 37.5. The hon. Minister may kindly note this point. Till February this year, that is, till a few days ago, 1.64 crores of households have been covered by the Scheme. According to the programme, this should have resulted in 164 crores of mandays at the rate of 100, but, actually, the number of mandays created was just 64 crores. If the hon. Minister

thinks that these are sufficient indices of the success of this Scheme, I am sorry I have no answer to that. I am not blaming you, Mr. Minister. The first one year of its working has not been successful, has not been auspicious, has not been adequate to guarantee good results. So, it is up to us to look into the Scheme find out what is specifically wrong about it, why it has failed or why it has not taken off, and, then, correct it. But, we have hurried with adding 130 districts to the list of 200. I leave it to the House to decide whether this addition of 130 to the existing 200 was really justified.

Sir, I said I will mentioned two or three points in which I consider the failure to be conspicuous. And the next point is about Judicial reforms. The hon. President has said that judicial reforms have been introduced, which will result in considerable independence of judiciary alongwith accountability and all that. But what has happened is that in the name of judicial reforms, the Government have just introduced a National Judicial Council Bill and that Bill takes away from this House the right of impeachment of Judges. It takes away from you, as the Chairman, the power to appoint the Committee to go into the allegations against a Judge. It takes away the power of the Speaker of the Lok Sabha to appoint a Committee. Judges have appointed the Committee of Judges to look into the complaints. And if that Committee reports to this House, even if 50 Rajya Sabha Members or 100 Lok Sabha Members would have initiated the proceedings, no further action can be taken by the Parliament. Sir, is it a progressive step, is if a reform or is it a retrograde step which will only help the judges or the judiciary, rather than the Parliament or the nation as a whole. Sir, judicial reforms should be handled boldly. We should think of All-India Judicial Service. We should restore to the Executive the right to appoint the High Court judges and the Supreme Court judges. The Constitutional right that had been given to the Cabinet, the Prime Minister of the country, has been taken away. Now, Judges appoint judges; and judges are also to judge the judges. And, then, we talk of judicial reforms in the name of this Bill before the House. So, practically, the Presidential address about judicial reforms creates an impression that something is being done, but the reform will mark a retrogression and not a progress.

Sir, one more point and then I will stop, and, that is the creation of the post of a Minister for Minority Welfare. I belong, technically, to a

minority community. But I am proud to say that we, the Christian population in Kerala, have been treated with utmost generosity, tolerance support and cooperatin by the Hindu population of the State, not for one Century, but for 2,000 years. We have never, therefore, suffered from minority complex, the Christian community in Kerala. But there are various needs of the minority communities like Christians, Sikhs and Muslims but the solution is not to appoint one Minister for Minority Welfare. I know that Minister very well. Barrister Antulay has long experience of administration; he has been Chief Minister one of the biggest States in our country and a genuine natinoalist Muslim but you put him in charge of Minority Affairs while all the powers relevant to the welfare of minorities are with the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs and various other Ministries. His hands are tied. At the end of five years, he will get the blame for not doing anything for minorities; and, minorities will have all the problems and defects they always had before. Therefore, these things should be redone, reworked, rethought, and this should be faced squarely. When we find something going wrong, correct it then itself that is the sign of good administration.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion moved by – I don't know whether to say Dr. Karan Singh or Maharaja Karan Singh – Dr. Karan Singh thanking the President for addressing the Joint Session. ....(*Interruptions*).... Sir, it gives me great pleausre in supporting this Motion. I start with the comments made by Dr. Sengupta that this speech or the programme of the Government has been chalked out after a serious thought by the Congress President Sonia Gandhi over *Aam Aadmi*. Sir, Sushmaji was saying about the *prathmikta* of the programme, and, Mr. Vyasji of BJP was speaking on the agenda of the then Government. Prior to 2004, we have seen various Presidential Addresses. If you just see the political agenda on that, there was no mention of farmers or the labour class in those agendas. After seeing for almost seven years, the Congress President, Sonia Gandhi, brought this *'Aam Aadmi'* theory into practicality by announcing these schemes in the manifesto. Sir, right from 2004, the highlight of all these manifestos was *Bharat Nirman*. In *Bharat Nirman,* there were a lot of programmes of the UPA Government wherein the stress has been given to NREG, the Jawaharlal Nerhu National Urban Renewal Mission,

the National Rural Health Mission, *Sarva Siksha Abhiyan,* the RTI and Rajiv Gandhi Gramin Vidyut Yojana. Sir, about all these programmes, a lot of Members have already spoken. They have made a mention about the Agricultural and National Rural Employment Guarantee scheme and other schemes like *Sarva Siksha Abhiyan.* I would just like to confine myself to Jawahalal Nehru National Urban Renewal Mission. This is one of the noble programmes as far as the urban infrastructure is concerned because, probably, in 2025, almost fifty per cent of the population of this country will be living in the urban areas. Therefore, there should be a vision to tackle the problem of urban infrastructure in this country. Sir, if you go by the history of the major metropolitan cities like mumbai – I will start from Mumbai – you will find that almost 60 per cent of the population lives in the slums. If I take the example of Tamil Nadu, a huge population lives in the slums there. Even if I take the example of Hyderabad, there are also a large number of people who are living in slums. In Bangalore alone, a huge population, something around 20 lakhs people, is living in slums. The majority of the people who have come from Tamil Nadu are residing peacefully in Bangalore and in other parts of the adjoining States like Goa. These States get maximum migrated population from Northern Karnataka where because of severe drought, a lot of people migrate from that part of Karnataka to Goa and Maharashtra. Sir, the President has rightly given more importance to the Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission. The Government has announced a huge package of almost one lakh thousand crores to be spent within seven years in almost 63 major metropolitan cities and towns. Sir, coming back to the rehabilitation of slum dwellers, I have been visiting some of the State capitals and some of the slum development areas, where instead of rehabilitating the slum dwellers, the programme is confined to relocating those slums. Some amount is also sanctioned for rehabilitation of the slums. Sir, there should be a proper vision, a proper planning while rehabilitating and providing the basic amenities for this poorest of the poor classes in the urban areas. Sir, there is a huge migration. As I said, by 2025, almost 50 per cent of the population would live in the urban areas. The reason for it is the huge migration from the rural areas to the urban areas because in the rural areas, we are not finding suitable employment opportunities for these people. So, the people are migrating to these State Capitals. Naturally, we have to provide the basic amenities for these people as

there are not basic amenities in the original slums. Where we are unable to provide the basic amenities there, naturally we have to go in for rehabilitation. For rehabilitation, we have to construct houses. I think, Tamil Nadu is the number one State in the country which has provided a wonderful rehabilitation scheme for the slum dwellers. It has not relocated the slums. It is my personal experience. In Tamil Nadu, they have done a wonderful job. ....(*Interruptions*).... No; no; I belong to a national party, the Congress party, and I think in the national perspective and not in the regional perspective. Sir, the President has rightly announced a special package amounting to more than Rs. 60,000 crores which is to be spent in 31 districts which are most affected by the farmers' suicide.

Another point is, in para 20, it has been said that the Government recognises the serious nature of the problem of water availability and water use both in agriculture and the urban economy. Sir, when the hon. President started his speech, he said that this is a special year in which we are celebrating the 60th year of the Independence, 150th year of the First War of Indian Independence and the centenary celebrations of our Satyagraha Movement. Sir, even after sixty years, some of the sensitive issues have not been addressed in this country, especially the issue of boundaries and water.

Let us take the example of Karnataka. Sir, after the reorganisation of States in 1956, the State of Karnataka was formed by taking bits and pieces from the Bombay Presidency, Madras Presidency, Nizam of Hyderabad and the Maharaja of Travancore. Bits and pieces were taken from these States and Karnataka was formed on linguistic basis. According to the Planning Commission, almost 160 taluqas are severely drought-prone areas. According to the Planning Commission, Karnataka has the largest arid area, more than even what Rajasthan has.

Sir, almost we have been seeing in the Parliament, some of our big brothers around us, around Karnataka, trying to paint Karnataka as a recalcitrant State, that is, the State which does not obey orders. Sir, it is ridiculous... *(Interruptions)* Is it correct? Sir, it is ridiculous if you go by the data pertaining to the Cauvery River. Karnataka's claim before the Tribunal is about 300 TMC for irrigation. Under the existing and ongoing projects, what is allowed is only 251 TMC. Against the cropped

area of 25,284 lakh acres, what is allowed is only 18,000 lakh acres. The area of cultivation under paddy has been reduced from 8000 lakh acres to 7000 lakh acres. Sir, against the cropped area of 29269 lakh acres, what is allowed is only 24000 lakh acres. This is gross injustice done by this Tribunal which was constituted in 1990.

Sir, in 2002, the Cauvery Regulatory Authority was constituted to regulate the flow of water in the Cauvery basin. The Tribunal, in its Order, has gone totally against the interests of Karnataka. It does not do any justice to Karnataka. It is death-knell to the farmers of Karnataka. People may say that Karnataka is greedy and does not allow the water to flow. Chandrasekar Reddyji or any of our other neighbours may say that. As I said, when the State was formed, it was formed with many disputes with the neighbours. In the past ten years, in Karnataka alone, 30,000 farmers have committed suicide. if there were proper irrigation facilities, if there were water, I don't think these many people would have died or committed suicide in Karnataka. The Tribunal is totally partisan in its approach. It never went into the technicalities of the availability of water. The demand of Karnataka is equitable apportionment of water to all the neighbouring States...*(Interruptions)*... I am not talking about Tamil Nadu ...*(Interruptions)*... I am talking about the injustice done to Karnataka. ...*(Interruptions)*... I am talking to the Chairman. I am talking about the injustice done to Karnataka. The Tribunal should be thrown out into the Arabian Sea, not even in the ...*(Interruptions)*... It is a partisan Tribunal.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, there is a provision to file a petition within three months before the Tribunal. that opportunity could be utilised; it need not be raised in this fashion... *(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Chairman Sir, that was the understanding that we would not raise the Cauvery issue. But hon. Member, Shri Narayanan had raised the issue yesterday. That is why I was forced to raise the issue. Otherwise, I would not have raised it.

MR. CHAIRMAN: You raise some other issue.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, as far as the Tribunal Award is concerned, it is a death knell for the farmers of Karnataka. Karnataka

will *in-toto* reject the Award given by the Cauvery Tribunal Authority, and we will not accept that.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): The Tribunal's order is a judicial order. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: The Centre should intervene to save the suicide attitude of the people of Karnataka, especially in the Cauvery Basin because the people are suffering due to shortage of water. Not only farmers, Sir, there is shortage of water even in Bangalore, where almost 80 per cent of people from Tamil Nadu are living. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): There are so many people from Karnataka who are residing in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Chairman, Sir, even the Tribunal has cut down the quantity of drinking water for Bangalore city. That is a great set back. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Are you not satisfied with 600 tmc of water? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, he is saying that people from Tamil Nadu are living in Karnataka. ...*(Interruptions)*... What is this?

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: I am proud of them. ...*(Interruptions)*... I am proud of them. I am proud of Tamilians who are living in Karnataka.

MR. CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, you have spoken enough about it.

SHRI B.K. HARIPRASAD: I am proud of Tamilians who are living in Karnataka. ...*(Interruptions)*... I am proud that even your leader is from Karnataka. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down, sit down, sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI S.G. INDIRA: You cannot direct me like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Mr. Chairman, Sir, I am not mentioning anything about Tamil Nadu. Sir, I am talking about problems in Karnataka, and they should not feel bad about that. ...*(Interruptions)*...

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: There are 25 lakh peasants in Karnataka who are utilising the Cauvery water in Karnataka itself. We want to protect both the ethnic groups. ...*(Interruptions)*... They can't even now enter Bangalore. ...*(Interruptions)*... Without protection the Tamilians cannot enter Bangalore from Tamil Nadu. That is the worry we are having. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, my only point is, only Tribunal or any court cannot decide on the nature. The natural resources can only be decided through the political statesmanship or through negotiations and not through the court or the tribunal.

Sir, finally, I have one more point. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Let us have friendly discussion. ...*(Interruptions)*... You are not agreeing to it. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, we are ready for it. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: They are not agreeing to any discussion.

MR. CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, are you from Tamil Nadu? ...*(Interruptions)*... Then, please keep quiet. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, we want to make it clear that we are ready for any discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I wanted to know only one thing whether you are from Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in the Cauvery water, Puducherry also has a share. ...*(Interruptions)*... It is not Tamil Nadu alone. We are also having interest in that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You are from Puducherry. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, Puducherry is also having its share in the Cauvery waters. ...*(Interruptions)*... Sir, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry are the four States which have share in it. ...*(Interruptions)*... Sir, Puducherry is also getting its share in that.

MR. CHAIRMAN: Now, come to some other point. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the Award by any standard is biased and is not acceptable to the State of Karnataka.

MR. CHAIRMAN: You have spoken so many times about it ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it is a burning issue.

MR. CHAIRMAN: It may be a burning issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: People are saying that we are not discussing it. ...*(Interruptions)*... The Parliament is not discussing it. It is an allegation against us. So, Sir, you have to allow us.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let him finish.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, we have requested for a Short Duration Discussion on this issue, but you have not allowed it so far.

MR. CHAIRMAN: You are speaking on that particular subject, then, what is the need of the Short Duration Discussion? This matter has been discussed here. He is speaking on this. ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it is not like that. What I am saying is, the Short Durating Discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You please take your seat. ...*(Interruptions)*... I won't allow you.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, you are not allowing me to speak.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, the river Cauvery does not get any water from the mountains of the Himalayas. It is entirely dependent...

MR. CHAIRMAN: You take water for Cauvery from Rajasthan. Then, you will be satisfied. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, it is a rain-fed river. Unless there is a good monsoon, there will be a serious problem in both the States. The Cauvery is an emotional issue for all the States around Karnataka.

I am not naming any State. Sir, even we have a dispute with Andhra Pradesh, as for the Krishna is concerned. We have a dispute with Goa which is a small State as far as the Mahadayi is concerned. We have a dispute with Mr. Narayanasamy's Pondicherry, which is also a small State. We have a dispute with a State like Kerala. But, Sir, it is a very sensitive issue because we are upper riparian State. The rights of upper riparian States are not defined. The same problem, what Chandra Sekhar Raoji is facing, we are also facing with regard to the Cauvery. Sir, what has happened in Punjab is that the Supreme Court has given an order, the Tribunal has given an order, it has not been implemented. It cannot be because it is an emotional issue. If there is negotiation at people to people level, then only this issue can be solved. Sir, in view of the kind of sensitivity the President has expressed in his speech, we should take it very seriously on emotional issues concerning boundaries and water, and it should be solved through negotiations. With these words, I support this Motion. Thank you.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, while generally supporting the Motion of Thanks on the President's Address, I would like to highlight a few important points which I wished should have been included in the President's Address.

I am thankful that a reference has been made to the 150th Year of India's First War of Independence, the great uprising of 1857. But while celebrating the 150th anniversary of this great event, we must not miss two very significant aspects. Firstly, it was not only an armed revolt of the then British Indian soldiers against the British Raj but the millions of oppressed poor peasants, ousted small *jamindars* and local freedom loving kings, retrenched soldiers and the common people as a whole joined the armed revolt.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Secondly, people of all communities Hindus and Muslims unitedly fought against the British Raj. This question of communal harmony is still very important and relevant today. Of late, some forces are very active to create communal violence and casteist hatred and divisions in the country. It is necessary to defeat these evil forces. The hon. President should have made a reference to it.

5.00 P.M.

Great optimism about the economic performance of the UPA Government has been expressed in the President's Address. But the much-publicised 9.2 per cent rate of growth of the GDP has in reality no impact on the lives of the common people. Benefits of economic growth have been concentrated among the 15 per cent of our population. so, there is no point in just making a fanfare of this high GDP growth. The people are hard hit by all time high up to 6.7 per cent inflation and continuously increasing prices of essential commodities. It has been even admitted in the President's Address but efforts have been made to over simplify the crisis and its reasons. The explanation that-'As growth and investments accelerate rapidly and incomes', there is rising demand which the supply side cannot meet causing thereby price rise is not based on reality and is, therefore, definitely, misleading. Dismal performance of agriculture cannot be ignored which has caused high price rise of all essential commodities like wheat, rice, pulses, milk, sugar and even vegetables commonly used by the people. The unabated price rise is artificially created by the traders, business houses and hoarders who indulge in forward trading with all the support and help from the Government. Instead of repeated demands by the Left parties, the Government did nothing to widen and strengthen the Public Distribution System. The Finance Minister in his Budget proposal has now ridiculously proposed only to computerise the PDS for strengthening it; but that is not the way to widen and strengthen the PDS. The Government has now pushed the country to a deplorable position of utter dependence on import of foodgrains on the one hand, and on the other hand thousands of peasants are committing suicides. It is a matter of shame for the country and it even reminds us of the dark days when the country had to wait anxiously for the arrival of ships with wheat from America under P.L. 480. The other matter of great concern is the Government's growing effort to bring all the sectors of public life under the public-private partnership model and ultimately, leading to all out privatisation, starting from various railway services and commercial activities, important areas of health and education are also being pushed through PPP model to privatisation. This is a typical feature of capitalist economy which would do more harm than benefit to the country. Under such a disastrous economic situation the Union Budget for the year 2007-08 has failed to give any good news of hope

to millions of unemployed youth of the country. The Government has completely failed to tackle the unemployment problem and in short, the UPA Government has failed to meet its commitment under the National Common Minimum Programme. Left support to the UPA Government was based on the NCMP. We hope that the Government would revise its anti-people policies and honour its commitments under NCMP. I would have been glad if all these issues were included in the President's Address for which we thank the hon. President of India. I promised to the hon. Chairman that I will make a very short speech, so, I just conclude my speech on the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address with observations. Sir, much has been said from the Government side about the growth of GDP to the extent of over eight per cent during the last three years and President has said that the Government is committed to provide food security to the poor, further strengthening the PDS.

But what is the real experience in our day-to-day life? Even in Delhi, the prices of onion alone in the last two weeks, in recent times, have risen from Rs. 16 per kg. to Rs. 26 per kg. The prices of all commodities have risen. If we consider the Budget of a working-class family in Delhi, the unit requires, at least, Rs. 800 to Rs. 1000 more to maintain the same standard of consumption as they did a year ago. And, Sir, there is 6.58 per cent increase in the WPI for the 4th week in January, 2007 which was the highest increase in the past two years. This is the commitment fulfilled by the Government! Who is responsible? The Left parties are long demanding to lift all restrictions on the entry of speculative capital in the future trade in agricultural commodities. In the last three years, the amount of speculative capital started trading in such essential commodities has increased hugely. The total value of future trade in commodities in 2003-04 was Rs. 1.2 lakh crores, increased to Rs. 5.71 lakh crores in 2004-05 and then to Rs. 21.43 lakh crores in 2005-06—an increase of over 600 per cent in just three years! In 2001-02, with the production of 696.8 lakh tonnes of foodgrains, there was a procurement of 206.30 lakh tonnes. In 2005-06, at about the same level of production, the procurement of the Government had come down to just 91 lakh tonnes. The consumers have to pay high prices in the open market. Our country, simultaneously, became the biggest importer of wheat during that period at a price of Rs. 400 more

per tonne than what was paid to the Indian farmer. No effort of the Government has been found to provide adequate price support to the farmers who are in distress. Sir, the farmers get relatively low price for their produce. Traders release the essential commodities into the market only when the prices shoot up due to artificial shortage. Sir, whose *Swargarajya* it is—free play of the market and the retreat of the Government? This is what we have found.

Sir, according to the UNDP Report, India ranks 126 in the human development ranking of the 177 countries. India represents 17 per cent of the world population. And, India accounts for 23 per cent of child deaths all over the world, 20 per cent of the maternal mortality, 68 per cent of leprosy cases and 30 per cent of the Tuberculosis cases. Very recently, we have been given a figure. So far as the ICDS programme is concerned, 3.6 crores of children, out of 6.51 crores weighed and measured between the age group of 3-6, are malnourished in varying grades of malnutrition. Sir, outlay for Sarva Shiksha Abhiyan has been cut. Allocation to the ICDS has been increased by a mere Rs. 674 crores. The entire provision for social security for labour has been increased by a paltry Rs. 1 crore! Sir, we have seen the comments of the President in his Address. Many hon. Members have quoted it. I would also like to quote it. It was in the last para of the Address. It says that through the great institutions of our democracy that the people of our country are the recipients of better governance. The number of unemployment grew more than three times in ten years. All the Reports suggest intensification of poverty, widening of disparity and rich galloping fortunes of a handful of affluents. Agrarian crises and farmers' suicides have intensified. The unemployment rates for both men and women, in both urban and rural areas have increased. Sir, the organised sector's share in employment has fallen from 9 per cent in 1991 to 7-8 per cent in 2004. The annual growth of employment in the organised sector between 1994—2004 declined by minus 0.38 per cent. We have been demanding for long for a proper legislation for the unorganised workers. Mr. Arjun Sengupta's Report was submitted in March, 2006. How long will it take for the Government to implement this recommendation?

According to the Economic Survey of 2004-05, around 92-93 per cent of the total workforce is engaged in unorganised sector. The condition of unorganised sector is, generally, marked by lack of

regulation employment, denial of benefits, seasonal employment, apparently no formal employer, absence of social security, etc. Even in the organised sector, the numbers of contractors and casual workers are increasing. At the same time, within one year, that is, between August, 2005 to August, 2006, the wealth of richest Indians grew by over Rs. 32,000 crore, that is, if we compare the list of Indian billionaires. On the other hand, in the Budget which was presented, the service tax for corporates has been reduced instead of raising it for mobilisation of resources for the welfare schemes.

Sir, on the question of SEZs our leader, Shri Sitaram Yechuryji has replied to this. The answer is that the Left is in favour of SEZ for industry. But some are in favour of real estate; SEZs for real estate. Our Leader, Shri Sitaram Yechuryji pointed out that here.

Sir, in the President's Address there is no mention of the communal disturbances. In West Bengal we are facing the problem of bank erosion in the North Bengal river. That has not been mentioned.

Sir, our Railway Minister was previously against privatisation in the Railways. But now he has come out with a budget which favours privatisation of the railway services. This is another thing which I would like to point out here.

Lastly, Sir, I would like to mention one point raised by Smt. Sushma Swaraj about the industrialisation prospect in West Bengal. Sir, I would like to mention that in the Singur block only 2.55 per cent area has been taken for industrialisation. It is not industry versus agriculture. It is not that. So, agriculture is the basis and industry is the future. This is the motto of the West Bengal Government. They have made it amply clear.

Sir, the Left initiated distribution of *benami* land to the landless peasants and that is a part of the history. Since land belongs to the tiller, they have received the compensation unparalleled in India. Rs. 8.40 lakhs to Rs. 12 lakhs per acre was given. This is unprecedented in the history of our country.

Sir, lastly, we also want to have a discussion on minorities in Parliament. Our Party has also placed one paper in the national plenum. In West Bengal, we are very serious. We know that in the process of

land reforms introduced in West Bengal, the rural population, irrespective of religions, have been benefited through this land distribution programme. With these words, I support the Motion of Thanks on the President's Address. Thank you, Sir.

DR. K. KASTURIRANGAN (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, the President in his Address identified several dimensions of the country's development. As it is difficult, within the limited time available, to pick up most of it, what I propose to do is to take up three of the major issues. I call them issues because, certainly, they are things which we need to address and take actions. The first one is related to higher education; the second is the skewed distribution of science and technology development within the country and its implications on the socio-economic growth; and, thirdly, certain elements of the environmental protection. The hon. President had underscored the importance of higher education in the context of evolving knowledge-based society in which India is expected to play a major role in the 21st Century. He has suggested that we should look at all the possibilities with respect to revitalisation of the higher education. In fact, he brought in a sense of urgency in his statement. I may say in this context that over the year, the 200-odd universities, the State Universities, have slowly become less and less effective and, I should say, it has become difficult for them to deliver quality education which they are expected to do. If one looks at the issues that are the reasons for this kind of a situation, one see that there is the question of outdated curriculum, there is the question of timely induction of qualified faculty, there is the question of poor infrastructure as well as the bureaucratic set up within which the universities function and overall ambience. Even though many steps have been taken in the recent years to correct many of these and to try to improve the functioning of the universities, much remains to be done. I would say a few of these in the context of an action plan. First of all, there is an imperative need for restructuring the governance of the university system, particularly, through the provisions of sufficient internal autonomy. When I talk about the internal autonomy of the university system, I talk about autonomy in administration, autonomy in finances, and most importantly, autonomy in developing the academic system. Different models have already been tried out in this country. The publicly funded institutions, in fact, when one looks at IITs and many other

institutions—have models which have successfully functioned in the context of governance and autonomy. The question is whether one can adopt these kind of autonomy models into the university system so that one could bring in an element of responsibility, accountability, and most importantly, a sustained excellence in their performance. And, of course, the Human Resource Development at the Centre level and the State Educational Agencies certainly have to come together in reviewing various mechanisms that are needed to bring in this autonomy and try to see whether we can provide a new direction to the management of the universities which is sorely in need of new directions with regard to governance.

The second important point relates to the support in terms of financial, infrastructural and induction of quality faculty into the university academic system. In this context, more recently, a Committee was set up under Professor M.M. Sharma—he is a very well known Chemical Engineer and an Educationist—to improve the working of universities. They came out, after going into the details of the functioning as well as the type of problems that the universities currently face, with a recommendation for selecting a few universities and also providing them with something like Rs. 600 crores as a first step towards rejuvenating universities. Certainly, it is a very important step in the context of looking at the universities; but when one looks at something like 20 to 30 universities that we need to select and try to take them to the world level, obviously, the type of money that one is talking of is like Rs. 20,000 to Rs. 30,000 crores in the next 10 years. So, roughly, one is talking of Rs. 2000-3000 crores per year. This is the only way in which universities can be made to function with an objective of excellence. We can put a target that in the whole process, at least, 10 of them would come within the best 100 universities across the world. So, with this kind of targets, with this kind of a performance demand and also ensuring that necessary restructuring has also been carried to ensure proper assimilation of this kind of money, I am sure, the universities could be brought into stream.

The third important aspect that I would like to bring is related to the need of bringing a stronger synergy between the undergraduate and the post-graduate education and the research. Today, if one looks at it, we have the colleges which provide the undergraduate education. There are universities which provide the post-graduate education. A substantial

amount of research work is done in the institutes. So, obviously, there is a need to bring in synergy within the university system. One of the beautiful elements of a university system is the ability to bring this synergy simply because all the elements are existing side by side. So, it is in this connection that a restructuring again in the context of the academic activities itself is called for. On the other side, one should also remember that for most of the students, the first degree is also the last degree. If I just give an analogy, if you look at the Cambridge University and suppose you have something like 200 and odd students who are undergraduates for the physics, about 85 per cent of them leave the studies and take up the professional jobs. Only 15 per cent of them go into research as well as other higher academic pursuits. But 85 per cent of these graduates who come out of the Cambridge University certainly perform extraordinarily well in terms of societal and professional careers. Central to the success of an undergraduate programme in this connection—nobody talks about the undergraduate programme; one always worries about the higher education, the Masters and Ph.Ds—is the need to bring in a new rejuvenation of the undergraduate curriculum, undergraduate teaching support as well as undergraduate laboratory infrastructure. The reason why I am emphasising this aspect of it, Sir, is that currently the undergraduate education is not given the same attention and resources in the context of improving the undergraduate education, and this has its impact in trying to turn out B.Scs or BEs and so on, whose performance immediately in the job market is much less than what the job market looks for. And, it is here that we need to really make changes in the educational system to make the undergraduate education much more effective. It also enables one to draw a certain human resource for the higher education who are much better prepared for higher education than what the current undergraduate students could perform.

The second point is in purely statistical terms, I may mention Mr. Deputy Chairman, not reckoning with the quality parameters, India's numbers significantly exceeds the US numbers up to the level of the first degree. In fact, we produce three million undergraduates against 1.3 million of the US. However, the world famous graduate schools in US produce 1.5 times the number of Masters degrees and 2.7 times the number of Ph.Ds in all disciplines compared to India. So, one can

see that there is certainly no connectivity between the number of undergraduates we produce and the number that is carried forward for higher education. Interestingly also, while the United States produces far more Ph.Ds in science and engineering, somethings like 1.5 times compared to those in other disciplines, India does just the opposite. India's Ph.Ds in other disciplines is 1.5 times more than the number in science and engineering. This comparative picture allows us to conclude that the quality of our educational system at all levels and throughputs at the tops levels of higher eudcation, *i.e.*, Masters and Ph.D, have to be significantly higher, and the second one is that it is not an impossible task for India to exceed the US numbers, and I want to underscore this that it is not at all impossible in the next ten years to do this and to match the quality of education that the US imparts. It is still possible in this country.

What I would like to say is that it is also good to see that there is a recognition of all these—it is not that I am saying something new today—at the higher level. I see it as a member of the Consultative Committee of Parliament. When I sit there I find that there are many Members who raise the same kind of questions which I have raised here. It is also good that the President has considered it important to include the higher education and the improvement in the quality of the higher education as a matter needing urgent consideration.

I shall mention one more issue, If you permit, Mr. Deputy Chairman, Sir, and this is regarding the disparities among the States in their capacity to create and use technology for development, and this is a kind of thing that has persisted over a long time since Independence. If one looks at the last decade's transformation that has been effected through economic liberalisation and emergence of global market place, it has raised the stakes of all the States to be able to create, adopt and use science and technological innovations. I am not talking of institutions being built in different States and they contribute to some national programme. There are several areas of science and technology that would directly impact the grassroot level provided one is able to develop the local science and technology system or elements that could be absorbed. It is here that first we have to address ourselves to what is the role of science and technology in the socio-economic regional development. Are States capable enough to reap such advantages? How

does one measure such capabilities? Sustainable science and technology development requires efforts in all three aspects of development, namely scientific, economic and human. While some States have done some breakthrough-work regarding the development and innovative techniques involving science and technology and adopting them to their benefit, this has not been put to use in majority of the States. So, there is still a tremendous amount of work, and I should say this in the context of a very good study that has been conducted very recently by Prof. Rama Rao, an eminent educationist, and a group with him, who have clearly pointed out the correlation between the socio-economic development and that State's ability to pursue science and technology as a means of contributing to the socio-economic development. There is a very clear-cut correlation. So, there is an urgency to remove these regional disparties; a much more closer look at how well is the science and technology integrated with the State's development plans is required. There are certainly State-related Science & Technology Ministries and other kinds of departments, but the question is how well it is integrated with the developmental aspects of the State and how much it can impact in the coming years in the context of the socio-economic development. I think one needs to do quite a lot of exercise and I think it is very important.

Thirdly, I would like to make just two points; one is related to the environment. The hon. President mentioned about the greening of the whole of the country. I may mention that this is in the context of sustainable development strategy. Particularly when it comes to the question of greening, one can look at the current forest cover—about ten per cent is the close cover; nine per cent is the open cover; and there is something like wooded cover, trees and other greenery outside the forest cover, which is about five per cent. So, about twenty-four per cent of the area of the country is what you may call as a forest cover. The national target is something like 30 to 33 per cent and there has been quite a lot of targets that have been set as to how we would reach this 30 or 33 per cent. One could also consider, in this context—since it is not going to be very easy and I would come to why it is not so easy—the issue of wastelands and I am aware that we have today excellent wasteland map right up to the district level. This information system about the wasteland certainly provides us with an information

base as to the strategy of making much of the wasteland, something like 45 million hectares, which could become culturable. So, out of the 45 million hectares, the queston is, whether one could use between 15 to 18 million hectares for social and commercial forestry. And this would straightaway take us to something like 30 per cent in terms of greenery. So, this is one idea which I would leave which could be though about in the context of the country's afforestation programme and increasing the greenery. At the same time, if one looks at the current forest reports, and every year we get this report on the forests and there is biennial report to the Parliament about the status of the forest wealth in the country, one clearly sees that one good thing is that we have arrested the depletion of forests; the denudation of forests is today arrested. But, on the other hand, if one looks at whether we are moving towards the 30 per cent, it is clear that is has been very marginal. So, there is an urgency to look at what is the best strategy for increasing forestation, taking it to the national goals, within what time-frame we could do it, what is the phasing we need to do; what kind of information base we need; what kind of monitoring we need to carry out; I think a new strategy to do these needs to be evolved.

Closely related to the forest, of course, is also the bio-diversity. There has been a lot of discussion on the question of what is the level of bio-diversity and the impact of anthropogenic as well as the natural and green-house warming, what impact it could have on the bio-diversity of the country. I may mention, in this connection, Sir, that we have something like 7.5 per cent of the world's biological diversity and which accounts to something like 37,000 flora and fauna. We have something like 14 bio-diversity hot-spots in the country. Assessment of the impact of the climate change, as well as, the anthropogenic activities show that Alpine, semi-alpine and species in temperate regions are likely to be most affected in respect of loss of diversity. In fact, they are already becoming a threatened species. Sir, there is an urgent need here to carry out *in-situ* and *ex-situ* conservat on measures, and we also need to bring in the modern bio-technolog cal interventions, particularly to genetically modify, multiply and popu late such species in suitable habitats to conserve the same. We, of course, have to evolve the necessary policy and the legislative framework, if needed, in this connection.

In summary, Mr. Deputy Chairman, Sir, education, science and technology and sustainable environment friendly development approaches, all call for dynamic and action-oriented strategies to be addressed with a sense of urgency, as India sets its ambitious targets for its role in the 21st century. It is in this context, I thought that I will pick this up and make some of these suggestions. I use this opportunity to express my support to the Motion of Thanks for the President's Address.

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय डा॰ कर्ण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए मैं यहां पर खड़ी हुई हूं।

मान्यवर, यह जो अभिभाषण है, जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया गया, यह इस UPA सरकार का संकल्प दिखाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ग्रामीण विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। गांवों के चहुंमुखी विकास को, किसानों, के कल्याण को, महिलाओं और बच्चों के कल्याण को और जो भी इस समाज में कमजोर, निर्धन, पिछड़े उपेक्षित और शोषित वर्ग हैं, उन सबको कैसे प्राथमिकता देते हुए उनका विकास किया जाए, कैसे उनको समाज की मूल धारा में लाया जाए, विकास की मूल धारा से जोड़ा जाए, सरकार की यह मंशा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट जाहिर होती है। इसके लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत धन्यवाद देती हूं।

महोदय, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों, इन तमाम वर्गों के लिए इस दस्तावेज में, इस अभिभाषण में बातें कही गई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री डा॰ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में संचालित इस UPA सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए विशेष बधाई देना चाहूंगी कि पूरे देश ने यह देखा है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ, पिछली जब NDA सरकार थी, वादे तो तब भी हुए। आज गांव-गांव में जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की एक सबसे बड़ी मांग है, वह है रोजगार। NDA सरकार में भी पूर्व प्रधानमंत्री जी का वादा था प्रतिवर्ष एक करोड़ लोगों को काम देने का, लेकिन वह वादा महज एक कागजी वादा बन गया। लेकिन, हमें इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को, एक सशक्त योजना बनाते हुए, न केवल कहा बल्कि उसको लागू भी किया, न केवल लागू किया बल्कि उसे 200 जिलों से बढ़ाकर 300 से अधिक जिलों तक ले जाने की जो बात कही है, ...। उससे यह जाहिर होता है कि इस सरकार की संकल्पशक्ति एवं वास्तविक मंशा क्या है। सरकार की कथनी एवं करनी में कहीं पर कोई अंतर नहीं है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी की जो नीयत है, जो छवि है एवं जो कार्यक्षमता है, सारा देश ही नहीं पूरी दुनिया भी इस बात से परिचित है। इसी प्रकार यूपीए की अध्यक्षा की सदैव कमज़ोर वर्गों के प्रति जो चिंता रहती है, उनके प्रति उनकी जो संवेदनशीलता है, उसे भी समय-समय पर, अनेक अवसरों पर, पूरे देश ने देखा है।

महोदय, इस अभिभाषण प्रस्ताव के लिए चंद पंक्तियों में मैं कुछ कहना चाहूंगी, सरकार की भावना इन पंक्तियों से अभिव्यक्त होती है:

गांव गरीब को पहले हक़ दो, गांव ही अपना नसीब है।

अपना गांव गरीब है तो सारा देश ग़रीब है।।

इस अभिभाषण से यही भावना दिखाई देती है।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से जो चिंता सामने आई है, वह है महंगाई एवं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। राजनीति से ऊपर उठ कर आज यह चिंता हम सभी को है, पूरी सरकार को है। प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में राज्य सरकारों से अपील भी की है, क्योंकि महंगाई अथवा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, बढ़ते हुए अपराधों अथवा आतंकवाद पर नियंत्रण करना, इसकी समूची ज़िम्मेदारी कभी-भी किसी केन्द्र सरकार की नहीं होती है। हर जगह पर राज्य सरकारें हैं, उनका अपना दायित्व होता है, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उनके अपने अधिकार होते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था होती है, प्रशासन होता है, पुलिस होती है, सभी कुछ होता है, उसके बावजूद विपक्ष की ओर से अगर कुछ माननीय नेता यह कहते हैं कि समूची जिम्मेदारी केवल केन्द्र सरकार की ही है तो यह बात उचित नहीं कही जा सकती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकारों से अपील भी की है कि वे महंगाई और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जमाखोरों, सटोरियों, कालाबाज़ारियों और वायदा कारोबारियों पर नज़र रखें, उन पर लगाम लगाएं। ऐसा न हो कि केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत जब हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया जाता है, उनकी ओर से उसके लिए कोई धन्यवाद तो नहीं आता लेकिन इस तरीके से दोषारोपण मढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। ऐसे में तो हम यही कहेंगे, यह तो वही बात हुई कि ''मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू''। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए सामूहिक प्रयास होने जरूरी हैं।

महोदय, महिलाओं के कल्याण की बात कही गई है, इस संबंध में ''हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम'' ला करके इस सरकार ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके माध्यम से पैत्रिक सम्पत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के बराबर भागीदारी दी गई है। इसी तरह से ''घरेलू हिंसा निवारण विधेयक'' लाकर महिलाओं को घरेलू हिंसा से राहत दिलाने का संकल्प इस सरकार के द्वारा

दिखाया गया है। लेकिन साथ ही सरकार इस बात पर भी सोचे कि हमारे समाज में पत्नी को कहने के लिए ही दुःख-सुख में बराबर की अर्द्धांगिनी कहा जाता है, इस तरह तो पति के नाम की हर चल और अचल सम्पत्ति में भी उसकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो। मैं उम्मीद करूंगी कि यह सरकार इस बात पर भी विचार करेगी। यदि ऐसा होगा तो घर में उसका और अधिक सबलीकरण होगा, उसकी सामाजिक स्थिति मज़बूत बनेगी और साथ ही उसे और भी अधिक सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

बच्चों के सर्वांगीण विकास की संकल्पना भी इसमें साकार हुई है। मिड-डे मील, चिकित्सा, शिक्षा, आंगनवाड़ी विस्तार और बच्चों को कुपोषण से बचाने को प्राथमिकता दी गई है। माननीय सदस्या सुप्रिया जी की तो पूरी स्पीच ही बच्चों पर थी। एक बात को देख कर अवश्य हमें बड़ी पीड़ा होती है, कई जगह बच्चों से भीख मंगवाने का काम लिया जाता है। इसके लिए सरकार यह देखे कि किस प्रकार से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसे रोका जाए। यह बहुत आवश्यक कार्य है।

महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, जब यूपीए की माननीय अध्यक्षा, जो कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं और जिन पर हमें गर्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर हमारे विपक्षी नेता अनेक बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कमेंट करते हैं... । ऐसी बातें करते हैं जबकि यह पूरा देश जानता है कि कहीं पर भी चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे जम्मू कश्मीर में जहां भी कहीं हिंसा की, आतंकवाद की इस तरह की कोई त्रासदियां होती हैं, जहां पर कोई बाढ़ या इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें कि लोग प्रभावित होते हैं वहां और कोई नेता तो बाद में पहुंचते हैं लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी सबसे पहले वहां पर जाकर के उन लोगों के हालचाल जानती हैं, उनकी सुध लेती हैं। इसलिए इस बात की भी कभी-कभी विपक्ष के लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए इसमें उनको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में निठारी का जो दुर्दान्त, बर्बर हादसा हुआ, पूरे देश ने देखा कि कितने मासूम बच्चों की वहां जिस तरह से बलि हुई। महोदय, वहां सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी पहुंचीं, वहां के मुख्य मंत्री तक नहीं पहुंच पाए बच्चों की सुध लेने के लिए। महोदय, इससे अधिक भारतीयता और भारतीयों के प्रति प्रेम का और क्या प्रमाण चाहिए। महोदय, वैसे भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तो पूरे देश और दुनिया में अपने त्याग की, जिसमें प्रधान मंत्री जैसे सर्वोच्च पद को ठुकरा करके एक मिसाल कायम कर दी और उसके बाद तो कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचता। फिर भी जब इस तरह की टिप्पणियां आती हैं उधर से तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि वे जरा कभी यह भी देखा करें कि पानी का ग्लास पूरा भरा हुआ है, उसमें केवल कमियां ही ढूंढने के प्रयास रहते हैं सरकार के कामों में, यह एक छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति है। अगर विपक्ष का यही काम रह गया है कि हर बात में केवल नकारात्मक ही सोच हो, तो महोदय, कभी यह भी होना चाहिए कि अगर 50 बात अच्छी की हैं तो उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि विपक्ष का केवल यही दायित्व रह गया है कि केवल मात्र आलोचनाएं ही की जाएं या उसमें कमियां या आलोचनाएं या बुराई ही देखी जाएं।

यह जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण है जिसमें अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की भी एक बहुत ही सशक्त योजना है जो प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बनाई गई है वह केवल मात्र एक कागजी योजना नहीं है, वह एक प्रभावी योजना है और जल्दी ही लोग देखेंगे कि उस पर अमल होकर के वस्तुतः अल्पसंख्यकों के प्रति यह समाज के जो दलित हैं या जो आदिवासी वर्ग हैं उनके प्रति इस सरकार की केवल दिखावे की मगरमच्छ के आंसू बहाने की सहानुभूति नहीं है, बल्कि वाकई उनके लिए कुछ कर दिखाने की संकल्पशीलता है, वही इस अभिभाषण में प्रतिध्वनित होती है और वहीं दिनोंदिन सरकार के एक-एक कदम से यह जाहिर हो रहा है कि सरकार उस दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है, चाहे वस्त्र उद्योग का काम हो, टैक्सटाइल्स पार्क बनाने या विकसित करने का काम हो, चाहे जगह-जगह वायुपत्तनों के विकास का कार्य हो और जिस तरह से रेल मंत्रालय ने काम किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इन सभी क्षेत्रों में निरन्तर यह सरकार जो विकास की तरफ बढ़ रही है इसे पूरा देश देख रहा है।

महोदय, जहां तक चिकित्सा का सवाल है, एम्स पद्धति पर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता है और साथ ही सरकार को यह भी देखने की आवश्यकता है कि आज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बने हुए जो बड़े-बड़े पांच सितारा अस्पताल हैं, यानी पांच सितारा होटल इतने महंगे नहीं होंगे, महोदय, जितने ये अस्पताल हैं। महोदय, मैंने अभी देखा कि एक बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त होने पर लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। उसका नौ दिन का बिल ग्यारह लाख रुपए का था। इसके अलावा वहां पर एक पति-पत्नी दुर्घटनाग्रस्त पड़े हुए हैं उनको उठाने वाला नहीं है, क्योंकि अस्पताल में पहले उनको दो लाख रुपए जमा कराना है। तो फिर वे कैसे अपनी चिकित्सा वहां पर करा पाएंगे। जबकि उनको तत्काल चिकित्सा की जरूरत है। ऐसी स्थिति में अस्पताल के लोग कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। तो इस तरह से उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो महोदय, ये कैसे चेरिटेबल अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, वैसे ही इतने ज्यादा मरीज हैं, इतनी तादाद है, अस्पतालों की काफी कमी है, इस बात को भी यह सरकार सुनिश्चित करे कि चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जो अस्पताल चलाए जाते हैं, जो क्लीनिक चलाए जाते हैं वह चेरिटेबल कहीं दिखाई भी देना चाहिए। अचानक कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर पहुंच गया और फिर उसके ऊपर लाखों रुपए की डिमांड करना तथा फिर कहना कि हमारे यहां कोई जगह ही नहीं है, कोई बेड ही खाली नहीं है इसलिए हम भर्ती नहीं कर सकते, इस तरह की स्थितियां न आएं। तो इस पर सरकार को भी लगाम लगाने की जरूरत है। महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र का इतना व्यवसायीकरण होता जा रहा है कि लाखों रुपये दो, तब कहीं प्राईवेट शिक्षण संस्थानों में दाखिले हो पाते हैं। गरीब लोग कहां से लाखों रुपये लायें? इस पर कहीं न कहीं कोई रोक, कोई पाबंदी लगनी चाहिए, कहीं, कोई सीमा तो इसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... अभी जो आतंकवाद की और नक्सलवाद की

घटनाएं हुई हैं, उन पर पूरा देश चिंतित है, चाहे वह आसाम में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे झारखंड में हो या आतंकवाद चाहे सीमापार से आ रहा हो। एक जो बात पाकिस्तान ने कही है, मैं चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय उस पर गौर करे कि हमारे कितने युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं और उनकी सूची ली जाए तथा उनको रिहा कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी होंगे ही, लेकिन इसके लिएं और अधिक प्रयास किए जाएं। अगर वाकई पाकिस्तान सरकार इस मामले के प्रति गंभीर है, तो वह सूची देगी कि कितने युद्धबंदी हैं। उनको जल्दी से जल्दी रिहा कराया जाए और इससे भारतवासियों को बड़ा संतोष मिलेगा।

चूंकि यहां पर समय की सीमा है, अत: मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगी। मैं अंत में बस यही कह सकती हूं कि जिस तरह से किसानों के लिए यह सरकार काम कर रही है, इसके बारे में लोगों ने कहा भी है और मैं भी कहना चाहूंगी कि किसानों के लिए जो ऋण में बढ़ोत्तरी की गई है, उसकी मैं तारीफ करती हूं, लेकिन जो 4 राज्यों में 31 जिलों का चयन किया गया है किसानों को ऋण माफी देने के लिए, यह माना गया है कि वहां किसान पीड़ित हैं..।

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): ऋण माफ नहीं हुआ है।

डा॰ प्रभा ठाकुर: सरकार ने 4 राज्यों के 31 जिलों में जो मंशा दिखाई है। महोदय, मैं यहां सरकार से यह अपील करना चाहूंगी कि किसानों की आर्थिक बदहाली कई प्रदेशों में है, केवल मात्र 4 राज्यों में नहीं है और इसका मापदंड आत्महत्या नहीं होना चाहिए। कई स्थान ऐसे भी हैं, जहां किसानों ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन आर्थिक बदहाली और कर्जदारी से किसान परेशान हैं। कहां पर अकाल पड़ा है, कहां पर फसल की बर्बादी हुई है, कहां पर किसान को अकाल या बर्बादी के कारण रिलीफ नहीं मिल पाया है, ऐसी स्थिति में किसान ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं है, उस चीज़ को आधार माना जाना चाहिए न कि मात्र आत्महत्या को, क्योंकि यह कोई मापदंड मेरी समझ में नहीं आता है। इस देश में बहुत भूमि है, जो बंजर पड़ी हुई है। अगर सेज के लिए औद्योगिक घरानों को भूमि देना जरूरी है, तो उस बंजर भूमि को दिया जाए, खेती की कृषि लायक भूमि को उसके लिए न दिया जाए। किसानों को सरकार ने प्राथमिकता देते हुए अनेक उपाय किए हैं, नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं और ऋण में वृद्धि की है। किसानों को ब्याज में कई स्थानों पर निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए, जहां पर किसानों को फसल नहीं मिल पाती है, अकाल की वजह से फसल नष्ट हो जाती है, इस पर भी सरकार गौर करे। इस सरकार की मंशा को देखते हुए, मैं यह कह सकती हूं कि यह सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सब किसानों, गरीबों, मजदूरों और आम आदमी के लिए, हम यह उम्मीद करते हैं और देश का आम आदमी भी यह उम्मीद करता है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बातें उभरकर आई हैं, सरकार उन पर चलेगी। जैसा अभी तक सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा है, उसी प्रकार सरकार इस दिशा में अपने कदम बढ़ाती रहेगी। इसलिए मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।